हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

30 मार्च, 2016

खण्ड-1, अंक-11

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 30 मार्च, 2016

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(11) 1
विश्व हिन्दू परिषद के राष्ट्रीय पदाधिकारी तथा पाइनग्रोव स्कूल, कसौली, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) के विद्यार्थियों/अध्यापकगण का स्वागत	(11) 13
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(11) 13
भारत स्थित पेरु के राजदूत का स्वागत	(11) 20
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(11) 20
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(11) 21
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(11) 24
दलित कन्या के बलात्कार का मुद्दा उठाना	(11) 32
नियम 30 के अधीन प्रस्ताव	(11) 33
वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा पुनरारम्भ तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर	(11) 34
मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्टीकरण/सूचना	(11) 60

मूल्य :

वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा पुनरारम्भ तथा
वित्त मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भ) (11) 61

बैठक का समय बढ़ाना (11) 78

वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानों के लिए मांगों पर चर्चा तथा मतदान (11) 79

बैठक का समय बढ़ाना (11) 101

वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानों के लिए मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)(11)102

विधान सभा समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना

(i) पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की 62वीं रिपोर्ट (11) 118

(ii) कमेटी ऑफ लोकल बाडीज एंड पंचायती राज इंस्टीटयूशंज की 8वीं रिपोर्ट (11) 118

(iii) कमेटी ऑफ लोकल बाडीज एंड पंचायती राज इंस्टीटयूशंज की 9वीं रिपोर्ट (11) 119

(iv) एस्टीमेट्स कमेटी की 44वीं रिपोर्ट (11) 119

(v) गवर्नमैंट एश्योरेंसिज कमेटी की 45वीं रिपोर्ट (11) 119

(vi) कमेटी ऑन दि वैलफेयर ऑफ शिडयूल्ड कास्ट्स, शिडयूल्ड ट्राइब्ज एण्ड बैकवर्ड क्लासिज की 39वीं रिपोर्ट (11) 120

विधान कार्य—

1. दि हरियाणा म्युनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 2016 (11) 120
2. दि हरियाणा म्युनिसिपल कारपोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 2016 (11) 122
3. दि कंट्रैक्ट लेबर (रैगुलेशन एण्ड एबोलिशन) हरियाणा (अमैंडमैंट) बिल, 2016 (11) 123
4. दि इण्डस्ट्रिएल डिसप्यूट्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2016 (11) 125
5. दि फैक्ट्रीज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2016 (11) 127

बैठक का समय बढ़ाना (11) 128

विधान कार्य (पुनरारम्भ) (11) 128

6. दि पेमैंट ऑफ वेजिज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2016 (11) 128

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 30 मार्च, 2016

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात: 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल होगा।

Water Supply and Sewerage System

***1274. Shri Balkaur Singh :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to State—

(a) whether it is a fact that water supply is not being provided in the Chattargarh Pati colony of Sirsa City and sewerage system is also lying dysfunctional; and

(b) if so, the time by which the water supply in the above said area will be provided togetherwith the time by which the sewerage system is likely to be made functional ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (श्री घनश्याम सर्राफ) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी। सिरसा शहर की चत्तरगढ़ पट्टी कालोनी से नहर पर आधारित पानी की उचित आपूर्ति की जा रही है और मौजूदा सीवरेज सिस्टम भी काम कर रहा है।

(ख) चत्तरगढ़ पट्टी की वंचित गलियों में सीवरेज सिस्टम कि सुविधा प्रदान करने का चल रहा कार्य दिसम्बर 2016 तक समाप्त करने की संभावना है।

श्री बलकौर सिंह : अध्यक्ष महोदय, चतरगढ़ पट्टी बहुत ही गरीब बस्ती है तथा शहर के नजदीक लगती है। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि वहां पीने के पानी की व्यवस्था नहर से की जाती है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस नहर की बात है तो मैं बताना चाहूंगा कि पानी के लिए जो पाइप डाले गए थे वे अब बंद हो गए हैं जिस वजह से उस नहर का पानी इस कालोनी में नहीं आ पाता। कालोनी वासियों के कहने पर जिला परिषद द्वारा वहां टयूबवैल लगाकर पानी दिया जाता है। टयूबवैल का बिजली का बिल 4 लाख रुपये आया है जोकि बहुत ज्यादा है। गरीब बस्ती होने के कारण उनकी पंचायत के पास कोई साधन नहीं हैं कि वे यह टयूबवैल का बिजली का बिल अदा कर सकें इसलिए बिजली का कनैक्शन काट दिया गया है और टयूबवैल बंद हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि नहरी पानी के लिए जो पाइप लाइन डाली गई थी वह जगह जगह से टूटी पड़ी है जिसके कारण पीने के पानी की इस कालोनी में समस्या है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सीवेरज का काम नगर पालिका द्वारा

[श्री बलकौर सिंह]

शुरू किया गया था लेकिन थोड़ा सा काम करके उसके काम को बंद कर दिया गया है। कुछ गलियों को सीवरेज डालने के लिए उखाड़ा तो गया है लेकिन सीवरेज का काम बंद कर दिया गया है इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो सीवरेज का काम बंद पड़ा है उसको कब तक चालू किया जाएगा ? बिजली का बिल ज्यादा होने के कारण हमारे यहां की पंचायत बिल नहीं भर पाई। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि टयूबवैल का जो कनैक्शन काट दिया गया है उसको दोबारा लगाकर पीने का पानी कब तक मुहैया करवाया जाएगा ?

श्री घनश्याम सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, सिरसा विधान सभा क्षेत्र में 4 नहर आधारित बुस्टिंग स्टेशंज का निर्माण किया गया है और वहां 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी की सप्लाई दी जा रही है।

श्री बलकौर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि हमारी यह चतरगढ़ पट्टी कालोनी सिरसा शहर में न पड़कर कालांवाली क्षेत्र में पड़ती है लेकिन सिरसा के साथ जरूर लगती है।

श्री घनश्याम सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि चतरगढ़ पट्टी कालोनी सिरसा के नजदीक पड़ती है और वहां शहर से ही पानी दिया जा रहा है। शहर में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से पानी दिया जा रहा है। तृतीय जलघर का कार्य भी 206.15 लाख रुपये के अनुमान के अंतर्गत पूरा किया गया है जिसकी क्षमता 135 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन है। जिस पर 316 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। चत्तरगढ़ पट्टी में ट्यूबवैल द्वारा पानी नहीं दिया जा रहा। जहां कहीं ट्यूबवैल द्वारा पीने के पानी की सप्लाई दी जाती है, उन ट्यूबवैल्ज का बिजली का बिल विभाग द्वारा समय-समय पर भरा जाता है। दूसरा सवाल माननीय साथी ने जो मल निकासी के बारे में पूछा है उस बारे में बताना चाहूंगा कि शहर में मल निकासी हेतू 200 मि.मी. से 1800 मि.मी. तक विभिन्न आकार का लगभग 214 कि.मी. भूमिगत सीवर बिछाया गया है। दो मुख्य मल उत्थान केन्द्रों एक कैलनियां रोड पर एवं दूसरा नटार रोड पर के अतिरिक्त 6 मध्यवर्ती उत्थान केन्द्र खैरपुर, बालभवन, कीर्तिनगर, कंगनपुर रोड, बाल्मिकी एवं मेला ग्राउंड द्वारा मल निकासी की जाती है। कैलनियां रोड और नटार रोड़ पर 2 मल संसोधन सयंत्र क्रमश:15 एम.एल.डी. और 5 एम.एल.डी. क्षमता के स्थापित हैं।

श्री बलकौर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो जानकारी दे रहे हैं वह मेरे सवाल से संबंधित नहीं है। मैंने चत्तरगढ़ पट्टी के बारे में पूछा है। वहां पर थोड़े दिन पहले काम शुरू हुआ था जो अब बंद पड़ा है। वहां पर यह कार्य कब तक पूरा किया जायेगा। दूसरा मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि चत्तरगढ़ पट्टी में ट्यूबवैल द्वारा पानी नहीं दिया जा रहा इस बारे में बताना चाहूंगा कि वहां पर तीन साल तक ट्यूबवैल चला है लेकिन उसका बिजली का बिल न अदा करने के कारण वह ट्यूबवैल बंद पड़ा है। क्या सरकार उस ट्यूबवैल का बिल अदा करने बारे कोई विचार कर रही है या नहीं। मैंने यह जानकारी मंत्री जी से मांगी है। कृपा इस बारे में मंत्री जी बतायें।

श्री धनश्याम सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को चत्तरगढ़ पट्टी के बारे में ही जानकारी दे रहा हूं। चत्तरगढ़ पट्टी वार्ड नं. 31 से होता हुआ प्रेम नगर तक 300 मि.मी. से 600 मि.मी. आकार का 4.6 कि. मी. लम्बा मुख्य ट्रंक सीवर बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। 56.59 करोड़ रुपये के अनुमान के अर्न्तगत नटार रोड़ सिरसा पर 5 एम.एल.डी. का तीसरे मल संशोधन संयंत्र का कार्य प्रगति पर है और यह कार्य मार्च, 2016 में पूर्ण हो जाने की संभावना है। इस कार्य पर अब तक 58.45 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। इसी तरह से एक 15 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता का चौथा मल संशोधन संयंत्र फरवरी, 2015 में स्वीकृत हुआ था जिस पर 33.91 करोड़ रुपये के प्राक्कलन के अंतर्गत बनना प्रस्तावित है। जिसे मार्च, 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। जहां तक माननीय साथी ने चत्तरगढ़ में ट्यूबवैल के बिजली के बिल के बारे में पूछा है इस बारे में मैं इनको फिर से जानकारी देना चाहूंगा कि वहां पर कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई से पानी दिया जाता है, ट्यूबवैल से वहां पानी नहीं दिया जाता।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, माननीय सदस्य ने सवाल यह किया है कि क्या यह तथ्य है कि सिरसा शहर की चत्तरगढ़ पट्टी कालोनी में जलापूर्ति उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। आप यह बतायें कि वहां पर जलापूर्ति उपलब्ध करवाई जा रही है या नहीं।

श्री घनश्याम सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी मुझे विभाग की टीम ने बनाकर दी है उसके मुताबिक वहां पर 135 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम से उपलब्ध करवाया जा रहा है।

श्री बलकौर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह पानी शहर में दिया जा रहा है, चत्तरगढ़ पट्टी में नहीं दिया जा रहा। स्पीकर सर, जो मैंने सवाल पूछा था मुझे उसका सही जवाब नहीं मिला है। मैंने यह पूछा था कि चत्तरगढ़ पट्टी का ट्यूबवैल बिजली का बिल न भरने के कारण बंद पड़ा है तो क्या माननीय मंत्री जी उसका बिल भरेंगे ताकि वह ट्यूबवैल चल सके।

श्री घनश्याम सर्राफ : स्पीकर सर, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है हम वहां पर इसकी इंक्वायरी करवा लेंगे और अगर ऐसा पाया जाता है तो तुरंत ही बिजली का बिल भरके उस ट्यूबवैल को चलाया जायेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या 1048

(यह प्रश्न पूछा नहीं जा सका क्योंकि इस समय माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी सदन में उपस्थित नहीं थी।)

तारांकित प्रश्न संख्या 1327

(यह प्रश्न पूछा नहीं जा सका क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री उदय भान सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Installation of Transformers

***1323. Shri Sukhwinder :** Will the Chief Minister be pleased to state the number of PET transformers installed for supplying the electricity to the Dhanies in District Bhiwani togetherwith the number of those Dhanies in which these transformers have not been installed so for alongwith the time by which the work of installation of these transformers is likely to be completed ?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : श्रीमान जी, जिला भिवानी में 216 पी.ए.टी. ट्रांसफार्मर स्थापित किए जा चुके है, जिनमें से 176 को चालू कर दिया गया है! 7433 ढाणियों को पहले ही शामिल किया जा चुका है। शेष 1153 ढाणियों को 31-07-2016 तक शामिल कर लिया जाएगा।

श्री सुखविन्द्र : स्पीकर सर, 06 अप्रैल, 2015 को माननीय मुख्यमंत्री जी बाढ़ड़ा की जनसभा में यह घोषणा करके आये थे कि 6 महीने के अंदर-अंदर जिले की सभी ढ़ाणियों में पी.ए.टी. ट्रांसफार्मर लगाकर उनको जगमग कर दिया जायेगा। आज लगभग एक साल पूरा हो चुका है लेकिन अभी तक इस बारे में कोई काम नहीं हो पाया है। सबसे पहले बाढ़ड़ा और झोंझू कलां के सर्कल को कम्पलीट कर दिया जाये उसके बाद डिगावा, जूई, अटेला, दादरी, सबरबन और लौहारू इत्यादि ऐसे सर्कल हैं जिनके अंदर अभी भी ढ़ाणियां पी.ए.टी. ट्रांसफार्मर की सुविधा से वंचित हैं। मंत्री जी ने इस काम के लिए 31.07.2016 तक का समय मुकर्रर किया है जिसमें 3-4 महीने और शेष बचे हैं। मेरा निवेदन यह है कि हमारा यह काम एक साल पहले ही लेट हो चुका है इसलिए इस समय को ही ऐसे न निकाला जाये और इसी समय के अंदर-अंदर इन सभी ढ़ाणियों को पी.ए.टी. ट्रांसफार्मर के माध्यम से बिजली की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाये।

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश में कुल 43900 ढ़ाणियां हैं। हमने प्रदेश की 35649 ढ़ाणियों को इस स्कीम के तहत शामिल कर लिया है। जो 8251 ढाणियाँ बाकी बची हैं उनको भी जल्दी से जल्दी इस स्कीम में शामिल कर लिया जायेगा। स्पीकर सर, यह ढ़ाणियों को बिजली देने वाली स्कीम कई बार आ चुकी है। सबसे पहले दिनांक 03.08.2010 को एक स्कीम आई थी जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि जहां पर 11 व्यक्तियों की बस्ती होगी उसको ढ़ाणी मान लिया जायेगा। यदि 50-50 प्रतिशत पैसा कंज्युमर और निगम जमा करवाये तो वहां पर कनैक्शंज़ दे दिये जायेंगे। यह स्कीम कुछ ही समय चली लेकिन अधिकतर लोग इसका लाभ नहीं उठा पाये। इसके बाद दूसरी स्कीम 14.11.2013 को आई जिसमें यह तय किया गया था कि 50 प्रतिशत पैसा निगम दे, 22.5 प्रतिशत पैसा एम.पी. लैड से आये, 22.5 प्रतिशत पैसा एच.आर.डी.एफ. से आये और बाकी का 5 प्रतिशत पैसा कंज्युमर दे तो वहां पर कनैक्शंज़ दे दिये जायें लेकिन यह स्कीम भी कामयाब नहीं हो सकी। इसके बाद अब हमारी सरकार ने पी.ए.टी. ट्रांसफार्मर का फैसला लिया है। इसमें जैसा कि मैंने माननीय सदस्य को जानकारी दी है कि हमने अभी तक 216 पी.ए.टी. ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिये हैं जिनमें से 176 पी.ए.टी. ट्रांसफार्मर को चालू कर दिया गया है। जिन ढ़ाणियों को अभी तक इस स्कीम में शामिल नहीं किया गया है उनको भी जल्दी ही इस स्कीम में शामिल कर लिया जायेगा।

———————

Up gradation of School in Hathin Constituency

***1009. Sh. Kehar Singh :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Girl Schools of village Mandkola, Manpur, Fulwari, Nangal Jat Dharot, Madnaka, Taharki up to Government Senior Secondary Schools in Hathin constituency; if so, the time by which the abovesaid schools are likely to be upgraded together with details thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) :

(ए) नहीं, श्रीमान् जी।

(बी) अत: यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, अपने इस प्रश्न के माध्यम से माननीय सदस्य श्री केहर सिंह रावत ने उनके विधान सभा क्षेत्र के गवर्नमैंट गर्ल्स स्कूल, मण्डकोला और उच्च विद्यालय, मानपुर, फुलवारी, नांगल जाट धरौट, मडनाका और टाहरकी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के स्तर तक अपग्रेड करने के बारे में पूछा है। स्पीकर सर, वर्ष 2010 में इस प्रकार के स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए तत्कालीन सरकार द्वारा कुछ मानक तय किये गये थे जिनके तहत दसवीं से 12वीं में अपग्रेड करने के लिए विद्यार्थियों की संख्या 210 होनी चाहिए तथा कम से कम 14 कमरे उपलब्ध होने चाहिएं। इसके साथ-साथ 5 किलोमीटर के आसपास कोई दूसरा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नहीं होना चाहिए। माननीय साथी श्री केहर सिंह जी को हम पिछले सवाल पर मडनाका और मंडकोला के बारे में विचार करने के लिए कह चुके हैं। ये हमारे साथी हैं और हनुमान भक्त हैं। जहाँ तक उपलब्ध जानकारी की बात है तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि मंडकोला में इस समय 150 बच्चे उपलब्ध हैं जबकि वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड करने के लिए कम से कम 210 बच्चे उपलब्ध होने जरूरी हैं। इसके साथ ही साथ 1.2 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भी मौजूद है। वहाँ पर जमीन 4 एकड़ अवश्य उपलब्ध है लेकिन वहाँ पर कमरे 14 की बजाय 11 हैं। इसी प्रकार से मानपुर में 210 की बजाय 101 बच्चे हैं हालाँकि वहाँ पर जमीन 6 एकड़ उपलब्ध है तथा कमरे भी 14 की बजाय 17 हैं लेकिन बच्चों की संख्या नॉर्म्स से कम 101 है। इसी तरह से फुलवाड़ी में only 79 students are available in the school तथा जमीन 2 एकड़ है। अगर नांगल जाट की बात की जाये तो इसमें बच्चों की संख्या 92 है और कमरे 14 की बजाय 7 उपलब्ध हैं। इसी प्रकार से मडनाका में 67 बच्चे उपलब्ध हैं और 10 कमरे हैं। टहरकी में इस समय 104 बच्चे उपलब्ध हैं। माननीय विधायक ने जो पूछा था उसकी स्थिति इस प्रकार थी।

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वर्ष 2003 में चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी ने शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए पहली कक्षा से इंगलिश क्लासिज शुरू की थी लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसने उस पैटर्न को बदल दिया और एक ऐसी शिक्षा नीति हरियाणा प्रदेश में लागू कर दी जिसके तहत पहली से सातवीं कक्षा तक तो स्कूल में जाने की ही जरूरत नहीं थी बच्चे वैसे ही पास कर दिये जाते थे।

श्री अध्यक्ष : केहर सिंह जी, आप अपने प्रश्न से संबंधित ही अनुपूरक प्रश्न पूछिये, यह आपके प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के जवाब में बताया है कि वहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या कम है। हरियाणा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होने का मुख्य कारण यह है कि लोगों का ध्यान सी.बी.एस.ई. पैटर्न की तरफ ज्यादा है। हर मां-बाप अपने बच्चों को इंगलिश मीडियम से पढ़ाना चाहता है। मेरा माननीय मंत्री जी के लिए एक सुझाव है कि पहली क्लास से जिस प्रकार सी.बी.एस.ई. की क्लासिज चलाई जाती हैं उसी प्रकार क्लासिज चलाई जायें ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। मेरा तो विचार यह भी है कि पहली क्लास की बजाय एल.के.जी. और यू.के.जी. की क्लासिज भी शुरू की जानी चाहिएं। हमारे पास अच्छे टीचर हैं तथा हम उनको अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं इसलिए हमें उनका पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि हरियाणा प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी स्थिति में लाया जा सके। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सी.बी.एस.ई. पैटर्न को कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री केहर सिंह जी की चिन्ता और इनका सुझाव बहुत उपयुक्त हैं और हरियाणा सरकार इस पर विचार करेगी।

Gender Ratio

***1342. Shri Umesh Aggarwal :** Will the Health Minister be pleased to state—

(a) the District-wise figures of gender ratio as on 30-9-2014 and 31-1-2016; and

(b) the District-wise and year-wise number of raids conducted in the Hospitals on the doctors who were found indulging in the prenatal tests from the year 2009 to 2014 and from 2014 to till date togetherwith the number of Hospitals and the doctors held guilty and convicted by the courts;

Health Minister (Shri Anil Vij) : Speaker Sir, the Hon'ble Member has wanted to know the gender ratio as on 30-09-2014 to 31-01-2016. Speaker Sir, we do not maintain the record of gender ratio. Gender ratio is maintained by the Census Department of Government of India. Therefore, the data from 30-09-2014 to 31-01-2016 cannot be provided. However, if the Member has wanted to know the gender ratio at birth, that record is maintained and a statement in this regard has been laid on the Table of the House.

Statement

(a) The District-wise figures of gender ratio as on 30-9-2014 and 30-1-2016 is not available since the census of india conducted once in 10 years.

The District-wise figures of gender ratio in Haryana as per 2011 census are as under :—

District-wise figures of gender ratio in Haryana as per Census 2011

Sr. No.	Name of District	Gender Ratio
1	2	3
1	Ambala	882
2	Bhiwani	884
3	Faridabad	871
4	Fatehabad	903
5	Gurgaon	853
6	Hissar	871
7	Jhajjar	870
8	Jind	861
9	Kaithal	886
10	Karnal	880
11	Kurukshetra	889
12	Mewat	906
13	Mahendergarh	894
14	Pawal	870
15	Panchkula	861
16	Panipat	879
17	Rewari	868
18	Rohtak	898
19	Sirsa	896
20	Sonepat	853
21	Yamunangar	877
	Haryana	877

[Source:- Census of India]

However, data relating to District-wise figures of **gender ratio at birth** in Haryana as per Civil Registration System as on 30-9-2014 and 31-1-2016 is as under :—

Sex/Gender Ratio at Birth in Haryana

Sr. No.	Name of District	For the month of September, 2014	Average/Cummulative 1-1-2014 to 30-9-2014	For the month of January, 2016 (upto 31-1-2016)
1	Ambala	856	888	872
2	Bhiwani	828	836	848
3	Faridabad	885	884	947
4	Fatehabad	931	888	942
5	Gurgaon	901	842	854
6	Hisar	890	876	926
7	Jhajjar	807	812	912
8	Jind	785	882	895
9	Kaithal	844	898	908
10	Karnal	844	886	912
11	Kurukshetra	840	874	896
12	Mewat	926	920	935
13	Mahendergarh	792	786	851
14	Palwal	882	881	891
15	Panchkula	900	915	892
16	Panipat	901	893	893
17	Rewari	797	797	889
18	Rohtak	885	887	872
19	Sirsa	980	900	965
20	Sonipat	856	846	921
21	Yamunanagar	828	858	881
	Haryana State	870	872	902

(b) The District-wise and year -wise number of raids conducted in the Hospitals on the doctors who were indulging in the prenatal tests from the year 2009 to 2014 till to date togetherwith the number of Hospitals and the doctors held guilty and convicted by the courts;

Sr. No.	Name of District	Raids		Number of Hospitals & doctors held guilty and convicted by the courts			
				Hospitals		Doctors	
		1-1-2009 to 31-3-2014	1-4-2014 to 9-3-2016	1-1-2009 to 31-3-2014	1-4-2014 to 9-3-2016	1-1-2009 to 31-3-2014	1-4-2014 to 9-3-2016
1	Ambala	12	10	2	0	2	0
2	Bhiwani	1	6	0	0	0	0
3	Faridabad	1	5	2	1	3	1
4	Fatehabad	4	1	0	0	0	0
5	Gurgaon	2	7	2	0	7	0
6	Hisar	2	11	0	0	0	0
7	Jhajjar	5	2	0	0	0	0
8	Jind	0	8	0	0	0	0
9	Kaithal	2	15	0	0	0	0
10	Karnal	31	26	4	0	4	4
11	Kurukshetra	6	8	0	0	0	0
12	Mewat	0	1	0	0	0	0
13	Mahendergarh	5	14	0	0	0	
14	Palwal	2	4	2	1	3	1
15	Panchkula	3	0	1	0	1	0
16	Panipat	0	7	0	0	0	0
17	Rewari	0	6	0	1	0	2
18	Rohtak	1	5	0	0	0	0
19	Sirsa	6	9	0	1	0	2
20	Sonepat	5	4	1	0	1	0
21	Yamunanagar	8	11	0	0	0	0
	Haryana State	**96**	**160**	**14**	**4**	**21**	**6**

श्री उमेश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने हाउस में जो डाटा रखा है उसके अनुसार वर्ष 2009 से 2014 में जो पी.एन.डी. टी. एक्ट के तहत डॉक्टरों पर छापे मारने की जो कार्रवाही की गई है उसके अन्दर उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जहां वर्ष 2009 से 2014 तक 296 डॉक्टरों के खिलाफ छापे मारे गये वहीं वर्ष 2014 से 2016 में दो वर्ष से भी कम अवधि में 160 डॉक्टरों के ऊपर छापे मारे गये जिसका उल्लेख मंत्री जी ने अपने जवाब में किया है। इस छापे की कार्रवाई से यह प्रतीत हो रहा है कि निश्चित रूप से जैंडर रेशो में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और जो भारत सरकार का और हरियाणा सरकार का कार्यक्रम था बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ उसमें सफलता मिली है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह कृपा यह बताएं कि यह पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत जो कार्रवाई की जाती है उसके अन्दर जो इन्फॉर्मर होता है

[श्री उमेश अग्रवाल]
अर्थात जो सूचना देता है कि वह डॉक्टर इस तरह के जैंडर रेशो की सक्रुटनी कर रहा है तो उस इन्फॉर्मर को उस शिकायत कर्ता को क्या ईनाम दिया जाता है और इसका क्या प्रोविजन है कृपा मंत्री जी इसके बारे में बताने का कष्ट करेंगे।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, इस सैक्स रेशो को ठीक करने के लिए हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं लेकिन हमने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि जो भी आदमी हमारे विभाग को इसकी पुख्ता सूचना देगा और ऐसे मामले पकड़वाएगा उसको हम एक लाख रूपया ईनाम देते हैं।

श्री उमेश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जैसा हमें बताया कि किसी भी सूचना देने वाले को हम एक लाख रूपया ईनाम देते हैं। मैं आपके माध्यम से सदन की व माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि इस सूचना पर जो एक लाख रुपये का ईनाम है उसके लालच में कई निर्दोष डॉक्टरों के खिलाफ और अस्पतालों के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। कोई भी आदमी 5-10 हजार रुपये देकर नकली ग्राहक बनाकर अस्पताल में भेज देते हैं। इसके अलावा कई ऐसे भी केस सामने आए है कि वहां डॉक्टर ने न कोई अल्ट्रासाउंड किया, न ही कोई जानकारी मिली और न ही कहीं रजिस्टर में एन्ट्री की हुई उसके बावजूद भी आपके विभाग की टीम उस डॉक्टर पर छापेमारी करके उसके खिलाफ कार्रवाई कर देती है और उस निर्दोष डॉक्टर का जीवन नरक बन जाता है। क्या सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर रही है जो इस तरह से दोषपूर्ण कार्रवाई करके और झूठी शिकायत करके दूसरे लोगों को फंसाने का कार्य कर रहे हैं क्योंकि इस एक्ट के कारण कहीं ऐसा न हो कि यह अमरजैंसी की हालात की तरह एक गलत तरह का सिस्टम न बन जाए कि लोग एक दूसरे को फंसाने के लिए गलत कार्रवाई न करने लगें।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, वैसे तो अभी तक इस प्रकार की कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है और बाकायदा इस तरह की अपील के लिए सिस्टम मकैनिजम बना हुआ है कि अगर किसी के साथ गलत होता है तो वह अपील कर सकता है। तीसरी बात जो मेरे साथी ने कही है कि गलत जगहों पर रेड मारी जाती है। दरअसल यह जो सारा रेड मारने का काम है वह मुख्यमंत्री जी ने अपने विभाग में एक सैल बना रखा है और उस सैल के हैड श्री राकेश गुप्ता हैं सारा काम वह करते हैं अब वह कहां छापा मारते हैं और कैसे मारते हैं उसका हमें पता नहीं है तो उसके बारे में मैं नहीं बता सकता।

तारांकित प्रश्न संख्या 1381

(यह प्रश्न पूछा नहीं जा सका क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री रहीस खान सदन में उपस्थित नहीं थे।)

To Abolish the Condition of Post-Mortem

***1077. Shri Om Parkash Barwa :** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether it is a fact that the Haryana Agricultural Marketing Board provides

financial aid to those farmers who die or become amputated while working in the field but the condition of post-mortem has been imposed in case of death; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to abolish the mandatory condition of post-mortern as referred to above ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : हां, श्रीमान् जी। शवपरीक्षा की अनिवार्यता शर्त को समाप्त करने की कोई योजना नहीं है। शवपरीक्षा से अप्राकृतिक मृत्यु के कारण का स्पष्ट पता चल जाता है।

श्री ओमप्रकाश बरवा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि किसान को कोई यह जानकारी नहीं होती कि किसान की मृत्यु पर सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता मिलती है। इसलिए अज्ञानता की वजह से, रूढ़िवादिता की वजह से भी किसान कई बार पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहता लेकिन जो वास्तव में सच्चे केस होते हैं उन केसों के बारे में क्या पंचायत स्तर पर नम्बरदार या सरपंच के माध्यम से या तहसील स्तर पर तहसीलदार या एस.डी.एम के माध्यम से जांच करवाकर क्या किसान को आर्थिक सहायता दी जा सकती है ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि सारा हाउस इस बात पर सहमत होगा कि यह जानना बहुत जरूरी होता है कि जो मृत्यु हुई है वह किसी दुर्घटना की वजह से हुई है या नहीं। इस बात की जांच करने का सही स्टीक माध्यम शवपरीक्षा ही होता है। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा कृषि कार्य करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हुए किसानों के हित के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं जिनका लाभ लेने के लिए पुलिस थाने में मृत्यु से संबंधित रिपोर्ट का दर्ज होना तथा शव परीक्षा को अनिवार्य बनाया गया है। यदि शवपरीक्षा की छूट दे दी जाती है तो समझ लीजिए यह ऐसा रास्ता बन जायेगा की कल इसका गलत प्रयोग किया जा सकता है और मुझे नहीं लगता कि शवपरीक्षा की छूट इस तरह के मामलों में दी जानी चाहिए। किसान भाइयों को इस तरह की अनिवार्य कंडीशनंज की भलीभांति जानकारी उपलब्ध है। काफी बड़ी राशि एक्सीडेंट्स तथा अंग-भंग के केसिज में किसानों को हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दी जाती रही है। वर्ष 1991 से लेकर 2015 तक लगभग 67 करोड़ रुपये की राशि इस तरह के केसिज में वितरित की जा चुकी है। इसके अलावा वर्ष 2014-2015 के बीच 19 करोड़ 89 लाख रुपये की एक बड़ी राशि कृषि कार्य करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हुए किसानों को वितरित की गई है। अगर माननीय सदस्य इस संबंध में यह चाहते हैं कि किसानों को और ज्यादा जागरूक किया जाये तो मंडियों में बोर्ड लगवाये जा सकते हैं अखबारों में विज्ञापन दिये जा सकते हैं। जहां तक शवपरीक्षा से छूट की बात है तो मुझे नहीं लगता है और सारा सदन भी मेरी इस बात से सहमत होगा कि शवपरीक्षा की छूट दे दी जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अभी पंजाब प्रदेश में इस संबंध में थोड़ी सी पहले करते हुए किसान की बीमारी अर्थात किसान हैल्थ बीमा को भी कृषि कार्य करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हुए किसानों को क्षतिपूर्ति वाली स्कीम्ज के साथ जोड़कर किसानों को लाभ देने का कार्य किया गया है। मैंने हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों से कहा है कि पंजाब की इस स्कीम की स्ट्डी करें और अगर इसको वॉयबल पाया जाता है तो इसको हरियाणा में भी इम्पलीमैंट किया जाना चाहिए। हम इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : गंगवा जी, आप भी माननीय धनखड़ साहब से कुछ पूछना चाह रहे थे। आप अब मंत्री जी से अपनी बात पूछ सकते हैं।

श्री रणबीर गंगवा : अध्यक्ष महोदय, हिसार से सांसद श्री दुष्यंत चौटाला जी हैं। उनसे हमने पातन गांव में ड्रेन बनाने के लिए ग्रांट ली थी। इस ग्रांट को दिए हुए आठ-दस महीने हो चुके है लेकिन इसकी अभी तक क्लियरेंस नहीं हो पाई है। जब इस बारे में पता किया गया तो हमें बताया गया कि ग्रांट की क्लियरेंस को चीफ इंजीनियर के पास एप्रूवल के लिए भेजा गया है। जब ग्रांट दे दी गई है तो एप्रूवल का क्या औचित्य रह जाता है। अब तक आपके महकमें के किसी भी अधिकारी द्वारा इस दिशा में कोई भी पहल नहीं की गई है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने महकमे के अधिकारियों को इस तरह की ग्रांट्स समय पर रीलीज करने के निर्देश दें। आज मेरे क्षेत्र के किसान बहुत दुखी हैं। उनके लिए अपने खेतों में जाना भी दूभर हो चुका है। हमने स्पेशल ग्रांट ली थी लेकिन अब तक भी इस दिशा में कोई कार्य संभव नहीं हो सका है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यदि इस तरह की कोई समस्या थी तो इस बारे में आप मुझे टेलीफोन पर या स्वयं मिलकर इस तरह की जानकारी दे सकते थे। अब यह मामला मेरे संज्ञान में आ चुका है। इस संबंध में आज ही आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देश देकर ग्रांट को क्लियर करवाने का काम किया जायेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या 1041

(यह प्रश्न पूछा नहीं जा सका क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल सदन में उपस्थित नहीं थे।)

To Construct the Four Lane Road

***1032. Shri Mool Chand Sharma :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the four lane road from Ballabhgarh to Sohna; if so, the details thereof togetherwith the time by which the four lane bridge on the said road is likely to be constructed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान जी। इसलिए, समय सीमा का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मूल चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो हमारा सोहना का फलाईओवर है यह औद्योगिक नगरी फरीदाबाद व गुड़गांव को जोड़ने के साथ-साथ अलवर, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी तथा मंझावली से धनकौर तक को भी जोड़ता है। सिंगल फलाईओवर होने के कारण इस पर एक-एक घंटे जाम लगा रहता है। सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात कही जाती है। आई.एम.टी. ग्रेटर फरीदाबाद में बसाई गई है लेकिन इसको जोड़ने के लिए कोई लिंक रोड़ तक नहीं है। एक-एक घंटा ट्रकों व गाड़ियों का जाम लगा रहता है। मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि यदि औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना है तो जहां पर रेलवे क्रांसिग है या जहां पर सिंगल फलाईओवर है वहां पर डबल रोड़ या डबल फलाईओवर बनाया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो यहां के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा नहीं मिल सकेगा। यह रास्ता मेन शहर के अन्दर

एन्ट्री करता है। जहां जी.टी. रोड़ भी 300 मीटर के दायरे में है, मैट्रो स्टेशन भी 300 मीटर के दायरे में है और रेलवे स्टेशन भी 300 मीटर के दायरे में है। जी.टी. रोड़ पर तो फ्लाई ओवर नहीं बन सकता है। जब तक रेलवे का फ्लाई ओवर चार लेन का नहीं होगा तब तक समस्या हल नहीं होगी। पूरा शहर ट्रैफिक में फंसा रहता है और यह दो प्रदेशों की औद्योगिक नगरी को भी जोड़ता है। अत : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से नम्र निवेदन है कि इस फ्लाई ओवर को चार लेन का बनाया जाये।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह प्रश्न मूल चन्द शर्मा जी ने किया है लेकिन पीछे से बहन सीमा त्रिखा, श्री टेक चंद शर्मा और श्री विपुल गोयल सभी कह रहे हैं कि इस फ्लाई ओवर को चार लेन का बनाओ। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह रोड़ रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के पास है, जो तकरीबन वर्ष 2026 तक बी.ओ.टी. के आधार पर दिया गया है लेकिन मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि यदि सर्वे में यह जायज पाया गया और वास्तव में भीड़ पाई गई तो हम इस पुल को जरूर बनवा देंगे।

विश्व हिन्दू परिषद् के राष्ट्रीय पदाधिकारियों तथा पाइनग्रोव स्कूल, कसौली जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) के विद्यार्थियों/अध्यापकगण का स्वागत

श्री रामविलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि विश्व हिन्दू परिषद् के राष्ट्रीय पदाधिकारी श्री महावीर प्रसाद जी व श्री शिव नारायण जी आज इस सदन की कार्यवाही देखने के लिए वी.आई.पी. दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं पूरे सदन की ओर से उनका स्वागत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि पाइनग्रोव स्कूल, कसौली, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) के विद्यार्थी तथा अध्यापकगण आज इस सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं पूरे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Construction of CHC Building

***1170. Shri Ram Chand Kamboj :** Will the Health Minister be pleased to state the time by which the construction work of CHC building of Rania in Rania Assembly constituency is likely to be started togetherwith the details thereof ?

Health Minister (Shri Anil Vij) : Sir, presently there is no proposal to construct a new building for the Community Health Centre, Rania.

श्री राम चंद कम्बोज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को रानियां क्षेत्र के सरकारी अस्पताल के बारे में बताना चाहता हूँ। रानियां क्षेत्र के सरकारी अस्पताल में जब मरीज उपचार करवाने के लिए जाता है तो मन में सोचता है कि कहीं अस्पताल की बिल्डिंग मेरे ऊपर गिर न जाए और मैं मर न जाऊँ। पिछले दो वर्षों से अस्पताल में ना तो फार्मासिस्ट है और ना ही एक्सरे मशीन को चलाने वाला अटैंडेंट है। यह 30 बैडों का अस्पताल है, जिसमें छोटे-

[श्री राम चंद कम्बोज]

छोटे कमरे हैं। इस अस्पताल की व्यवस्था देखकर ऐसा लगता है कि यह अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग है। जिसमें यह अस्पताल चल रहा है। जमीन का स्तर नीचे होने के कारण बरसात के दिनों में अस्पताल में 5-6 फीट पानी जमा हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि अस्पताल में बैडों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ नवर्निमाण के बारे में सरकार का क्या रूख है ? इसके बारे में बताया जाये।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, डिपार्टमैंट की रिपोर्ट के मुताबिक जो बिल्डिंग की कंडीशन है that is satisfactory. इसके ऊपर 25.80 लाख रुपये खर्च करके मदर एण्ड चाइल्ड हैल्थ विंग ने इसे कंसट्रेक्ट किया है। वर्ष 2013-14 में 7,24,536/- रुपये खर्च करके इसकी रिपेयर की गई थी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जहां इसकी बैड संख्या या दूसरी बात कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा है कि हमारी सरकार जितने भी पी.एच.सीज., सी.एच.सीज. व जिला अस्पताल हैं उनको अपग्रेड करने का विचार कर रही है और उसके लिए बकायदा जो प्रपोजल है वह काफी एडवांस स्टेज पर है। यह सुविधा हम सभी अस्पतालों में करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी बताया था कि 84 अस्पतालों को एन.ए.बी.एच. के तहत अक्रेडिटैशन कराने जा रहे हैं और उसके लिए बड़ी जल्दी ही अक्रेडिटैशन बोर्ड के साथ एम.ओ.यू. साईन होने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी अचीवमैंट है। इससे हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग का नक्शा ही बदल जायेगा। ऐसा हिन्दुस्तान के किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रोसैस में समय लग सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि हैल्थ डिपार्टमैंट का स्टॉफ अस्पताल के नजदीक या उसके दायरे में ही रहे। क्योंकि रात को एमरजेंसी के दौरान यदि स्टॉफ की जरूरत पड़े तो वह 10 किलोमीटर की दूरी से नहीं आ सकते हैं और जो स्पेशलिस्ट्स डॉक्टर होते हैं उनकी ऑन कॉल तुरंत रात को जरूरत पड़ती है। मैंने विभाग को क्वार्टर्स के एस्टीमेट्स बनाने के आदेश दिए हैं और एस्टीमेट्स बन जाने के बाद सारे मेडिकल स्टाफ के लिए क्वाटर्स बनवाएंगे a huge budget is needed for that लेकिन इससे पहले हमें अपनी सारी कार्यवाही पूर्ण करनी होगी और बजट के लिए भी We have some planning. Speaker Sir, for NABH also a huge budget is needed. Approximately, may be one thousand crore rupees is needed to upgrade all the Hospitals for NABH accreditation. Speaker Sir, we have started work in this regard but it will take time. हम हर हॉस्पिटल में बेड स्ट्रैंग्थ बढ़ाना चाहते हैं। मैंने अपने विभाग से अस्पतालों में मरीजों के लिए बैड्स की संख्या की स्टडी करवाई है। इसमें हमें पता चला है कि जिस अस्पताल में 100 बैड्स की जगह है हम वहां पर 217 पेशेंट्स को इन्डोर एडमिट कर रहे हैं। लोग डॉक्टरों को बैड न होने पर भी दाखिल करके ईलाज के लिए शुक्रिया अदा करने की अपेक्षा गाली देते हैं और मीडिया भी विभाग के अच्छे कार्य की सराहना करने की अपेक्षा आलोचना करता है कि एक बेड पर तीन-तीन मरीजों को लिटाकर ईलाज किया जा रहा है। लोगों को हमारा धन्यवाद करना चाहिए चूंकि अस्पताल में जगह उपलब्ध न होने पर भी हम मरीज को मना नहीं कर रहे हैं और उन्हें अपनी चारपाई लाकर ईलाज करवाने की भी इजाजत दे रहे हैं। हम अपने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, सी.एच.सी., पी.एच.सी. और सब-सैंटर इत्यादि सभी जगह का अध्ययन करवा रहे हैं। अध्ययन हो जाने के बाद हम अपने अस्पतालों की बैड स्ट्रैंग्थ बढ़ाएंगे। मैं in one flow स्वास्थ्य

विभाग का कायाकल्प करना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि मैं उनके विधान सभा क्षेत्र रानिया का विशेष ध्यान रखूंगा।

श्री रामचंद कम्बोज : अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र के अस्पतालों की बिल्डिंग और क्वार्टर्स की स्थिति ऐसी है कि वहां डॉक्टर्स को भी रैंट पर मकान लेकर रहना पड़ता है। अत : मंत्री जी इनके निर्माण की 6 महीने या एक साल की अवधि निश्चित कर दें कि हम इस दिन तक इन क्वार्टर्स और बिल्डिंग का निर्माण कर देंगे। मुझे डर है कि मंत्री जी इनके निर्माण की सिर्फ बातें करते न रह जाएं और उनका कार्यकाल समाप्त हो जाए क्योंकि इस सरकार से पहले 10 साल में भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। अगर आप मेरे क्षेत्र में इनका निर्माण जल्दी से करवा देंगे तो मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करूंगा।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक मेरा कार्यकाल समाप्त नहीं होगा। मैंने यह बात सिर्फ रानिया विधान सभा क्षेत्र के लिए नहीं कही है बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए कही है। मैं हरियाणा सरकार का स्वास्थ्य मंत्री हूं और मुझे पूरे हरियाणा प्रदेश के स्वास्थ्य की फिक्र है। मैं इनके क्षेत्र में बिल्डिंग्स और क्वार्टर्स के निर्माण के लिए समयावधि निश्चित नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरे पास इसके एस्टीमेट्स बनकर नहीं आए हैं। We are working on it.

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, हैल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज की कोशिश है कि हैल्थ विभाग में जितनी भी कमियां हैं उनको दूर करके सुधार किया जाए। पिछले बजट के दौरान भी इनके यही प्रयास रहे हैं। उस वक्त बजट प्लान में स्वास्थ्य विभाग को जो पैसा मिलना था उसे भी कम कर दिया गया है। इस वर्ष स्वास्थ्य के लिए केवल 13 करोड़ रुपये बढ़ाये गए हैं। मेरा प्रश्न है कि इतने पैसों से मंत्री अस्पतालों में ये सुविधाएं कैसे मुहैया करवा पाएंगे ? हमने जब बजट को पढ़ा तो हमारी पार्टी के सभी सदस्य इससे चिंतित हो गए कि बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए सिर्फ 13 करोड़ रुपये बढ़ाए गए हैं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष जी, "नम्बर 1 हरियाणा" का प्रचार करने वाली पिछली सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किये थे। उन्होंने बजट में स्वास्थ्य के लिए कभी 2 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि नहीं की। मैंने कल भी कहा था कि किसी भी प्रदेश के स्तर को नापने के जो पैरामीटर्स होते हैं सोशल स्टैटिक्स क्या कहते हैं और हैल्थ इंडीकेटर्स क्या कहते हैं यह उस पर डिपैंड करता है। जिस प्रदेश में पिछले 30-40 सालों से स्वास्थ्य पर बजट का केवल 2 परसैंट खर्च किया जाता रहा हो, उसके स्वास्थ्य की क्या हालत होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं हैल्थ के बजट को बढ़ाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के नेता को बताना चाहूंगा कि हालांकि यह बजट मेरी उम्मीद के मुताबिक नहीं है लेकिन फिर भी 37 परसैंट हैल्थ का बजट बढ़ाया गया है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आपने हैल्थ का बजट इसलिए बढ़ाया होगा क्योंकि उतना कर्जा भी तो आपने ले रखा है। जब बजट बढ़ेगा तो कर्जा भी बढ़ेगा और 100 फीसदी आंकड़े बढ़ जाएंगे लेकिन एक्चुयल में प्लान बजट में इसके लिए 13 करोड़ रुपये ही बढ़ाया गया है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि मेरे पास इस समय डाटा नहीं है। यह अलग प्रश्न था अन्यथा मैं बजट का डाटा लेकर जरूर आता। हैल्थ का टोटल बजट 37.1 परसैंट बढ़ाया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि इसको बढाकर हमने कम से कम शुरूआत तो की है। पिछले साल हैल्थ का बजट 2857.28 करोड़ रुपये था और इस साल यह 3916.94 करोड़ हो गया है यानि 37.1 परसैंट की वृद्धि की गई है। पूरे हरियाणा से मुझे मुबारकबाद मिली है। कि मंत्री जी, आपने हैल्थ के बजट को बढ़ाया है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि यह उतना बजट नहीं है जितना मैं चाहता हूं तथा उतना नहीं है जितने की हमें जरूरत है। इसके लिए कोई अल्टरनेटिव अरैंजमैंट के बारे में हम जरूर सोच रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम कम्प्रीहैंसिव बजट बनाकर योजनाएं बना रहे हैं। आवश्कता पड़ी तो हम वर्ल्ड बैंक का भी दरवाजा खटखटाएंगे। मैं एक बार तो इस विभाग को ठीक करना चाहता हूं ताकि किसी भी तरह से हरियाणा के लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो सके।

श्री अभय सिंह चौटाला : मंत्री जी, हम आपके साथ हैं लेकिन आप इसके लिए वित्त मंत्री महोदय से कुछ बजट तो ले लो।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष जी, मैं नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी की भी अपनी सीमाएं होती हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या 1086

(इस समय यह प्रश्न पूछा नही जा सका क्योंकि माननीय सदस्य श्री नागेन्द्र भडाना सदन में उपस्थित नहीं थे।)

To open a Polytechnic College in Jind

***1001 Shri Hari Chand Middha :** Will the Technical Education Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Polytechnic College in Jind City; and

(b) if so, the time by which the above said Polytechnical college is likely to be opened ?

शिक्षा मंत्री : **(श्री राम बिलास शर्मा)** :

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय, हरिचंद जी ने जींद में पोलिटैक्निक कॉलेज खोलने के बारे में सवाल पूछा है। इनके प्रश्न के जवाब में 'नो सर' कहने को हमारा मन नहीं मानता क्योंकि हरिचंद मिढ्डा जी हैंडसम और नाइस एम.एल.एल. हैं। हम उनका सम्मान करते हैं। ये कैप्टन अभिमन्यु

को अपना भांजा कहते हैं इसलिए हम इनको मामा मानते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि जींद के नरवाना क्षेत्र के हथो गांव में यह बहुतकनीकी संस्थान आलरेडी चल रहा है। अब तक पूरे हरियाणा में जो इस तरह के संस्थान हैं उनके बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, अम्बाला शहर, कल्पना चावला राजकीय महिला बहुतकनीकी संस्थान, अम्बाला शहर, राजकीय महिला बहुतकनीकी सस्थान, फरीदाबाद, बहुतकनीकी संस्थान हिसार, बहुतकनीकी संस्थान, झज्जर, बहुतकनीकी संस्थान मंडी आदमपुर, हिसार, बाबा खेतानाथ राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, नारनौल्, ब्रहमानंद राजकीय बहुतकनीकी सस्थान, नीलोखेड़ी, राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, सिरसा और राजकीय महिला बहुतकनीकी संस्थान, सिरसा, , बहुतकनीकी संस्थान, सोनीपत, बहुतकनीकी संस्थान,उटावड़ पलवल, बहुतकनीकी संस्थान लोहारू, भिवानी और बहुतकनीकी संस्थान नाथू श्री चोपटा, सिरसा, बहुतकनीकी संस्थान मानेसर और बहुतकनीकी संस्थान मोरनी, पंचकूला में है और सांघी रोहतक में है और डाक्टर साहब की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि राजीव गांधी बहुतकनीकी संस्थान, नरवाना, जींद में है। इसी तरह से बहुतकनीकी संस्थान लिसाणा, रेवाड़ी में है, चीका, कैथल में है, सांपला रोहतक में है, उमरी, कुरूक्षेत्र में है। सेरगढ़, कैथल में है, दामला, यमुनानगर में है और रोहतक में है। अध्यक्ष महोदय, इनमें कुछ तो गवर्नमैंट एडिड इन्स्टीच्यूशंज हैं और कुछ सीधे-सीधे राजकीय हैं और जींद में अभी इस तरह का संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री हरिचन्द मिड्ढा : अध्यक्ष महोदय, हमारा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी जींद गये थे और वहां पर कालेज और ऑटो मार्केट बहुत जल्द बनाने की घोषणा करके आये थे। इस समय भी मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं भी गरीब हूं और मेरा जींद हल्का भी गरीब ही है इसलिए मंत्री जी वहां पर बहुतकनीकी संस्थान खोलने की कृपा करें, दोबारा से मंत्री जी नहीं में जवाब न दें।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मिड्ढा साहब में अपनी बात मनवाने की एक कला है। मैं मिड्ढा साहब पहले ही कह चुका हूं कि आपके सवाल पर हम नहीं में जवाब बहुत कम देते हैं। ऑटो मार्केट बनवाना तो मेरे बस की बात नहीं है और बहुतकनीकी संस्थान की प्रपोजल मिड्ढा साहब आप वहां से बनवाकर भिजवा दें हम उस पर जरूर विचार करेंगे।

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि समुचित हरियाणा प्रदेश में पिछली सरकार पोलिटैकनीक और इन्जीनियर कॉलेजिज का जाल खोलकर गई थी। आज भी टैकनीकल एजुकेशन में 1.45 लाख सीटे खाली पड़ी हैं। इस प्रकार का बेड़ा गर्क पिछली सरकार ने दस सालों में एजुकेशन के क्षेत्र में हरियाणा का किया। क्या इसको सुधारने की तरफ सरकार कोई कदम उठा रही है। पिछली सरकार के समय में अनाप-सनाप इन्जीनियरिंग की डिग्रीयां बांटी गई और आज वे युवक किसी लायक नहीं है क्या इस पर भी सरकार विचार करेगी ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस प्रश्न के लिए ढुल साहब को स्प्रेट नोटिस की जरूरत है लेकिन फिर भी मैं इनको बताना चाहूंगा कि 1.45 लाख सीटें टैक्नीकल एजुकेशन में भरी गई हैं और 44 हजार सीटें खाली रही हैं। इनकी यह बात सही है कि पिछली सरकार ने हर क्षेत्र में प्रदेश का बेड़ा गर्क किया है। इस पर मैं एक कहवात सुनाता हूं जो मैंने पिछले सैशन में भी सुनाई थी। एक गांव में एक लड़का रमलू था जो कोई काम-काज नहीं करता

[श्री राम बिलास शर्मा]

था। गांव के लोग उसे कहने लगे कि रमलू तो पूरे दिन इधर-उधर की बात करता रहता है तू कोई काम कर ले। रमलू ने कहा कि क्या काम करूं। गांव वालों ने उसे टांची लाकर दे दी और कहा कि तू चक्की राहने का काम कर ले। रमलू टांची लेकर काम पर निकल गया। एक बुढ़िया ने कहा कि मेरी चाक्की राह दे। बुढ़िया चाक्की रमलू को राहने के लिए छोड़कर पानी लेने चली गई। रमलू ने जोर से चौट मारी और जो बुढ़िया की पुराने पाट की चाक्की थी वह टूट गई। रमूल ने सोचा काम का पहला दिन था तेरी तो बुहणी ही खराब हो गई और बुढ़िया आयेगी तो मारेगी। वह जैसे ही भागने के लिए जल्दी में खड़ा हुआ तो ऊपर छिक्के में घी रखा था वह गिर गया और रमलू उस पर फिसल कर दरवाजे से जा टकराया जिसके कारण घर का पुराना कवाड़ भी टूट गया। उसके बाद रमलू बुढ़िया से टकरा गया और बुढ़िया का मटका भी टूट गया जिसमें वह पानी लेकर आई थी। बुढ़िया ने कहा अरे रमलू मैं तनैं कड़े-कड़े तैं रो लूं। रमलू ने कहा आगे-आगे चलती जा और मुझे रोती जा और संभालती जा। इसी तरह के कार्य पिछली सरकार ने दस सालों में किए हैं। उस दौरान बहुत ही विसंगतियां और बेकायदगियां हुई हैं।

श्री रणबीर गंगवा : स्पीकर सर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमारे गंगवा गांव के स्कूल के लिए प्रिंसीपल भेज दिया है मैं सबसे पहले तो माननीय शिक्षा मंत्री जी का इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। अब मेरी माननीय शिक्षा मंत्री जी से यही रिक्वैस्ट है कि वहां पर स्टॉफ भी जल्दी से जल्दी भेज दिया जाये ताकि वहां की छात्राओं की पढ़ाई आने वाले सैशन से जल्दी से जल्दी शुरू हो सके।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं गंगवा जी को यह कहना चाहूंगा कि यह ऐसी सरकार है जो बिना पक्ष और विपक्ष का विचार किये सभी माननीय सदस्यों के उचित सुझावों को खुले दिल से स्वीकार करती है। जैसे श्री केहर सिंह रावत जी ने एजुकेशन डिपार्टमैंट की पॉलिसी से सम्बंधित एक सुझाव सरकार को दिया है। हम उनके सुझाव पर उस पॉलिसी को बनाने के बारे में विचार करेंगे।

Completion of Roads

***1016. Shri Anoop Dhanak :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state the time by which the incomplete roads from Bhaini Badshahpur to Khedar and kinala to Daulatpura are likely to be completed togetherwith the details thereof ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : श्रीमान् जी, सड़क अनुसार ब्यौरा निम्न है—

ब्यौरा

क्रम संख्या	सड़क का नाम	निर्मित लम्बाई (कि0मी0 में)	मलकियत	पूर्ण होने की तिथि
1	भैणी बादशाहपुर से खेदड़	5.42	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	31-05-2016 तक
2	किनाला से दौलतपुरा	3.66	लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग	अभी यह नहीं कहा जा सकता जबकि इसे 2016-17 में शुरु किया जाना है।

श्री अनूप धानक : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी वैसे तो सब प्रश्नों का जवाब "ना" में देते हैं लेकिन उन्होंने मेरे प्रश्न का जवाब "हां" में दिया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूं।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, परसों मैंने भाई अनूप धानक जी से उनके क्षेत्र की उन सभी सड़कों की लिस्ट मांगी थी जिनकी रिपेयर ज़रूरी है। मैंने इनके सभी कामों की हां कर दी है। इन्होंने सबसे ज्यादा सवाल पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.) से सम्बंधित पूछे हैं। यह भाई अपोजीशन में बैठा है मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इनकी ज्यादा से ज्यादा सड़कों का काम जल्दी से जल्दी करूंगा।

श्री अनूप धानक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो किनाला से दौलतपुर का रोड है उसकी रिपेयर की भी समय सीमा मुझे बता दी जाये कि यह सड़क कब तक बनकर तैयार हो जायेगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह भी बताना चाहूंगा कि फरीदपुर से दौलतपुर, खिलाना से साहू और खैरी से साहू रोड पर भी इसी प्रकार से पत्थर बिछाये हुए हैं। वहां अभी तक कोई आगे का काम नहीं हुआ है। जो खैरी से साहू रोड है वह पहले 18 फुट का था लेकिन अब उसे 12 फुट का कर दिया गया है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसको भी 18 फुट का कर दिया जाये।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का यह निर्णय है कि जो भी सड़कें तीन गांवों को जोड़ती हैं उन सारी सड़कों की चौड़ाई 18 फुट की जायेगी और जो सड़क एक गांव को जोड़ती है उसको 12 फुट की रखेंगे। मैंने इनसे लिस्ट मांगी है इनकी लिस्ट में जो भी जायज़ होगा उस काम को जल्दी से जल्दी किया जायेगा।

———————

To Develop a Tourist Spot

***1157 Shri Tek Chand Sharma :** Will the Tourism Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to develop any tourist spot adjacent to the village Gadpuri/Aalhapur on National highway No. 2 partiularly in the midst of the Industrial area together with the time by which it is likely to be developed ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : श्रीमान, जी नहीं, इस प्रकार के स्थल विकसित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। माननीय स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने गदपुरी और आल्हापुर के पास विशेष ओद्योगिक क्षेत्र के बीच में कोई पर्यटन केन्द्र बनाने के बारे में पूछा है। यह बात सही है कि गदपुरी और आल्हापुर हाईवे के ऊपर हैं। इनके नज़दीक मैगपाई हमारा बड़ा पर्यटन केन्द्र है और ऐसे ही सूरजकुण्ड में भी बहुत ही बड़ा पर्यटन केन्द्र है।

श्री टेक चंद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मुझे माननीय मंत्री जी से इस प्रकार के जवाब की उम्मीद नहीं थी। मुझे यह आशा थी कि वे इस मामले में मेरा कुछ तो लिहाज़ करेंगे ही करेंगे। मैं तो यह चाहता था कि इनसे हमारी रिश्तेदारी के नाते इतना तो ये करेंगे ही करेंगे। इन्होंने जो जवाब दिया है उसके सम्बंध में मैं थोड़ा सा इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वहां से सूरजकुण्ड लगभग 45 किलोमीटर दूर है, वहां से होडल का पर्यटन केन्द्र डबचिक भी 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मेरा पृथला विधान सभा क्षेत्र दो जिलों पलवल और फरीदाबाद के अंदर बंटा हुआ है। इसके अंदर न तो कोई रैस्ट हाउस है और न ही कोई सर्किट हाउस ही है। यह एक बहुत ही तेज़ी से विकसित होता इण्डस्ट्रियल एरिया है। दिल्ली से जितने भी पर्यटक ताज़महल को देखने के लिए आगरा जाते हैं उनके लिए जी.टी. रोड पर कोई भी पर्यटन केन्द्र नहीं पड़ता है जो मैगपाई है वह भी बहुत दूरी पर स्थित है। हमारी सरकार का यह लक्ष्य है कि "सबका साथ, सबका विकास" इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पुन : निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर चाहे पी.पी.पी. मोड के तहत या फिर किसी और स्कीम के तहत वहां पर रैस्ट हाउस, सर्किट हाउस अथवा आधुनिक पर्यटन केन्द्र का निर्माण किया जाये। इसके साथ ही साथ मैं एक बात का और माननीय मंत्री जी को यह विश्वास दिलवाना चाहता हूं कि अगर वहां पर रैस्ट हाउस, सर्किट हाउस अथवा आधुनिक पर्यटन केन्द्र का निर्माण किया जाता है तो वह किसी भी तरह से इनकम के मामले में घाटे में नहीं जायेगा इसलिए इसका एक बहुत बड़ा फायदा सरकार को भी मिलेगा।

भारत स्थित पेरु के राजदूत का स्वागत

Chief Minister (Shri Manohar Lal) : Speaker Sir, Mr. Jose J.G. Betancourt R., Ambassador of Peru in India alongwith a delegation present in VIP Gallery, I, on behalf of this House welcome them.

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, श्री टेकचन्द शर्मा जी ने जो नैशनल हाईवे नं.2 पर गदपुरी और आल्हापुर के पास पर्यटक स्थल विकसित करने की बात कही है उस बारे में मेरा कहना है कि पर्यटक विभाग के फरीदाबाद में राजा नाहर सिंह, मैगपाई तथा होडल में डबचिक पर्यटक स्थल बने हुये हैं। गदपुरी और आल्हापुर वहाँ से 17 से 25 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इनकी यह बात भी सही है कि डबचिक वहाँ से 48 किलोमीटर दूर है लेकिन जो नाहर सिंह ट्यूरिस्ट कॉम्पलैक्स है वह इनके बिल्कुल नजदीक है और मैगपाई भी नजदीक ही है। दूसरी बात यह है कि गदपुरी की लोकेशन भी ठीक नहीं है इसलिए गदपुरी में ट्यूरिस्ट कॉम्पलैक्स बनाने का सरकार का इस समय कोई विचार नहीं है।

श्री टेकचन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र पृथला में न तो कोई सरकारी रैस्ट हाउस है और न ही कोई सर्किट हाउस है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वहाँ पर कम से कम एक ट्यूरिस्ट कॉम्पलैक्स बनाने की कृपा करें। जहाँ तक राजा नाहर सिंह ट्यूरिस्ट कॉम्पलैक्स की बात है तो वह हाईवे से अन्दर जा कर है इसलिए वहाँ पर बहुत कम ट्यूरिस्ट आते हैं। गदपुरी में 2 एकड़ जमीन हाईवे पर पड़ी हुई है इसलिए उसका कोई सर्वे करवा कर उस पर ट्यूरिस्ट कॉम्पलैक्स बनवाने के लिए विचार किया जाये।

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ये जो ट्यूरिज्म विभाग के कॉम्पलैक्सिज बनते हैं ये लोकेशन के हिसाब से बनते हैं। जिस प्रकार से बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह का नाम बहुत प्रसिद्ध है इसलिए उनके नाम से बल्लभगढ़ में बहुत बड़ा ट्यूरिस्ट कॉम्पलैक्स बनाया गया है। इसी प्रकार से सूरजकुंड में भी आप जानते हैं कि पांडु पुत्रों के कारण वह जगह प्रसिद्ध है। अभी कुछ दिन पहले सूरजकुंड मेले में 23 देशों के 20 लाख लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। अध्यक्ष महोदय, जो पृथला विधान सभा क्षेत्र है उसकी लोकेशन बीच में पड़ती है और वहाँ पर सघन आबादी है। माननीय विधायक की यह बात सही है कि उनके विधान सभा क्षेत्र में कोई भी रैस्ट हाउस या सर्किट हाउस नहीं है इसलिए इस बात पर हम अवश्य विचार करेंगे।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, पूरे हरियाणा में मेवात ही अकेला जिला है जहाँ पर कोई भी ट्यूरिस्ट कॉम्पलैक्स नही है। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि फिरोजपुर झिरका में शिवजी का एक प्राचीन झिर मंदिर है और लाखों की संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उनके ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि फिरोजपुर झिरका में झिर मंदिर के पास एक ट्यूरिस्ट कॉम्पलैक्स बनाया जाये। इसके अतिरिक्त आजकल ऐडवेंचर के लिए लोग देहरादून और मनाली जाते हैं लेकिन यहाँ झिर मंदिर के पास ऐडवेंचर के लिए बहुत उपयुक्त जगह है इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वहाँ पर ऐडवेंचर का कोई सैंटर भी खोला जाए।

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी श्री नसीम अहमद की बात सही है कि फिरोजपुर झिरका में शिवजी का प्राचीन झिर मंदिर है और वहाँ पर साल में दो बार शिवरात्रि पर बहुत बड़ा मेला लगता है। वहाँ पर पूरे मेवात, तिजारा, अलवर, भरतपुर, फरीदाबाद, फिरोजपुर झिरका, तावडू और हथीन आदि क्षेत्रों से लाखों की संख्या में लोग आते हैं। वहाँ पर 1987 में पानी की समस्या आई थी उस समय मेरे पास यह विभाग था तब हमने वहाँ पर एक ट्यूबवैल बोर किया था। हम इस बारे में अवश्य विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

To Construct a Paddock

***1131. Smt. Renuka Bisnoi :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Municipal Council had passed a resolution to construct a paddock to solve the problem of helpless and stray cattles in the area of Hansi; if so, the details thereof; and

(b) The scheme of the Government for the permanent solution of helpless and stray cattles in Hansi area together with the details thereof ?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) :

(क) हां, श्रीमान् जी। नगर परिषद हांसी, द्वारा पुत्थी रोड पर स्थित कसाई खाने के नजदीक एक मवेशी खाने का निर्माण करने हेतु दिनांक 19-12-2014 को प्रस्ताव पास किया गया है।

(ख) वर्तमान में हांसी क्षेत्र में आवारा मवेशियों को पनाह देने हेतु 2 गौशालायें है। सरकार द्वारा आवारा मवेशियों की देखरेख के लिये गौ-अभ्यारण्य के निर्माण हेतु जिला हिसार में राजकीय पशुधन फार्म से सम्बन्धित 50 एकड़ जमीन को चिन्हत किया गया है तथा इस हेतु ₹10 करोड का अनुमान तैयार किया गया है।

———————

Damage to Crops

***1384. Smt. Prem Lata :** Will the Agriculture Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that sudden change in weather pattern resulted in crop damage, poor yield and loss of income to the farmers in Kharif last year 2015; if so, the total loss incurred by farmers;

(b) whether there is any proposal to compensate the farmers alongwith details thereof; and

(c) the contingency plan drawn by the Government to overcome climate change togetherwith the action initiated by Agriculture University to produce seeds which can withstand the severe weather pattern ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

(क) नहीं श्रीमान् जी, हालांकि खरीफ 2015 में कीट के हमले (सफेद मक्खी) ने कपास फसल को प्रभावित किया है।

(ख) हां श्रीमान् जी, 967 करोड रुपये की राशि प्रभावित किसानों को वितरण के लिए पहले ही जारी कर दी गई है।

(ग) चौ0 चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हिसार ने आकस्मिक फसल योजना तैयार की है। इसके द्वारा बाजरा की मौसम प्रतिरोधी किस्में नामत: HHB 667-I, HHB 234 और HHB 226 तथा ग्वार की HG 365, HG 563 और HG 220 किस्में जारी की गई है। चौ० चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हिसार द्वारा ऊपर दी गई बाजरा की किस्मों के बीज उत्पादन बढ़ाने तथा बीज वितरण के लिए उत्पादकों के साथ समझौता ज्ञापन किए गए हैं। प्रतिकूल अजैविक प्रभाव को कम करने के लिए चौ0 चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, विभिन्न फसलों पर अनुसंधान कर रहा है।

———————

Repair/Reconstrution of CHC Buildings

***1149. Shri Pirthi Singh :** Will the Health Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that building of CHC in village Ujjana of Narwana Assembly constituency is in dilapidated condition; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to repair or to re-construct the abovesaid building togetherwith the time by which it is likely to be repaired/ reconstructed ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) :

(क) नहीं श्रीमान जी।

(ख) यद्यपि गांव उझाना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अतिरिक्त भवन के निर्माण हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

———————

To Promote Women Entrepreneurship

***1283. Shri Jasbir Singh :** Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to promote women entrepreneurship in the State; if so, the details thereof ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : हां श्रीमान, एक वक्तव्य सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

वक्तव्य

राज्य में महिला उद्यमिता को बढावा देने के लिए राज्य सरकार ने निम्नलिखित प्रावधान किये है :

1. हरियाणा राज्य ओधोगिक एवं सरचना निगम की ई0पी0पी 2015 नीति के अनुसार (चैपटर-3, क्रम संख्या 3.4 आबटन प्रक्रिया) राज्य में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए, महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित की जा रही परियोजना को 5 अंकों की अतिरिक्त अहमीयत दी जाती है।

2. निर्यात अवार्ड योजना के अर्न्तगत, राज्य निर्यात अवार्ड के लिये अवार्ड धनराशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये तथा सांत्वना पुरस्कार के लिये 21,000/- रुपए से 51000/ - रुपये बढा दी है।

3. राज्य से सम्बन्धित उत्कृष्ठ कलाकारों/बुनकरों को पेन्टिग, मिट्टी के वस्तुओं, पत्थर एवं मार्बल, कसीदाकारी एवं टैक्सटाईल, लकड़ी एवं बांस, धातु चमड़ा, हैन्डलूम जूट, मोम एवं लाख श्रेणी में 3 लाख रुपये की धनराशि का, एक सर्वश्रेष्ठ महिला कलाकार हस्तशिल्प अवार्ड प्रदान किया जायेगा।

4. प्रधानमंत्री रोजगार उत्पादन कार्यक्रम योजना, जो भारत सरकार की एक महत्वाकाक्षी

[कैप्टन अभिमन्यु]

योजना है, इसको ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने तथा कलाशिल्पियों की अर्जन क्षमता में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भी क्रियान्वित किया जा रहा है। महिला उद्यमियों को बढावा देने के लिये, उनसे योगदान, परियोजना लागत का सामान्य श्रेणी से 10 प्रतिशत की तुलना में 5 प्रतिशत की दर से बहुत कम रखा गया है तथा परियोजना लागत की सब्सिडी की दर सामान्य श्रेणी मामलों के लिये शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमश: 15 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत की तुलना में 25 प्रतिशत एवं 35 प्रतिशत रखा गया है। प्रधानमन्त्री योजना के अर्न्तगत महिला उद्यमियों के लिए 30 प्रतिशत का आरक्षण भी रखा गया है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Functioning of PHC

320. Shri Hari Chand Midda : Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that the Primary Health Centre in Village Lohchab is not functioning is so, the time by which it is likely to be short functioning togetherwith the total number of Primary Heath Centres and Community Health centres in Jind Assembly constituency ?

स्वास्थ्य मंत्री (अनिल विज) : श्रीमान जी, गांव लोहचब में कोई स्वास्थ्य संस्था नहीं है और इसलिए गांव लोहचब में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कार्य करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जीन्द विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है।

Construction of Tehsil Building

304. Shri Rajdeep Phogat : Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state the time by which the construction work of New Tehsil Building in Baund Kalan town is likely to be started ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान जी, उप-तहसील बौंद कलां की नई इमारत के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित की जा रही है। जैसे ही भूमि उपलब्ध हो जायेगी, निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

Financial liabilities of the Sugar Mills

340. Shri Karam Singh Dalal : Will the Minister of State for Cooperation be pleased to state the financial Health of each Sugar Mill in the State from the year 2015 till to date togetherwith the loan/financial liability of each sugar Mill of the State ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बिक्रम सिंह यादव): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है

विवरण

(क) **चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति**

वर्ष 2015 से आज तक के दौरान राज्य में प्रत्येक चीनी मिल की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :—

सहकारी चीनी मिलें

(रुपये करोड़ों में)

मिल का नाम	वर्ष 2014-15 के दौरान (+)लाभ (-)हानि	वर्ष 2015-16 में अबतक का अनुमानित (+)लाभ / (-)हानि
पानीपत	-51.69	-45.00
रोहतक	-79.71	-63.54
करनाल	-54.05	-35.04
सोनीपत	-50.40	-40.00
शाहबाद	-74.64	-42.00
जींद	-47.36	-54.97
पलवल	-41.22	-40.50
महम	-68.94	-79.50
कैथल	-61.28	-46.34
गोहाना	-60.18	-43.61
असंध	-37.62	-18.71
कुल	**-627.09**	**-509.21**

निजी चीनी मिलें

(रुपये करोड़ों में)

मिल का नाम	वर्ष 2014-15 के दौरान (+)लाभ (-)हानि	वर्ष 2015-16 में अबतक का अनुमानित (+)लाभ / (-)हानि
यमुनानगर	-45.20	-19.31
भादसों	-20.01	-10.00
नारायणगढ़	-26.33	-10.55
कुल	**-91.54**	**-39.86**

[श्री विक्रम सिंह यादव]

(ख) चीनी मिलों के ऋण /वित्तीय देनदारियां।

दिनांक 10-3-2016 तक चीनी मिलों के ऋण/वित्तीय देनदारियों का विवरण निम्न प्रकार है :—

सहकारी चीनी मिलें

मिल के नाम	राज्य सरकार द्वारा ऋण	अन्य द्वारा ऋण (HAFED+ HUDA+ HSAMB+ SDF etc.)	राज्य सरकार व हैफड आदि द्वारा प्रदान ऋण पर ब्याज की देनदारी	केन्द्र सरकार की स्कीम तहत सहकारी बैंकों से एकसाईज डयूटी के एवज़ में ऋण	गन्ना किसानों की बकाया राशि
पानीपत	123.85	52.39	58.46	11.30	34.47
रोहतक	199.35	23.07	41.62	17.17	63.56
करनाल	72.20	12.35	12.15	15.86	26.77
सोनीपत	126.05	4.13	41.22	12.11	26.22
शाहबाद	0.00	38.39	0.73	30.48	49.81
जींद	137.35	5.08	27.24	9.91	32.60
पलवल	113.65	1.69	23.19	8.74	33.75
महम	131.45	22.04	39.52	12.38	28.93
कैथल	154.80	9.32	48.45	13.07	32.54
गोहाना	69.80	12.21	11.52	14.31	25.26
असंध	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33
कुल	**1128.50**	**180.67**	**304.10**	**145.33**	**367.24**

निजी चीनी मिलें

(रुपये करोड़ों में)

मिल के नाम	राज्य सरकार द्वारा ऋण	अन्य द्वारा ऋण (HAFED+ HUDA+ HSAMB+ SDF etc.)	राज्य सरकार व हैफड आदि द्वारा प्रदान ऋण पर ब्याज की देनदारी	केन्द्र सरकार की स्कीम तहत सहकारी बैंकों से एकसाईज डयूटी के एवज़ में ऋण	गन्ना किसानों की बकाया राशि
यमुनानगर	100.00	0.00	2.17	71.24	46.87
भादसों	45.00	87.71	0.00	7.10	48.87
नारायणगढ़	30.82	0.00	0.45	26.36	23.28
कुल	**175.82**	**87.71**	**2.62**	**104.7**	**119.02**

Total number of Incidents of Dacoity

321. Shri Hari Chand Middha : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of incidents of dacoity registered in the state during the year from October, 2014 to February, 2016; and

(b) the total number of cases of dacoity traced during the year from October, 2014 to February, 2016 togetherwith the district wise details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

डकैटी जिला	बिन्दू क दर्ज घटनायें	बिन्दू ख हल हुये मुकदमें
1	2	3
गुड़गांव	37	22
फरीदाबाद	21	9
अम्बाला-पंचकूला	7	6
हिसार	13	11

[श्री मनोहर लाल]

1	2	3
सिरसा	7	7
भिवानी	23	12
जीन्द	7	6
फतेहाबाद	3	3
रेवाड़ी	17	16
पलवल	16	13
नरनौल	7	4
मेवात	27	23
रोहतक	18	11
सोनीपत	8	6
पानीपत	16	11
झज्जर	11	10
करनाल	5	3
यमुनानगर	8	5
कुरुक्षेत्रा	8	6
कैथल	1	1
रेलवेज	6	5
कुल योग	**266**	**190**

Bus Queue Shelters in Each Village

305. Shri Rajdeep Singh Phogat : Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Bus queue shelters on the main bus stops in each village of Dadri constituency; if so, the time by which these are likely to be constructed ?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : श्रीमान् जी, नहीं।

Various Development Works in Municipal Areas

341. Shri Karan Singh Dalal : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the amount of money given to each Municipality of the state including each Municipal Corporation from the year 2012 till to date for various Development works in above mentioned Municipal areas of the state ?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री (श्रीमती कविता जैन) : राज्य की विभिन्न पालिकाओं को वर्ष 2012-13 से अब तक जारी की गई राशि का विवरण अनुबन्ध 'क' पर प्रस्तुत है।

विवरण

अनुबन्ध 'क'

(₹ लाखों में)

क्र0 सं0	जिले का नाम	नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (14-03-2016 तक
1	2	3	4	5	6	7
1	अम्बाला	अम्बाला	5225.65	5007.62	4105.53	8910.11
2		नारायणगढ़	780.73	345.27	546.24	403.88
3		बराड़ा	0.00	0.00	0.00	302.94
4	भिवानी	भिवानी	2192.59	1273.22	2310.21	3308.95
5		बुवानी खेड़ा	272.83	289.23	636.09	385.85
6		चरखी दादरी	730.42	792.11	559.78	948.41
7		लोहारु	274.30	254.08	290.95	321.57
8		सिवानी	254.58	248.23	279.68	384.90
9	फरीदाबाद	फरीदाबाद	29440.98	29485.46	23433.65	26708.30
10	फतेहाबाद	भूना	132.52	360.09	398.96	462.52
11		फतेहाबाद	2787.75	668.25	951.96	848.18
12		रतिया	657.89	454.47	492.78	595.84
13		टोहाना	962.61	684.66	1070.36	1375.09
14	गुड़गांवा	गुड़गांवा	19692.79	12793.88	11565.82	13468.28
15		फारुखनगर	362.88	180.42	366.98	238.75
16		हेली मण्डी	471.89	342.25	489.58	531.20
17		पटौदी	555.65	345.87	492.72	448.31
18		सोहना	1424.01	780.89	638.40	1035.43
19	हिसार	हिसार	6206.15	3560.83	6776.85	5141.34
20		बरवाला	999.45	613.18	661.96	860.02
21		हांसी	945.04	788.43	1029.53	1393.05
22		नारनौंद	312.88	275.83	515.07	406.60
23		उकलाना मण्डी	236.91	338.21	322.29	386.31
24	झज्जर	बहादुरगढ़	2658.33	1187.27	3846.95	2589.16

[श्रीमती कविता जैन]

1	2	3	4	5	6	7
25		बेरी	507.08	892.77	242.19	281.16
26		झज्जर	730.50	1180.65	1522.25	816.11
27	जीन्द	जीन्द	2703.65	1936.29	1184.44	1435.50
28		जुलाना	265.05	272.05	312.91	350.19
29		नरवाना	769.83	627.23	686.72	801.31
30		सफीदों	736.78	585.53	799.36	713.47
31		उचाना	218.30	174.98	396.73	286.01
32	कैथल	कैथल	1857.42	1281.67	2308.57	1492.00
33		चीका	568.33	450.11	679.92	603.22
34		कलायत	497.44	292.77	326.33	421.71
35		पुण्डरी	425.28	345.31	572.55	481.21
36		रजौन्द	0.00	69.61	176.59	321.36
37	करनाल	करनाल	4002.66	6104.81	6487.91	7383.26
38		असन्ध	742.06	460.08	704.30	621.47
39		घरौण्डा	552.72	531.20	773.30	719.63
40		इन्द्री	176.87	191.08	391.50	852.08
41		नीलोखेडी	263.44	227.85	455.26	303.93
42		निंसिग	218.03	162.91	384.86	214.45
43		तरावडी	632.05	690.81	957.31	931.69
44	कुरुक्षेत्र	थानेसर	2270.79	1095.40	1746.76	1911.26
45		पेहवा	582.86	729.38	968.57	614.66
46		शाहबाद	919.82	771.46	1030.70	1001.23
47		लाडवा	537.11	520.15	773.99	685.73
48	मेवात	फिरोजपुर झिरका	303.78	282.93	317.86	360.45
49		नूंह	450.00	302.26	529.44	298.77
50		पुन्हाना	356.59	300.46	461.68	368.64
51		ताबडू	430.52	372.07	542.11	737.08
52	महेन्द्रगढ़	अटेली मण्डी	114.89	108.07	390.35	346.14
53		कनीना	226.20	172.78	431.36	428.32

1	2	3	4	5	6	7
54		महेन्द्रगढ	1112.71	549.11	505.25	475.47
55		नारनौल	1454.05	1206.52	1006.67	1008.36
56		नागल चौधरी	0.00	143.43	342.74	226.80
57	पंचकुला	पंचकुला	3388.04	5129.96	5439.42	5767.48
58	पानीपत	पानीपत	4446.70	7485.89	5630.39	7617.74
59		समालखा	945.90	404.44	968.15	1007.48
60	पलवल	होडल	664.47	688.97	925.38	887.98
61		हथीन	268.07	222.14	258.08	921.34
62		पलवल	1312.04	967.09	1344.36	1089.17
63	रेवाडी	बावल	280.40	193.82	445.91	756.95
64		धारुहेडा	604.18	387.75	671.41	505.66
65		रिवाडी	1613.19	1047.99	1656.57	2381.15
66	रोहतक	रोहतक	3918.07	5558.61	7117.76	6066.95
67		कलानौर	398.55	266.83	778.75	367.60
68		महम	355.51	354.81	834.81	468.39
69		सापला	383.97	360.57	528.00	291.31
70	सिरसा	डबवाली	741.15	632.27	655.95	803.82
71		ऐलनाबाद	469.21	434.37	451.28	531.60
72		कालावाली	344.92	277.34	302.66	343.36
73		रानिया	496.77	286.87	319.03	373.76
74		सिरसा	2385.05	1193.84	1272.19	1592.54
75	सोनीपत	गन्नौर	1370.07	449.64	1085.15	589.67
76		गोहाना	1158.21	874.17	1103.33	992.52
77		खरखौदा	556.76	352.88	360.17	423.22
78		सोनीपत	5714.79	5361.22	2670.58	5052.92
79	यमुनानगर	यमुनानगर	4842.53	5070.96	6629.18	6942.03
	नगर परिषदों/नगर पालिकाओं की स्टाम्प डयूटी		15200.00	11244.36	18025.01	19500.00
	कुल		**154034.18**	**133348.26**	**149666.32**	**164222.12**

नोट :- नगर परिषद व नगर पालिकाओं की स्टाम्प डयूटी के लिए सम्बन्धित उपायुक्तों को बजट अलाट किया गया है।

———————

Sewerage System of Jind City

322. Shri Hari Chand Middha : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether it is a fact that the sewerage system of Jind City is in very bad condition; if so, the steps taken by the Government to improve the condition of the sewerage system togetherwith the amount spent by the State Government thereon ?

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी राज्य मंत्री (श्री घनश्याम सर्राफ): नहीं श्रीमान जी। जीन्द शहर में सीवरेज प्रणाली ठीक प्रकार से कार्य कर रही है।

---

306. Shri Rajdeep Phogat : Will the P.W. (B.&R) Minister be pleased to state the time by which the reconstruction work of the bridge of canal on Dadri Delhi Road between village Morwala and Imolota is likely to be completed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : दादरी-दिल्ली सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग 334बी) पर इस पुल के पुनर्निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए इसके पूर्ण होने के लिए कोई समय सीमा अभी नहीं बताई जा सकती ।

Faridabad as a Smart City

342. Shri Karan Singh Dalal : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether Faridabad city has been selected to be Smart city in the country, if so, the details thereof ?

सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मन्त्री (श्रीमती कविता जैन) : फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी के रुप में विकसित करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चयनित किया गया है, जिसके अन्तर्गत 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रुप में विकसित करने के लिए चयनित किया गया है। यद्पि, फरीदाबाद इसका हिस्सा नहीं है।

Library in Village Bound Kalan

310. Shri Rajdeep Phogat : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government library in Village-Baund Kalan; if so, the time by which it is likely to be opened ?

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : नहीं श्रीमान् जी।

दलित कन्या के बलात्कार का मुद्दा उठाना

परमिन्दर सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, कल रात से टेलीविजन पर एक भयंकर दर्दनाक खबर दिखाई जा रही है जिसमें महेन्द्रगढ़ जिले की एक दलित लड़की के साथ रेप हुआ है उसकी नंगी तस्वीरें टेलीविजन पर पिछले 6 दिनों से दिखाई जा रही हैं लेकिन अभी तक इस बारे में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और न ही किसी को गिरफ्तार किया गया है। वहां

महेन्द्रगढ़ में कंवरपाल ढ़ालु भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के उपाध्यक्ष हैं उनके बेटे को इस मामले में बचाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ कल सारी रात फास्ट चैनल पर उस लड़की की वीडियो दिखाई जा रही है। मैं सदन के नेता से जानना चाहूंगा कि वह इस बारे में बताएं कि जिस दलित लड़की के साथ रेप हुआ है और जिसका नाम* * * है और जिसके पिता का नाम सतबीर है उसको आज सात दिन हो गये कहीं कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उसकी नंगी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यहां पीड़िता का नाम नहीं ले सकते इसलिए आप लड़की के नाम को कार्यवाही से निकलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है उस लड़की का नाम कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे साथी विधायक श्री परमिन्दर सिंह ढुल जी ने बहुत ही सैंसिटिव विषय उठाया है। जहां तक बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की बात थी। अगर हरियाणा प्रदेश में इस तरह का कोई घिनौना कार्य होता है अगर उसकी तस्वीरें टेलीविजन पर दिखाई जाती हैं और अगर वह मीडिया में आई है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो यह सरकार के लिए एक शर्मिंदगी की बात है। सदन के नेता को इसके ऊपर तत्काल बताना चाहिए कि हम उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। कब तक उन लोगों को पकड़ लिया जाएगा ताकि दलित के साथ जो घटना घटी है कम से कम सदन में जब इस तरह की बात आ जाए तो फिर सदन के नेता की जिम्मेवारी बनती है कि वह उसके ऊपर अपना जवाब जरूर दें।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, सदन की समाप्ति से पहले इस विषय पर जवाब दे दिया जाएगा।

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : अब संसदीय कार्यमंत्री नियम-30 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं -

> कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 30 को निलंबित किया जाए तथा वीरवार 31 मार्च 2016 को सरकारी कार्य किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

> कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 30 को निलंबित किया जाए तथा वीरवार 31 मार्च 2016 को सरकारी कार्य किया जाए।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 30 को निलंबित किया जाए तथा वीरवार 31 मार्च 2016 को सरकारी कार्य किया जाए।

प्रस्ताव पारित हुआ।

वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा पुनरारम्भ तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण अब वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भ होता है।

मुख्य संसदीय सचिव (डॉ. कमल गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मैं इस महान सदन में सदन के नेता, नेता प्रतिपक्ष और मेरे सभी भाई-बहन जो अपनी-अपनी बात अपनी बुलंद आवाज में उठाते रहते हैं उन सबको मैं वंदन करता हूं और उन सभी को भारत माता की जय और वंदे मातरम् कहता हूं। मैं अपनी बात शुरू करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि --

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी आप केवल मेरे को संबोधित करें न कि जन सभा की तरह सबको नाम लेकर।

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, 'जाना था उनको दूर, बहाने बना लिये, न जाने कहां-कहां उन्होंने ठिकाने बना लिये।' कांग्रेस के हमारे मित्रों ने सबसे पहले तो महामहिम राज्यपाल की मौजूदगी में उनके अभिभाषण की प्रतियां सदन में फाड़ डाली और उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। सदन में बजट भी पेश हुआ तथा आरक्षण बिल भी सर्वसम्मति से पास हुआ, इन सभी कार्यवाहियों के दौरान कांग्रेस के मित्र सदन से बाहर रहे। इस तरह की चीजें स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत घातक सिद्ध होती हैं। क्योंकि :-

गिरते हैं स-सवार ही, मैदान-ए-जंग में,
वो क्या गिरेगा, जो घुटने के बल चले।

सदन में तो हमने बहुत तरह की चर्चाएं और लड़ाईया होती देखी हैं। उत्तर प्रदेश की विधान सभा में माईकों और जूतों से एक दूसरे पर वार करते हुए देखा जा सकता है लेकिन सदन की किसी भी चर्चा में भाग न लेना और सदन से भाग जाना, कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई दूसरी हो नहीं सकती है। यह दुख की भी बात है। मैं अपनी बात की तसदीक रामायण में तुलसीदास जी की चौपाई से शुरू करता हूँ। यह चौपाई उस समय के वाक्या को दर्शाती है जब भरत वन में राजा राम को लेने जाते हैं और राजा राम ने आने से इंकार कर दिया तो ऐसी स्थिति में भरत उनकी खड़ाऊ को सिर पर रखते हैं और अयोध्या नगरी वापिस आने के लिए आग्रह करते हैं। इस अवस्था में प्रभु श्री राम जी भरत को, मुखिया कैसा होना चाहिए, उसका वर्णन करके बताते हैं। मुखिया कैसा होना चाहिए इसके बारे में चौपाई के माध्यम से बताया गया है कि :-

मुखिया मुख सो चाहिए, खान-पान महु एक,
पालहई, पौ साई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक।

कहने का मतलब यह है कि हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे मुखिया हैं। इस चौपाई में मुखिया को मुख जैसा बताया गया है अर्थात जिस प्रकार मुख सब कुछ ग्रहण तो करता है लेकिन अपने पास कुछ नहीं रखता है लेकिन अपने शरीर के सभी अंगों को यथाशक्ति, यथा-योजना के हिसाब से चाहे वह हाथ हों, चाहें वह पैर हों, चाहे वह सिर हो, चाहें वह दिमाग हो या चाहें फिर वह आंतें हों सबको समान वितरण करते हुए समान विकास का काम करता है उसी प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 'सबका साथ-सबका विकास' नीति पर कार्य करते हैं। इस प्रकार के राज के मुखिया का वर्णन भगवान श्री राम जी ने भरत को बताया। मैं समझता हूँ कि उसी भावना के नीमित हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी समस्त समाज के कल्याण की भावना रखते हैं। डेढ़ साल के कार्यकाल में सरकार ने पिछले पचास सालों से सत्ता का सुख भोग रही सरकार के कार्यों पर अपने डेढ़ साल के अच्छे कार्यों की एक छाप छोड़ी है। जब प्रदेश में ओलावृष्टि की वजह से फसलों को नुकसान हुआ तो इस सरकार ने एक हजार बानवे करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों को दिया। आज तक किसी भी सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में भी कभी इतना मुआवजा नहीं दिया था। इसके बाद जब सफेद मक्खी की वजह से पांच जिलों में नरमे की फसल खराब हुई तो उसके लिए 967 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर देने का काम किया गया। यह आज तक का एक रिकॉर्ड है। अभी पिछले दिनों जब जाट आरक्षण की आड़ में लोगों की दुकानों को जलाया गया तथा अनेक नुकसान किए गए तो सरकार ने व्यापारियों और निर्दोष लोगों को फिर से अपना जीवन संवारने के लिए जो मुआवजे की राशि देने की प्रक्रिया आरम्भ की वह आज तक के इतिहास में बेमिशाल है। जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से इतनी दरियादिली से मुआवजा कभी नहीं दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकलांगों व वृद्धों के लिए, निसहाय के लिए जो पैशन पहले 1000 रुपये होती थी उसको प्रति वर्ष 200 रुपये के हिसाब से बढ़ाने का जो प्रावधान किया है वह भी बेमिसाल है। इस तरह से चाहे खिलाड़ियों को इनाम देने की बात हो या फिर फसल बीमा करने की बात हो, ऐसी अनेक अच्छी बातें हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने इस डेढ़ साल के छोटे से कार्यकाल में करके दिखलाई हैं और उनकी रहनुमाई में हमारे वित्त मंत्री ने भी ऐसे समय में जो यह दूसरा इतना बढ़िया बजट पेश किया है वह भी बेमिसाल कहा जायेगा। कोई भी नई चीज बनाना आसान होता है लेकिन पुरानी को ठीक करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। किसी भी कपड़े को काटकर नया कोट बनाया जा सकता है। पिछली कांग्रेस की सरकार जो छोटा कोट बनाकर चली गई है उसको कांट-छांटकर दोबारा से ठीक करना यह बहुत ही मुश्किल काम है। वेदों में कहा गया है कि :-

सो धन धन्य, प्रथम गति जाकी

यहां पर धन का मतलब बजट से है और वेदों में लिखी गई इन लाईनों में धन की तीन गतियों का वर्णन किया गया है। जिनका वर्णन इस प्रकार है :-

प्रथम जन कल्याण (उत्तम गति)
निज कल्याण (निकृष्ट गति)
अराजकता आतंक (अति निकृष्ट)

धन की पहली गति से पूरे जन का कल्याण होता है। दूसरी निज कल्याण गति जिसको निकृष्ट गति कहते हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी ने हमेशा निज कल्याण के काम किए हैं। तीसरी अराजकता आंतक जिसे अति निकृष्ट गति कहते हैं। इन तीनों गतियों में सौ धन धन्य जो पहली उत्तम गति

[डॉ. कमल गुप्ता]

माननीय वित्त मंत्री महोदय ने प्रदान की इसके लिए मैं इन्हें बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। माननीय वित्त मंत्री मोहदय ने जो बजट पेश किया है, यह सौम्य, सुन्दर, स्वादिष्ट, सुहावना और सबका पसंदीदा है। पिछले वर्षों से जो मंदी का दौर चल रहा है, इससे लोग निराश और हताश हैं। सरकार को मंदी के दौर को दूर करने के लिए अपने खर्चे बढ़ाने होंगे रेवेन्यू एक्सपैंडीचर करना पड़ेगा तो कैपिटल गेन करना पड़ेगा कैपिटल रिसीट करनी पड़ेगी। यदि कैपिटल रिसीट करेंगे तो लोगों में पैसा जायेगा तो उससे मंदी का दौर दूर होगा। अध्यक्ष महोदय, पिछले साल से इसका मुकाबला करें तो हम बजट को at a glance देंखे तो वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 में जो रेवेन्यू रिसीट हुई हैं उसमें 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2016-17 का जो बजट अनुमान पेश किया गया है, उसमें रेवेन्यू रिसीट में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू रिसीट में वृद्धि का मतलब है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार कम हुआ है। सरकार ने टैक्सों की रिकवरी ज्यादा वसूल की है। जब सरकार रेवेन्यू टैक्सिज की रिसीट ज्यादा करेगी तो उससे definitely हमारा फिस्कल डैफिसिट रेवेन्यू एक्सपैंडिचर घटेगा। कैपिटल डैफिसिट में भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में भी वर्ष 2014-15 में 40 प्रतिशत की वृद्धि थी। वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 में जो बजट पेश किया गया है उसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि है। अध्यक्ष महोदय, यह बजट का बहुत अच्छा इंडेक्स है। अर्थ शास्त्रियों का नियम है कि जब हमारी रिसीट्स चाहे वो टैक्स की हो चाहे व नॉन टैक्स की हों उसमें वृद्धि होगी तभी हमारी जी.डी.पी. बढ़ेगी। बजट में मुख्य जड़ रेवेन्यू डैफिसिट की होती है। अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू डैफिसिट यदि हम किसी भी तरीके से शून्य पर लेकर आएं तो वह प्रदेश का सबसे अच्छा बजट माना जाता है। कांग्रेस के शासनकाल में रेवेन्यू डैफिसिट 8319.2 हजार करोड़ रुपये छोड़ा गया था, जो 1.88 प्रतिशत था। जिसे हमारी सरकार ने वर्ष 2015-16 में घटाकर 1.34 प्रतिशत किया था और अब उसे हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय ने घटाकर 1.1 प्रतिशत पर ला दिया है। यह बहुत ही अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय आने वाले बजट में इस रेवेन्यू डैफिसिट को घटाते-घटाते शून्य प्रतिशत पर ले आएंगे। अध्यक्ष महोदय, यदि हम फिस्कल डैफिसिट की बात करें तो हमारी सरकार जिस समय सत्ता में आई उस समय 2.8 प्रतिशत था और वर्ष 2015-16 में 2.58 प्रतिशत आया, अब यह 2.47 प्रतिशत पर आ गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से एक सुझाव है कि यदि हम फिस्कल डैफिसिट को बढ़ाएं और उसको कैपिटल एक्सपैंडीचर में निवेश करें तो यदि फिस्कल डैफिसिट यदि बढ़ भी जाये और रेवेन्यू एक्सपैंडीचर भी बढ़ जाये तो अच्छी बात है। उसमें हम पैसे को ऐसी जगह निवेश करेंगे जिससे हमारा रेवेन्यू रिसीट बढ़ेगा। उदाहरण के तौर पर हम कोई भी चीज लोन लेकर लेते हैं, लोन लेने के बाद हम अच्छी योजनाओं में निवेश करते हैं। अच्छी योजनाओं में निवेश करने के बाद जब हमारा रेवेन्यू रिसीट बढ़ता है तो उस रेवेन्यू रिसीट से फिस्कल डैफिसिट घटता है। इस तरह से यह एक अच्छे बजट की निशानी है। इस तरह की सारी चीजें को माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट में पेश किया है। अध्यक्ष महोदय, यदि हम इस बजट की डिटेल में जायेंगे तभी हमें अच्छे बजट का पता लगेगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सदन में कहा कि हरियाणा में आज जो बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर ऑलरेडी 56 हजार रुपये कर्ज है। हमारे पूर्व वित्त मंत्री की तरफ से बयान आया कि आज पैदा होने वाले हर बच्चे पर 70 हजार रुपये कर्ज है। मेरा विचार है कि बच्चे के कर्ज के साथ पैदा होने में कोई बुराई नहीं है। सोचने वाली बात

यह है कि क्या हम अपने बच्चों के लिए फिस्कल डैफिसिट या अन्य योजनाएं भी छोड़कर जाएंगे जिससे हमारे रेवेन्यू रिसीट्स और टैक्स बढ़ें। अगर ऐसा होगा तो आने वाला बच्चा इस कर्ज के बारे में सोचकर दुखी नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूँ कि रेवेन्यू रिसीट्स और टैक्स बढ़ाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि टैक्स ही बढ़ाए जाएं। अगर टैक्स देने वाले लोग बढ़ जाएं, चोरी रूक जाए और भ्रष्टाचार रूक जाए तो हमारे पास टैक्स और रेवेन्यू काफी बढ़ सकता है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सबसे पहला सुझाव रेवेन्यू रिसीट्स और टैक्स रिसीट्स बढ़ाने के बारे में है। गुड़गांव हरियाणा का ऐसा शहर है जो पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आई.टी. सैन्टर है। वहां जितनी भी कम्पनियां हैं उन सबके हैड आफिसिज दिल्ली में है। वे कम्पनियां कमाई तो हरियाणा में करती है परंतु टैक्स दिल्ली को पे करती है। हमें रूल्ज में कुछ ऐसा अमेंडमैंट करना चाहिए जिससे ये कम्पनियां हरियाणा को ही टैक्स पे करें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कुछ समय पहले हिसार में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी और उसके टैक्स से हिसार को बहुत फायदा होता था लेकिन पिछली सरकार ने उसको इतना तंग किया कि वह कम्पनी अपने हैड ऑफिस को छतीसगढ़ में ले गई। इसके हैड ऑफिस के हरियाणा के बाहर जाने से हमारे प्रदेश को ही नुकसान हुआ है। इसके टैक्स से हमें ही आमदनी होती थी। अत : इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जो कम्पनियां हरियाणा में स्थापित हैं उनके हैड ऑफिस भी हरियाणा में ही होने चाहिए। हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है। हरियाणा के 50 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। हरियाणा सरकार ने "हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इनवेस्टर्स सम्मिट" आयोजित किया जिससे हरियाणा में 5,84,000 करोड़ के एम.ओ.यूज. साइन हुए हैं। जब ये इनवेस्टमैंट्स धरातल पर आएंगे तो इससे हरियाणा को टैक्स रिसीट्स मिलेंगे उससे फिस्कल डैफिसिट घटेगा। अत : इससे हरियाणा को बड़ी अच्छी तरक्की की संभावना है। तीसरी बात, पिछली सरकारों ने सभी बजट सिर्फ रेवेन्यू एक्सपैंडीचर किये थे। उन्होंने कोई भी कैपिटल एक्सपैंडीचर बजट नहीं किया जिससे हमें इनकम हो सकती थी। तीसरा जो मेरा सुझाव है उस पर ऑलरेडी काम हो रहा है जोकि इंटरनैशनल एयरपोटर्स से संबंधित है। हिसार में इंटरनैशनल एयरपोर्ट बन रहा है और वह जितनी जल्दी बनकर तैयार होगा उतनी ही जल्दी हमारी इनकम शुरू हो जाएगी जिससे हमारी रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ेगी और फिसकल डैफिसिट घटेगा। अत : मेरी आदरणीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि इसके लिए उन्हें चाहे जितना भी फिसकल डैफिसिट बढ़ाना पड़े लेकिन यह काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। अभी हाल में हमारा फिसकल डैफिसिट 2.47 परसेंट है जिसे हम 3.25 परसेंट तक आराम से ले जा सकते हैं। अत : हम हिसार में जितना जल्दी इंटरनैशनल एयरपोर्ट बनाएंगे उतनी ही जल्दी हमारी इकॉनोमी इम्प्रूव होगी और हमारी आने वाली पीढ़ियां सरकार के गुण गाएंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे जो हवाई जहाज हैं उनकी मैंटीनैंस और ओवरहॉलिंग हिन्दुस्तान में नहीं होती। उनका यह सारा काम मुम्बई और सिंगापुर में होता है। हिसार में 4 हजार एकड़ जमीन पर जब एम.आर.ओ. एस्टैब्लिश होगा तो मैं समझता हूं कि इससे हमारी अर्थ नीति बहुत अच्छी होगी और हमारी इन्कम भी अच्छी होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि यह जो हमारी विधान सभा है इसकी भोगौलिक स्थिति भी लगभग हरियाणा जैसी है। हम एक तरफ के विंग को नोर्दन विंग कह सकते हैं, दूसरी तरफ के विंग को साउदर्न विंग तथा इस तरफ वैस्टर्न विंग, यानि ये तीन पोर्शन हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप

[डॉ कमल गुप्ता]

दिल्ली, यानि सैंटर में बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर हम स्थिति का विश्लेषण करें तो वैस्टर्न हरियाणा में बहुत सारा स्पेस इम्प्रूव होने का है। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बात तो इंटरनैशनल एयरपोर्ट की रखी तथा दूसरा मैं वित्त मंत्री महोदय से रिक्वैस्ट करता हूं कि एक इंटरनैशनल क्रिकेट ग्राउंड का भी यहां प्रावधान किया जाए। वैस्टर्न हरियाणा में यदि इंटरनैशनल क्रिकेट गाउंड बन जाएगा और एक भी टैस्ट मैच यदि हरियाणा में हो जाएगा तो उससे अनेक प्रकार की आमदनी हरियाणा में होगी और हमारी ग्रोस रिसीट्स बढ़ेंगी। मैं समझता हूं कि इससे हमारी अर्थ नीति भी बढ़िया हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को एक और सुझाव देना चाहता हूं और वित्त मंत्री जी मेरे उस सुझाव से जल्दी ही सहमत हो जाएंगे। राखीगढ़ी में हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी खोज हुई है इसलिए मैं प्रपोज करता हूं कि वहां विश्वस्तरीय पर्यटक स्थल डिवैल्प किया जाए। इससे भी हमारी रिवैन्यू रिसीट्स और टैक्स रिसीट्स बढ़ेंगी। अग्रोहा को अग्रोहा धाम कहा जाता है और यदि इसकी और ज्यादा डिवैल्पमैंट करेंगे तो यहां समाज के अमीर लोग बहुत ज्यादा आकर्षित होंगे ओर हरियाणा को बहुत ज्यादा फायदा होगा। हरियाणा में खासकर वैस्टर्न हरियाणा में तो टूरिज्म का ज्यादा बोल बाला नहीं है इसलिए राखीगढ़ी और अग्रोहा को अगर अच्छी तरह से डिवैल्प करेंगें तो हरियाणा को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वित्त मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 350 करोड़ रुपये का प्रावधान रोहतक, महम और हांसी की रेलवे लाइन के लिए रखा है। वह रेलवे लाइन जुड़ेगी तो जो वैस्टर्न हरियाणा और हिसार हैं इसकी कनैक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। किसी एरिया की डिवैल्पमैंट के लिए यदि कनैक्टिविटी अच्छी होती है तो उसकी अनेक तरह की डिवैल्पमैंट होती है और अनेक तरह के होटल और दूसरी चीजें वहां आ जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, हिसार में तीन यूनीवर्सिटीज हैं। पिछले काल में तीनों यूनीवर्सिटीज का जो स्टेटस रहा है वह लगभग एक स्कूल का रहा है। मेरी मुख्यमंत्री महोदय जी से और वित्त मंत्री महोदय जी से यह प्रार्थना है कि उन तीनों में से कम से कम एक यूनीवर्सिटी को इंटरनैशनल लैवल तक ले जाया जाए और उसमें कम से कम 10 हजार स्टूडैंट्स हों। यूनीवर्सिटी का स्टेटस बढ़ेगा तो शहर का कद बढ़ेगा और हरियाणा का कद बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे बिजली विभाग का 35 हजार करोड़ रुपये का जो घाटा था उस पर हम साढ़े 12 परसैंट इंट्रस्ट दे रहे थे। यह हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी की बहुत अच्छी सोच है कि एक ऋण बेटे पर हो और उसे पिता ले ले क्योंकि पिता के नाम से इंट्रस्ट कम पड़ता है तो इसे लेने में कोई बुरी बात नहीं है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री महोदय जी का भी धन्यवाद करता हूं। 'उदय' स्कीम के तहत बिजली विभाग का 35 हजार में से 25 हजार रुपये का ऋण हरियाणा सरकार ने अपने ऊपर लिया है जोकि बहुत अच्छी बात है। इससे हमारा फॉल्स फिसीकल डैफीसिट तो बढ़ा है लेकिन उसके बावजूद भी यह अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री ने इण्डिया में और इण्डिया में भी हरियाणा में और हरियाणा में भी जिला गुड़गांव में इंटरनैशनल सोलर एलायंस के हैड आफिस का उदघाटन किया था। इंटरनैशनल सोलर एलायंस में 122 देशों की भागीदारी है। प्रत्येक घर में छोटे-छोटे यूनिट लगाये जायें और सोर उर्जा से बिजली का उत्पादन करके स्टोर करें। ऐसा करके लोग अपने घर में भी बिजली यूज करें और जो सरप्लस बिजली हो उसको सरकार को दे दें। ऐसा करने से बिजली की कमी भी दूर होगी और लोगों की आमदनी भी होगी। इस तरह से छोटे-छोटे लघू उद्योग लग जायेंगे। अपनी

बात को कंक्लूड करते हुए मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि जी.डी.पी. को बढ़ाया जाये, कैपीटल इनवैस्टमैंट की जाए और टैक्स रैवेन्यू भी इस माध्यम से बढ़ाया जाये। इसके साथ-साथ सेवा के जो काम हैं चाहे स्वास्थ्य के, शिक्षा के, चाहे गरीबों के लिए हैं, चाहे एफोर्डेबल हाऊसिज की बात है, चाहे अंत्योदय की बात हो। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पण्डित दीनदयाल जी का जीवन संस्कृति अंत्योदय थी। जो हमारे समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हैं उनका पालन पोषण करना सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार को करना भी चाहिए। इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी जो अर्थ व्यवस्था है उसको आश्रित नहीं होना चाहिए। अंत में मैं राम राज की कल्पना में तुलसीदास जी ने जो चौपाई कही थी वह कहकर अपनी बात को विराम दूंगा-

नहि दरिद्र कोई, दुखी न हीना, नहि कोई अबुध, न लच्छन हीना।

इसका अर्थ है राम राज में कोई भी गरीब नहीं और न कोई दुखी है। न कोई अशिक्षित और न ही कोई ऐसा जैसा कि कुछ समय पहले कुछ उपद्रवियों ने जाट आरक्षण की आड़ में जो यह लक्षणहीन लोग थे जिन्होंने लक्षणहीन काम किए इस तरह के आदमी भी राम राज में नहीं होने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका दोबारा से धन्यवाद करता हूं।

श्री तेजपाल तंवर(सोहना) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। जो बजट माननीय वित्तमंत्री जी ने पेश किया है ऐसा बजट हरियाणा बनने के बाद से आज तक प्रस्तुत नहीं किया गया। हरियाणा को बने हुए 50वां साल है और इस 50 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इससे पहले बहुत सी सरकारें प्रदेश में रही लेकिन उन्होंने ठीक तरह से प्रदेश में काम नहीं किए। हरियाणा प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश है अगर पिछली सरकारों ने यहां पर थोड़े-थोड़े काम भी किए होते तो आज प्रदेश की हालत यह नहीं होती। माननीय वित्तमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं हुई है। जितनी भी योजनाएं बजट में हैं उनके लिए सुरक्षित पैसे का प्रावधान किया गया है और सभी वर्गों को उसमें छूआ गया है। आप चाहे शिक्षा के क्षेत्र को देख लें, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र को देख लें हर क्षेत्र के लिए बजट में पैसे का प्रोपर प्रावधान किया गया है। हमारे विपक्ष के साथियों की सरकार भी प्रदेश में रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार भी प्रदेश में रही है। कांग्रेस के साथी सदन में नहीं आ रहे। इनेलो की सरकार में हम भी शामिल रहे हैं लेकिन उनकी सरकार के समय में प्रदेश में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। उस समय न के बराबर काम हुए। कांग्रेस के समय में तो ऐसा था कि आंधा बांटे खीरनी, घर-घर के ही खांयें। कांग्रेस राज में तो जो पैसा प्रदेश में लगना था उसमें से 50 प्रतिशत पैसा तो सरकार के लोग ही ले लेते थे और जो पैसा बचता था वह भी वे अपने क्षेत्र में ही लगाते थे। उस समय हमारे प्रदेश की ऐसी हालत रही थी। पिछले 50 वर्षों के शासन के दौरान हरियाणा प्रदेश में सत्तासीन रही सरकारों ने जो गलत काम किये और प्रदेश के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सबको ठीक करते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। चाहे पानी का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो और चाहे खेलों का क्षेत्र हो उन सभी में विशेष कार्य करवाये जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में सड़कों की पिछले 10 सालों के दौरान क्या हालत थी यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। नई सड़कें तो बनाना दूर की बात कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी मुख्य सड़कों और महत्वपूर्ण लिंक रोड़्ज़ पर पैच

[श्री तेजपाल तंवर]

वर्क भी नहीं करवाया था। हरियाणा प्रदेश की सड़कों की कांग्रेस सरकार के समय में क्या हालत थी इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जो दूरी एक घंटे में तय की जा सकती थी उसको तय करने में 6-6 घंटे का समय लगता था। उस सफर को लोग तत्कालीन सरकार के नुमाइंदों को कोसते हुए पूरा करते थे। जब से हमारी सरकार आई है चाहे हम प्रदेश के किसी भी कोने में चले जायें हरियाणा प्रदेश की सभी प्रमुख सड़कें और सभी लिंक रोड्ज़ की इतनी अच्छी स्थिति है कि लोग चारों तरफ वाहवाही कर रहे हैं। अगर कोई सड़क थोड़ी बहुत भी खराब है उसके बारे में भी हमारे विधायक भाई लिखकर दे रहे हैं जिसको तुरंत ठीक करवाया जा रहा है। हमारी सरकार वह कार्य हरियाणा प्रदेश में कर रही है जैसे पहले कभी किसी भी सरकार ने नहीं किये थे। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश में जो अस्पताल मृत प्राय : हो चुके थे उनका जीर्णोद्धार किया गया है। पहले प्रदेश के अधिकतर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों का अकाल पड़ा हुआ था और मरीज़ों को अपनी किसी छोटी सी बिमारी की दवाई लेने के लिए भी 6-6 घंटे इंतज़ार करना पड़ता था। हमारी सरकार द्वारा गम्भीर प्रयास करके नई भर्तियां करके प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा रहा है। इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार द्वारा अच्छे काम किये जा रहे हैं और जो पिछली सरकारों ने हरियाणा प्रदेश में सरकारी स्कूली शिक्षा का बेड़ा गर्क करने का काम किया गया था उसमें भी तीव्रता के साथ सुधार किया जा रहा है। हमारे प्रदेश में पिछले कुछ समय में शिक्षा का स्तर इतना गिर गया था कि लोग जाली डिग्रियां लेने लगे थे। हमारी सरकार के प्रयासों से हरियाणा प्रदेश में शिक्षा के स्तर में हर रोज़ नये आयाम स्थापित किये जा रहे हैं। नवयुवकों व नवयुवतियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए नित नई योजनओं को बनाकर अमलीजामा पहनाया जा रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए एक बेहतर बजट वर्ष 2016-17 के लिए लेकर आई है। इस बजट में प्रदेश के सभी वर्गों का विशेष रूप से ख्याल रखा गया है। इस बजट से हमारी सरकार के "सबका साथ, सबका विकास" नारे को अभूतपूर्व गति मिलेगी। हमारी सरकार का यह बजट रोजगारोन्मुख और प्रदेश की स्वास्थ्य व शिक्षा सेवाओं के साथ सभी सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली में पूर्ण सुधार करने वाला बजट है। ऐसे ही हमारी सरकार के प्रयासों से प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा गुड़गांव में एक सौर उर्जा प्लांट की स्थापना की गई है। यह अपने आप में ऐतिहासिक काम है जो कि हरियाणा में पहली बार हुआ है। सौर उर्जा के इस प्लांट को देश के बहुत से प्रदेश अपने यहां लगवाने के लिए प्रयासरत थे लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्य के लिए हमारे हरियाणा प्रदेश के गुडगांव शहर को ही चुना। (विघ्न)

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, हमारे देश में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने गुड़गांव से देश में सौर उर्जा के लिए आह्वान किया है उनके इस आह्वान में अपना योगदान देते हुए हरियाणा सरकार ने पानीपत थर्मल प्लांट में 10 मेगावाट के सौर उर्जा प्लांट की स्थापना के लिए काम शुरू कर दिया है और हमें उम्मीद है कि इस सौर उर्जा प्लांट को जल्दी ही फंक्शनल बना दिया जायेगा।

श्री तेज पाल तंवर : माननीय स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि अगर माननीय मंत्री जी को सदन को कुछ जानकारी देनी है तो वह उसे मेरे बैठने

के बाद दे दें इस तरह मुझे डिस्टर्ब न करें। मैं यह कह रहा था कि हैपनिंग हरियाणा इंवैस्टर मीट का आयोजन भी हमारे गुड़गांव में हुआ। इसके बारे में विपक्ष के माननीय नेता यह कह रहे थे कि हैपनिंग हरियाणा इंवैस्टर मीट का आयोजन तो ज़रूर हुआ लेकिन इससे हरियाणा में आया क्या? मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हम अपने यहां पर निवेश को इनवाईट नहीं करेंगे तो फिर अपने आप कौन हमारे हरियाणा प्रदेश में निवेश करने के लिए आयेगा। ऐसा करके हमारी सरकार ने एक कोशिश की है। यह बात मैं भी मानता हूं कि ऐसा हो सकता है कि हमारी सरकार की यह कोशिश 100 प्रतिशत कामयाब न हो पाये लेकिन हमारी सरकार की यह कोशिश कम से कम 70 प्रतिशत तो कामयाब होगी ही होगी इसकी हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है। हमारी सरकार का यह प्रयास रंग लाने लगा है और हमारे हरियाणा प्रदेश में उद्योगपतियों द्वारा अपने उद्योग लगाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। पिछले दिनों हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खेलों के एक फंक्शन में गुड़गांव में गये थे वहां पर एक उद्योगपति ने माननीय मुख्यमंत्री जी से उद्योग लगाने के लिए हरियाणा में 2000 एकड़ ज़मीन देने के बारे में मांग की थी। जब इस प्रकार के उद्योग हरियाणा प्रदेश में लगेंगे तो उनमें प्रदेश के बेरोजगार वर्ग को काम मिलेगा और प्रदेश की तरक्की के द्वारा खुलेंगे। उद्योग लगने से स्थानीय जनता जैसे रेहड़ी वाले को, दुकानदार को और मकान किराये पर देने वाले सभी लोगों का फायदा होगा। यह हमारी सरकार की क्रांतिकारी नीतियों का ही परिणाम है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में एतिहासिक विकास कार्य तीव्रता के साथ चल रहे हैं। हमारी सरकार काम कर रही है लेकिन विपक्ष के माननीय साथी हमारी सरकार के किसी भी काम की प्रशंसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। विपक्ष का तो यह हाल है कि अगर हमारी सरकार सोने की सड़क भी बना दे तो वे फिर भी उसे लोहे की ही बतायेंगे। लोकतंत्र में किसी भी विपक्ष को ऐसी संकुचित सोच का मालिक नहीं होना चाहिए। उसको सरकार के अच्छे कार्यों की दिल से प्रशंसा करनी चाहिए और अगर आलोचना करना ज़रूरी भी हो तो सकारात्मक रवैया अपनाकर सरकार की आलोचना करना भी बुरी बात नहीं है लेकिन अगर हम सिर्फ आलोचना करने के लिए ही आलोचना करेंगे तो वह किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। इसीलिए मैं यह बात कहना चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार प्रदेश की व्यापक हित के दृष्टिगत कोई विशेष कार्य करती है तो समूचे विपक्ष को उसमें ईमानदारी के साथ सहयोग करना चाहिए। हमारी पार्टी भी विपक्ष में थी और हम कभी सरकार में इंडियन नैशनल लोकदल के सहयोगी भी रहे हैं। उस समय हमने ईमानदारी के साथ अपनी भूमिका को बखूबी निभाया था। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सरकार के अच्छे कामों की उनको भी दिल खोलकर सराहना करनी चाहिए। अगर ऐसे ही आपसी खींचतान में लगे रहे तो हमारा प्रदेश विकास की दौड़ में बड़ी बुरी तरह से पिछड़ जायेगा। जिस पहलवान ने इस बार के ईनामी दंगल में एक करोड़ रुपये की राशि जीती है अगर हम उसको शाबाशी नहीं देंगे तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं विपक्ष से भी कहना चाहता हूं प्रतिपक्ष के माननीय नेता हमारे साथी हैं और उनका बहुत लम्बा राजनीतिक अनुभव रहा है। उनको भारतीय जनता पार्टी की जो बिना किसी भी प्रकार के भेदभाव वाली कार्यशैली है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हरियाणा प्रदेश की उन्नति के काम में हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। अगर कहीं पर कोई कमी उनके ध्यान में आती है तो उसको उन्हें सरकार के ध्यान में लाना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर वे ऐसा करेंगे तो हरियाणा सरकार द्वारा उसका सही तरीके से निराकरण किया जायेगा। जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है इसमें हरियाणा को देश के दूसरे सभी राज्यों से विकास की दौड़ में सबसे आगे निकालने का पूरा दम-खम है। उन्होंने अपने बजट में सभी विभागों के लिए

[श्री तेजपाल तंवर]

विशेष रूप से बजट का आबंटन किया है। अभी कुछ सदस्य कह रहे थे कि बजट बहुत कम दिया गया है मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इस बार बजट में अधिक धन का प्रावधान किया गया है। आज आप गांवों में जा कर देखिये कि कितने जोरशोर से विकास के कार्य हो रहे हैं। इसी प्रकार से सड़कों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जिन सड़कों पर कभी कार्य नहीं हुआ था आज उन सड़कों को बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से जिन गांवों में पीने का पानी नहीं था और जहाँ पिछले 10 साल से एक भी ट्यूबवैल नहीं लगा था आज वहाँ पर 10-10 ट्यूबवैल लगाये जा रहे हैं ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की कुछ समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मोहम्मदपुर अहीर गांव में एन.डी.ए. के शासनकाल में एक हॉस्पीटल बनना शुरू हुआ था लेकिन कुछ समय बाद से ही उसका काम रूका हुआ है इसलिए उसका निर्माण शीघ्र शुरू करवा जाये। इसी प्रकार से तावडू क्षेत्र में जहाँ लगभग 70-80 गांव लगते हैं और उनमें एक ही छोटा सा हॉस्पीटल है और उसकी हालत बहुत खराब है इसलिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे हॉस्पीटल्स को जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाये ताकि लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से तावडू क्षेत्र में एक भी महिला कॉलेज नहीं है इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ पर एक महिला कॉलेज का निर्माण करवाया जाये ताकि लड़कियों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। हमारे एक स्कूल में तो 5000 लड़कियाँ हैं जिनके बैठने के लिए भी जगह नहीं है इसलिए उनके लिए भी कुछ अतिरिक्त कमरों की व्यवस्था की जाये। हमारे क्षेत्र में बिजली की बड़ी भारी दिक्कत है। हमारे क्षेत्र में पचगावां में एक 33 के.वी.ए. का सब-स्टेशन बनना है जो कि काफी समय से लम्बित पड़ा है इसलिए उसको यथाशीघ्र बनवाया जाये। इसी तरह से बिजली की तारें जो बहुत समय से बदली नहीं गई हैं और वे पुरानी तारें टूट-टूट कर गिर रही हैं, सरकार ने इस काम के लिए बजट में भी प्रावधान किया है लेकिन मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र किया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री ज्ञान चन्द गुप्ता चेयर पर आसीन हुये।)

सरदार बख्शीश सिंह विर्क (असन्ध) : सभापति महोदय, वर्ष 2016-17 के लिए जो बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। इस बजट की सभी सदस्यों ने और नेता प्रतिपक्ष ने भी सराहना की है कि यह बजट आम आदमी के लिए अच्छा बजट है जिसमें किसानों, मजदूरों, दुकानदारों और व्यापारियों को बहुत फायदा होगा। इसके साथ-साथ मैं वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री जी का भी इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी सलाह ले कर एक बहुत अच्छा बजट पेश किया है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि 1966 में हरियाणा बनने के बाद हिन्द की चादर गुरू गोविन्द सिंह जिन्होंने देश पर अपना पूरा वंश वार दिया उनकी जयन्ती के अवसर पर कभी भी अवकाश की घोषणा नहीं की गई लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने गुरू गोविन्द सिह के प्रकाशोत्सव पर 16 तारीख को अवकाश की घोषणा की थी जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इससे हमारे समाज में एक भाईचारे का अच्छा संदेश जायेगा। सभापति महोदय, इसी प्रकार से एक-दो बात मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की भी करना चाहता हूँ। एक बात मैंने पिछली बार भी सदन में उठाई थी और अब फिर कह रहा हूँ

कि असंध के सरकारी अस्पताल में एक्स-रे मशीन नहीं है और न ही वहाँ पर कोई सर्जन है। अगर वहाँ पर किसी को एक्स-रे करवाना पड़ जाये तो हमें सीधा करनाल जाना पड़ता है जो कि वहाँ से 46-47 किलोमीटर दूर है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि असंध के सरकारी अस्पताल में एक्स-रे मशीन लगवाई जाये तथा वहाँ पर एक सर्जन का इंतजाम भी किया जाये। अभी 6-7 महीने पहले एक प्रस्ताव आया था कि हरियाणा के जिस गांव में 250 एकड़ जमीन उपलब्ध होगी वहाँ पर होर्टीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई जायेगी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि असंध विधान सभा क्षेत्र में मुनक गांव इन सभी नॉर्म्स को पूरा करता है। वहाँ पर नहर का पानी भी है और जमीन भी सड़क के साथ है और वह सड़क दो जिलों के साथ लगती है क्योंकि इसराना इलाका, हमारा असंध इलाका व पानीपत का ग्रामीण एरिया है वह भी उसके साथ लगता है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मुनक गांव में 250 एकड़ जमीन जो पहले लेने की बात की गई थी और उस जमीन पर जो यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई थी इसलिए मैं कृषि मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह यूनिवर्सिटी वहीं पर बननी चाहिए। वह किसी दूसरी जगह नहीं जानी चाहिए क्योंकि उससे हमारे दो जिलों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता केवल एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है और वैसे भी मैं ज्यादा नहीं बोलता फिर भी स्पीकर साहब ने कल भी मुझे बोलने का समय नहीं दिया और परसों भी नहीं दिया। मेरी यह मंशा थी कि श्री ज्ञान चन्द गुप्ता जी स्पीकर की कुर्सी पर बैठेंगे तभी मुझे समय देंगे तो उन्होंने कुर्सी पर बैठते ही मुझे बोलने का समय दिया है इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और विशेष तौर से मैं बजट के लिए आपका बहुत-बहुत शुकराना करता हूं। विशेष तौर से वित मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने सभी विभागों के लिए इतना अच्छा बजट पेश किया है, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे वह शिक्षा विभाग हो, चाहे वह हैल्थ विभाग हो, चाहे वह सड़कों का विभाग हो, चाहे वह सिंचाई विभाग हो, चाहे वह एस.सी.,बी.सी., का कोई भी विभाग हो, इन सभी विभागों में हमें फायदा मिला है और जो पिछले साल का बजट था इस साल उससे भी बढ़िया बजट पेश किया गया है। इसके लिए मैं इस बजट की सराहना करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूं कि अगली बार जो बजट आएगा वह इससे भी बढ़िया आएगा। जिसका हमारे प्रदेश की अढ़ाई करोड़ जनता को इस बात का फायदा मिलेगा। आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री नसीम अहमद (फिरोजपुर झिरका) : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। जैसा कि जब माननीय वित मंत्री जी ने बजट पेश किया तो प्रदेश की जनता को और यहां बैठे सभी विधायकों को एक फिक्र और चिन्ता होती है कि आज पूरे प्रदेश का लेखा जोखा पेश होगा। नई-नई स्कीमों के लिए बजट कितना दिया गया है उसके बारे में बताया जाएगा और प्रदेश किस तरह से तरक्की पर आगे बढ़े उन सारी स्कीमों का खाका तैयार करके पेश किया जाएगा। सभापति महोदय जब यह बजट पेश हुआ तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि यह पिछले साल का बजट है। इसमें कोई नई चीजें दिखाई नहीं देती। आज जिस तरीके के प्रदेश के हालात हैं उसके हिसाब से खर्चा तो बढ़ा दिया लेकिन जो नई स्कीमें हैं वह कोई लागू नहीं की बल्कि जो पिछले साल की योजनाएं थी केवल उन्हीं को ही बजट में दर्शाया गया है। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तो उससे पहले जो चुनाव घोषणा पत्र था

[श्री नसीम अहमद]

उसमें बी.जे.पी. द्वारा करीब 150 घोषणाएं की गई थी लेकिन इस बजट में उनमें से एक भी घोषणा को लागू करने का जिक्र नहीं किया गया और ज्यादातर घोषणाएं अभी ज्यों की त्यों पड़ी हैं। सभापति महोदय, आज प्रदेश के हालात इतने खराब हैं कि वर्ष 2015-16 के बजट में जो 32 घोषणाएं की गई थी उनमें से भी 14 घोषणाएं अन कम्पलिट पड़ी हैं। मेरा अनुरोध है कि उन पिछली घोषणाओं को भी पूरा किया जाए और आगे के लिए जो घोषणाएं की गई हैं उनको भी पूरा किया जाए। मैं यह बताना चाहता हूं कि जो पिछली घोषणाएं थी वह ज्यादातर कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई थी जिसमें अटल खेती बाड़ी योजना, प्रधान मंत्री कृषि योजना, डिजिटल रजिस्ट्रेशन कार्ड योजना, गेंहू, धान चक्र फसली योजना आदि थी जो किसान के लिए बढ़िया योजना थी और जिसकी हमने पिछले साल सराहना भी की थी लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से उन योजनाओं की कोई रूप रेखा तैयार नहीं की गई है कि इनको कैसे लागू किया जाएगा। सभापति महोदय, जब बजट पेश किया जाता है जो हमने कांग्रेस पार्टी के राज में भी देखा था कि टैक्स फ्री बजट लेकिन बजट सैशन खत्म होते ही टैक्सों की भरमार लगा दी जाती थी कभी वैट के नाम पर बढ़ा दिया जाता है, कभी पैट्रोल-डीजल के नाम पर उसमें बढ़ोतरी कर दी जाती है। सभापति महोदय, इसके बारे में वित्त मंत्री जी और सरकार को सोचना चाहिए कि जब टैक्स फ्री बजट की घोषणा की जाती है तो फिर उस बजट को टैक्स फ्री ही रहने देना चाहिए। पूरे साल बजट में कोई नया टैक्स नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अगर जोड़ा जाता है तो बजट में इस तरह की घोषणा कदापि नहीं की जानी चाहिए कि यह बजट पूरी तरह से टैक्स फ्री रहेगा। सभापति महोदय, प्रदेश के कुल राजस्व का लगभग 44 प्रतिशत वेतन और पैंशन पर खर्च होता है। 17 प्रतिशत ब्याज चुकाने में चला जाता है। इसके अतिरिक्त हम कर्ज के रूप में पैसा लेते हैं, इसको चाहे और बढ़ा दिया जाये लेकिन किसी भी क्षेत्र को पिछड़ा नहीं रहने देना चाहिए। मैं मेवात क्षेत्र से संबंध रखता हूँ। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में मौजूद नहीं हैं, जब उनके लिए पाकिस्तानी शब्द का प्रयोग किया गया था तो उनकी आंखों से आंसू छलक आये थे। सभापति जी, आप अंदाजा लगाईये उस व्यक्ति के बारे में जिसको चोट लगती है, उसको कितनी पीड़ा या दुख होता होगा। उसी तरह आप यह भी सोचिए कि जब बार-बार हमारे मेवात क्षेत्र के लिए पिछड़ा शब्द का प्रयोग होता होगा तो हमें कितनी पीड़ा होती होगी। सभापति महोदय, क्या इस पिछड़ेपन शब्द को हम मेवात के लोग जिन्दगीभर ढ़ोते रहेंगे। क्या पिछड़ेपन का जो धब्बा और दाग लगा हुआ है इसके लिए मेवातियों का कोई कसूर है। क्या सरकार को यह जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए कि जो मेवात में पिछड़ापन है उसको दूर किया जाए। मेवात क्षेत्र का यह पिछड़ापन सरकार की नाकामियों और सरकार की बेकायदगियों की वजह से है। अगर मेवात क्षेत्र से पिछड़ापन का धब्बा हटाना है तो नि :संदेह सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। मेवात में वर्ष 1980 और वर्ष 1982 में मेवात डिवेलपमैंट बोर्ड का गठन यह सोचकर किया गया था कि मेवात और क्षेत्रों से पिछड़ा हुआ है अत : इस तरह का बोर्ड बनाकर इस क्षेत्र को पिछड़ेपन से मुक्ति दिलाई जाए। मेवात की इतनी दयनीय हालत तो जब है जबकि यह दिल्ली से महज 60 किलोमीटर दूर है, जयपुर से केवल 150 किलोमीटर दूर है और आगरा से केवल 150 किलोमीटर दूर है। (विघ्न)

श्री तेजपाल तंवर : सभापति जी, मेवात क्षेत्र के नल्हड़ में जो हॉस्पिटल बना है वहां पर बहुत ज्यादा घोटाले हुए हैं उनकी जांच कराई जाये।

श्री नसीम अहमद : सभापति जी, तेजपाल जी ठीक कह रहे हैं नल्हड़ के हॉस्पिटल को बनाने में बहुत बड़े घोटाले हुए हैं, उसकी भी जांच करानी बहुत आवश्यक है। यही नहीं मेवात डिवेलपमैंट बोर्ड में भी बहुत बड़े घोटाले हुए है। इन सबकी जांच करानी बहुत आवश्यक है। सभापति महोदय, जब वर्ष 2014 का चुनाव चल रहा था तो उस वक्त प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई थी। उस वक्त कांग्रेस राज में पिछले द्वार से, कांग्रेस के आर्शीवाद प्राप्त अफसरों व कांग्रेस के लोगों ने मिलीभगत करके मेवात डिवेलपमैंट बोर्ड में भर्तिया की थी। यह भर्तिया सरासर इलीगल थी। इसके बारे में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की थी। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हम इन सबकी इंक्वॉयरी करवायेंगे। इस बात को हुए लगभग डेढ़ साल के करीब हो गये है लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ नहीं किया गया है। क्या यह तो नहीं होगा कि सरकार का कार्यकाल पूरा हो जायेगा और इंक्वॉयरी पैंडिंग ही पड़ी रहेंगी। कहीं ऐसा तो नहीं जिस लाईन पर कांग्रेस चला करती थी उसी लाईन पर भारतीय जनता पार्टी चलने लग गई है। कांग्रेस सरकार हमेशा पाईप लाईन में पानी छोड़कर आगे का रास्ता बंद करने वाली नीति पर काम किया करती थी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उसी रास्ते पर चलने लग जायेगी तो फिर यह प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य साबित होगा। सभापति जी, मेवात क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत कमी है। यहां पर पीने के पानी की इतनी विकराल समस्या है कि आज भी हमारी बहन-बेटियां दो-तीन किलोमीटर पैदल चलकर सिर पर मटकियां रखकर पानी लाती हैं। आज यहां पर होदियां खोदकर टैंकर बनाये जाते हैं और दूसरे-तीसरे दिन टैंकरों के माध्यम से पानी मंगवाया जाता है। एक टैंकर की कीमत 1500 से 2000 रुपये या इससे उपर तक की होती है। इस पानी को होदी में स्टोर कर लिया जाता है और फिर तीन-चार दिन तक इस्तेमाल किया जाता है। मेवात जिला अभी पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर ही अटका हुआ है और जहां तक रेल की बात है यह तो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत दूर की बात है। सरकार को सर्वप्रथम तो मेवात क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। अभी पिछले दिनों हॉस्पिटल में डॉक्टर्ज की इतनी बेकायदगी रही कि एक महिला की प्रसव पीड़ा के दौरान ही मृत्यु हो गई। मेवात का क्षेत्र दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है उसके बावजूद भी यह क्षेत्र रेल सेवा से वंचित है। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की कांगेस सरकार के समय घोषणा की गई थी कि मेवात क्षेत्र के लिए गुड़गांव से सोहना, फिरोजपुर तथा अलवर के लिए रेल सेवा शुरू की जायेगी लेकिन उसके लिए न तो कोई सर्वे हुआ है और न ही बजट में कोई प्रावधान रखा गया है न ही उसके लिए कोई स्कीम बनाई गई है। कांगेस सरकार ने महज घोषणा करके मेवात के लोगों के साथ छलावा किया है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उसी तरह के छलावे में शामिल होना चाहती है या फिर मेवात क्षेत्र का विकास करना चाहती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार मेवात क्षेत्र के लिए कब तक रेल सेवा शुरू करवा पायेगी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2007 में नूंह से गुड़गांव तक एक हाइवे निकला था उसे राष्ट्रीय राजमार्ग 248-ए का दर्जा दिया गया था। उसको गुड़गाव से मुंडका बॉर्डर तक चार लेन करने के लिए मंजूरी मिली थी और उसके लिए बजट भी अलॉट हो चुका था। वर्ष 2007 में इस हाइवे का उद्घाटन उस समय के माननीय केन्द्रीय परिवहन मंत्री और चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा करने आए थे और उन्होंने उसे नूंह तक के लिए ही मंजूरी दी थी। सभापति महोदय, नूंह से आगे इसलिए कह कर रोक दिया गया था क्योंकि इस हाइवे पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता इसलिए इसे चार लेन नहीं बनाया जायेगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को एक जानकारी

[श्री नसीम अहमद]

देना चाहता हूँ कि मेवात जिले में ट्रैफिक के कारण जनवरी से लेकर मार्च, 2016 तक लगभग 137 दुर्घटनाएं हुई हैं। इनमें से 124 लोग घायल हुए और इनमें से 60 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है।

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नसीम जी, आप कौन से जिले की बात सदन में बता रहे हैं ?

श्री नसीम अहमद : सभापति महोदय, मैं मेवात जिले की बात बता रहा हूँ। चार लेन पर भी दुर्घटना हुई थी, खासकर नूंह से फिरोजपुर झिरका के बीच दुर्घटना हुई थी। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी को मेवात हल्के से काफी लगाव है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से नम्र अनुरोध करता हूँ कि इस हाइवे को तुरंत चार लेन किया जाये।

श्री नरबीर सिंह : सभापति महोदय, पहले ही हमने माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी से मीटिंग करके इसकी डिटेल प्रोजैक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.) बनाई है जो तकरीबन तैयार हो गई है। सभापति महोदय, यह राष्ट्रीय राजमार्ग है, सरकार की कोशिश है कि मुंडका बॉर्डर तक इस साल चार लेन का काम शुरू हो जायेगा। इसकी डी.पी.आर. के लिए 60 लाख रुपये भी दे दिए गए हैं।

श्री नसीम अहमद : सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन में एक बात और बताना चाहता हूँ कि फिरोजपुर झिरका-बिवान सड़क को दो लेन बनाने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी जिक्र किया गया है, लेकिन अभी तक इस सड़क को बनाने के लिए ना तो टैंडर हुआ है और ना ही उसको बनाने की कोई योजना है। सभापति महोदय, यह सड़क राजस्थान से जुड़ी हुई है।

श्री नरबीर सिंह : सभापति महोदय, यह सड़क बी.ओ.टी. स्कीम के तहत दी जा चुकी है, जो फाईनल स्टेज पर है। सभापति महोदय, हम इस सड़क को पूरी तरह से कंक्रीट की बनाने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि यह काम 15 अप्रैल, 2016 तक शुरू हो जायेगा।

श्री नसीम अहमद : सभापति महोदय, इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ और जिस दिन यह सड़क बन जायेगी मैं माननीय मंत्री महोदय का स्वागत भी करूँगा। (विघ्न) सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण सड़क जिसके बारे में माननीय मंत्री जी को पता है कि नगीना से तिजारा तक जो मेवात जिले से जुड़ी हुई है उसे भी क्या मंत्री जी बनवाने की कृपा करेंगे?

श्री नरबीर सिंह : सभापति महोदय, मैं मंत्री बनते ही मेवात गया था और घोषणा करके भी आया था। तिजारा में हमारे जैन भाइयों का बड़ा तीर्थ स्थल है। तिजारा जाने के लिए हमें लगभग 45 किलोमीटर घुमकर नगीना से आना पड़ता है। सभापति महोदय, यदि एक सीधी सड़क बन जाये तो 15-16 किलोमीटर की दूरी पर ही तिजारा आ जायेगा। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा अपने शासनकाल में मेवात जाकर तीन बार घोषणा करके आए थे। सभापति महोदय, मैंने माननीय केन्द्रीय परिवहन और हाइवे मंत्री श्री नितिन गडकरी से कहा है कि यह सड़क धार्मिक स्थल से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी बनवाया जायें। सभापति महोदय, यह दो राज्यों की

कनेक्टिविटी का मामला है, केवल हरियाणा का नहीं है। हरियाणा में तो सिर्फ सात एकड़ जमीन एक्वायर हो रही है। सरकार जमीन एक्वायर नहीं कर रही है बल्कि वहां के लोगों से कह रही है कि आप लोग मार्किट रेट पर जमीन दे दें, हम हरियाणा के अन्दर सड़क बना देंगे। राजस्थान सरकार ने सड़क बनाने के लिए अपनी सहमति दे दी है। सभापति महोदय, मुझे उम्मीद है कि यह सड़क वर्ष 2016-17 में बनकर तैयार हो जाएगी।

श्री नसीम अहमद : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहता हूँ कि यदि यह सड़क बन जाये तो मेवात, अलवर, आगरा रोड़, जयपुर रोड़ इससे बिल्कुल कनैक्ट हो जायेंगे जिससे लोगों को व्यापार करने में और आने-जाने में बहुत सहूलियतें हो जायेंगी। इसके अतिरिक्त मैं स्वास्थ्य के बारे में भी बोलना चाहूंगा। (विघ्न)

श्री सभापति : अहमद जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है। प्लीज, आप बैठ जाइये।

श्री नसीम अहमद : सभापति जी, वर्ष 2011 में कांग्रेस शासन काल में पूरे प्रदेश में "शिशु जननी योजना" लागू की गई थी और इसकी शुरूआत मेवात से की गई थी। मेवात के मांडीखेड़ा के जनरल अस्पताल में इस योजना की शुरूआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने इस योजना के बारे में बड़े-बड़े दावे भी किये थे। "शिशु जननी योजना" का लक्ष्य बच्चों का कुपोषण और महिलाओं की कमजोरी को दूर करना था। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस वक्त इस योजना का उद्घाटन किया जा रहा था उस वक्त जनरल अस्पताल में एक भी लेडी डॉक्टर उपस्थित नहीं थी। अगर भाजपा सरकार भी उसी रास्ते पर चलेगी तो यह आपकी पार्टी के हित में नहीं होगा। पिछली सरकार ने प्रदेश में दस साल राज किया लेकिन आज उन्हें सड़क पर बैठने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है। अगर आपने मेवात के साथ दोगला व्यवहार किया तो आपके साथ भी वैसा ही होगा जैसा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ हो रहा है। (विघ्न) हमने तो बहुत कुछ किया है। हमारी सरकार ने मेवात को जिला बनाया और चौधरी ओमप्रकाश चौटाला ने मेवात में 400 करोड़ रुपये की रैनीवैल परियोजना शुरू की गई थी। खासकर नगीना ब्लॉक में ... (विघ्न)

श्री सभापति : नसीम जी, आपको बोलते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब आप बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. पवन सैनी : सभापति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडवा हलके में 800 करोड़ रुपये की परियोजना की घोषणा की थी जिस पर काम शुरू हो गया है और वहां पर विधान सभा की कमेटी विजिट करके आई है। (विघ्न)

श्री महीपाल ढान्डा(पानीपत ग्रामीण) : सभापति महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। (विघ्न) हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री ने सदन में बजट पेश किया है। हरियाणा की अढ़ाई करोड़ जनता ने सरकार के इस बजट की तारीफ की है मगर मात्र 38 लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बजट में खामियां नजर आ रही हैं। बजट पेश होने के बाद हमें एक टी.वी. चैनल पर बुलाया गया और वहां पर विपक्ष के सदस्य और आजाद उम्मीदवार श्री जयप्रकाश जी भी मौजूद थे। (विघ्न)

श्री जयप्रकाश : सभापति महोदय, मैं आजाद हूँ और आजाद रहूंगा। (विघ्न)

श्री महीपाल ढान्डा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री जयप्रकाश को समझने में जरा भूल हो गई है। मैंने उन्हें विपक्ष के सदस्यों में काउंट नहीं किया है। जब हम वहां पर गए तो बजट को लेकर विपक्षी सदस्यों द्वारा काफी शोर-शराबा मचाया जा रहा था। (विघ्न) वहां पर कहा गया कि इस बजट से हरियाणा कर्ज के बोझ के नीचे दब जाएगा और यह बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल है। मुझे आंकड़ों की बात तो समझ में नहीं आती मगर एक बात जरूर समझ में आती है कि हरियाणा विधान सभा के सत्र में हर सदस्य सिर्फ अपने हल्के के विकास की बात करता है। यहां पर कोई सदस्य कहता है कि मेरे क्षेत्र में खेतों में पानी नहीं है, कोई कहता है कि मेरे क्षेत्र में अस्पताल की हालत ठीक नहीं है और बिल्डिंग गिर गई है, कोई कहता है कि मेरे क्षेत्र के स्कूल ठीक नहीं है, हमारा नहरी तंत्र खत्म हो चुका है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था ठीक नहीं है और उसको दुरूस्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार से हर सदस्य हर क्षेत्र में बजट के बढ़ाने की मांग करता है। जब हमारी सरकार बजट बढ़ाकर पेश करती है तो विपक्ष के सदस्य कहते हैं प्रदेश पर वित्तीय घाटा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और हरियाणा प्रदेश कर्ज के बोझ में डूब जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि वे सदस्य वित्तीय घाटा तो याद रखते हैं मगर उनको एक बात याद नहीं रही कि हमारे यहां एक मूक क्रांति भी हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि हमें आंकड़ों का ज्यादा ज्ञान नहीं है लेकिन जो मूक क्रांति हुई है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। जब हम लोगों को सत्ता मिली थी उस समय आर्थिक जगत में जो सर्वे हुआ उसके हिसाब से हरियाणा 12वें स्थान पर खड़ा था। सभापति महोदय, जब यह बजट पेश किया गया उस वक्त 'इंडिया टूडे' के हिसाब से हरियाणा प्रदेश हिन्दुस्तान में नम्बर एक पर खड़ा था। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम के लिए एक बात कहना चाहता हूं -

परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके 'पर' बोलते हैं।
वो लोग रहते हैं खामोश अकसर जमाने में, जिनके हुनर बोलते हैं।

सभापति महोदय, ये हमारा मूक हुनर बोला था, जिसकी वजह से हम 12 वे नम्बर से पहले नम्बर पर आ खड़े हुए हैं। सभापति महोदय, कल भी और उससे पहले भी हमारी बहुत ही सम्मानित विधायक आदरणीय नैना चौटाला जी ने एक कविता पढ़ी थी। वे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी बहुत अच्छा बोली थी। कल भी उन्होंने अपने भाव बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त किए थे। कल उन्होंने कहा कि सब लोग जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो एक बात बोलते हैं कि 'सबका साथ सबका विकास'। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास, यह कौन सी गलत बात है ? हम तो इसी मूल मंत्र पर ही काम कर रहे हैं। इसी मंत्र के अनुसार ही हमारे मंत्री राव नरबीर सिंह जी ने एक संदेश दिया था। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार चाहती है कि सबको साथ लेकर सबका विकास करें। इसी नारे को लेकर ही उन्होंने बिना किसी के कहे सबकी टेबल पर यह लिखकर भिजवा दिया कि यदि आपकी कोई सड़क बची है जिसकी रिपेयर होनी रहती है तो आप उसके बारे में लिखकर दे दें, हम उसको ठीक करवा देंगे। सभापति महोदय, हमने कभी भी पक्षपात का रवैया नहीं अपनाया। जितने भी विधायकों ने गांव गोद लिए हैं, हमने उन विधायकों को कहा है कि आप अपने गांव को प्रगतिशील, उन्नतिशील और आदर्श गांव बनाएं। इसके लिए कृषि मंत्री जी ने उनको एक एक करोड़ रुपये देने की भी घोषणा

की है। प्रधानमंत्री महोदय का सपना है कि हम अगले 5 सालों में हरियाणा के किसान की ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसान की आय दुगनी करेगें। उसी बात को लेकर हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने पूरी संलग्नता के साथ इस काम को गति देना शुरू किया कि कैसे 5 सालों में किसान की आय दुगनी हो। इसके लिए हमको बहुत कुछ करना होगा। सभापति महोदय, हमारे यहां के किसानों की सबसे बड़ी समस्या पानी की है क्योंकि उनको अपने खेतों में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता। कहीं किसान को सेम की समस्या है तो कहीं पानी की कमी है और कहीं पानी है ही नहीं इसलिए हर विधायक खड़ा होकर बोलता है कि हमारे यहां पानी नहीं पहुंचाया गया। जमीन का गिरता भूस्तर हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। सभापति महोदय, इस चुनौती को समाप्त करने के लिए हमें जल संरक्षण करना ही पड़ेगा। **(इस समय अध्यक्ष महोदय चेयर पर आसीन हुए।)** अध्यक्ष महोदय, इसके लिए चाहे हमें वाटर शैड विकास प्रबंधन के कार्यक्रम शुरू करने पड़ें, तो हम करेंगे। सेम से प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनकी समस्या को दूर करने के लिए हमें पैसा चाहिए और बजट बढ़ना ही चाहिए। जब बजट बढ़ता है तो कई बार हमारे साथी बोलते हैं कि दो करोड़ बढ़ा दिया, 5 करोड़ बढ़ा दिया, 8 करोड़ बढ़ा दिया, इस बजट में क्या होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं उन साथियों को बताना चाहूंगा कि ये 8 करोड़, 5 करोड़ या 2 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है न कि मात्र 8 करोड़, 10 करोड़ या 12 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इस क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे तो किसान की पानी की समस्या हल हो जाएगी, सेम की समस्या समाप्त हो जाएगी और फसलें लहलहाएंगी। यदि फसलें लहलहाएंगी तो पक्की बात है कि प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो सपना था, वह पूरा होगा। इसके लिए सार्थक कदम हमारी सरकार ने भी उठाए हैं जिसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, हम लोग किसान की आय को बढ़ाना चाहते हैं। क्या यह आय हम केवल मात्र धान और गेहूं की फसल से बढ़ायेंगे। किसान की आय बढ़ाने के लिए हमें बागवानी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। बागवानी की योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए किसान को यह बताना होगा कि आप मात्र एक फसल पर निर्भर न रहिये और अपने फसल तंत्र को बदलिये और किसानों को बागवानी की तरफ आकर्षित कीजिए। बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में खुलने जा रहा है। उसका हमारे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा और उसके कारण हमारे किसान अपनी आय को बढ़ाने में सक्षम होंगे। इतना ही नहीं बल्कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान के लिए भी बजट बढ़ाया गया है उसकी भी मैं तारीफ करता हूं। उसकी तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि हमें आधुनिक खेती के नुख्से उसी अनुसंधान से सीखने को मिलते हैं। हमारे साईंटिस्ट टैस्ट करके बताते हैं उसका लाभ सभी किसानों को मिलता है। इसके लिए बजट बढ़ाया गया है इसका लाभ भी किसानों को अवश्य मिलेगा। यह जो हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय आने वाले सालों में दोगुनी की जाये उसको आगे बढ़ाने में एक कदम है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर बातें होती हैं कि हमारे जो किसान हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और यह बात बिल्कुल सही है। कहीं पर जल भर जाता है तो किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, कहीं पर आग लग जाती है तो किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, कहीं पर बिजली की चिंगारी से किसान की फसल बर्बाद हो जाती है। इसी तरह से आंधी से, तूफान से , ओलावृष्टि से और भारी बरसात से भी किसान की फसल बर्बाद हो जाती है। हमारी सरकार बनने के बाद भी बहुत से एरियाज में ऐसा हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने फसल नुकसान के मुआवजे के दायरे की राशि को बढ़ाया है। इससे हरियाणा के किसानों को बहुत लाभ मिलने वाला है।

श्री अध्यक्ष : ढ़ांडा साहब, प्लीज, आप वाईंड अप करें।

श्री महीपाल ढ़ांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। सर, मैं किसान की बात कर रहा हूं। सर, हमारे यहां पर फसल के नुकसान की भरपाई करने के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इससे हमारे किसानों को बहुत लाभ मिलने वाला है। ये ऐसे छोटे-छोटे प्वायंट हैं जो किसान की आय को दोगुना करने में सक्षम बन सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, पण्डित दीनदयाल जी का सपना था कि हर खेत को पानी मिले। हम हर खेत का पानी तभी दे पायेंगे जब हमारी नहरी सिस्टम पूरी तरह से दुरूस्त होगा। जब नहरी सिस्टम को ठीक करने की बात करते हैं तो इधर-उधर से यहां बातें आती हैं कि हमारे यहां पर नहरी सिस्टम ठीक करने के लिए 10 करोड़ रुपये की जरूरत है, कहीं से आवाज आती है कि 20 करोड़ की और कहीं से आवाज आती है 50 करोड़ रुपये की जरूरत है। इस बार इस सारे तंत्र को ठीक करने के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। जिसके कारण हमारे यहां पर पानी की समस्या समाप्त होगी और किसानों को इससे बहुत फायदा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, यदि किसान के पास पशु धन नहीं है तो वह अधूरा रहता है। यहां पर पशुधन की चिंता किसी ने नहीं की। यहां कोई चिंता करता है तो कहता है कि हमारे यहां 100 बैड का हास्पिटल होना चाहिए, पी.एच.सी. होनी चाहिए या सी.एच.सी. होनी चाहिए। लेकिन हमारा जो किसान है वह पशुधन के बगैर अधूरा है। उसके पशु धन की चिकित्सा की बात भी यहां होनी चाहिए और सरकार ने उसकी तरफ ध्यान भी दिया है। पशुधन की चिकित्सा के लिए भी बजट बढ़ाया गया है जिसके कारण अच्छी टैक्नोलोजी पशु चिकित्सा संस्थानों में आयेगी और किसानों के पशुओं का उसमें अच्छी तरह से ईलाज होगा। जिससे किसान को बहुत फायदा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दुग्ध प्रोत्साहन योजना को भी लागू किया है। दुग्ध पर पहले जहां 4 रुपये प्रति लीटर सबसिडी थी उसको बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से हमारी सरकार ने किसानों के लिए हर क्षेत्र में काम किए हैं और विपक्ष के साथी कहते हैं कि किसानों के हित में सरकार ने काम नहीं किए। हमारी सरकार ने किसानों की गन्ने की बकाया पेमैंट देने के लिए शुगर मिल्ज को भी 646 करोड़ रुपये दिए हैं ताकि किसानों की बकाया पेमैंट हो सके। इसी प्रकार से आने वाले वित्त वर्ष में भी 400 करोड़ रुपये सहकारी चीनी मिलों और 50 करोड़ रुपये निजी चीनी मिलों को देने का प्रावधान किया है। मैं इसके लिए भी माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, अब मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछेक समस्यायें लाना चाहूंगा। हमारे यहां पर एक शुगर मिल है जिसको शिफ्ट करने की योजना पर काम चल रहा है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस बजट में इसके लिए विशेष राशि का प्रावधान करके पानीपत की इस शुगर मिल को जल्दी से जल्दी शिफ्ट करवाने का कार्य करवाया जाये। मेरे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पॉलिक्लीनिक बनाने की भी घोषणा की थी लेकिन इस मामले में एक टैक्नीकल प्वांयट लगाकर इस घोषणा को दरकिनार कर दिया गया है कि दो जिलों के लिए केवल एक ही पॉलिक्लीनिक की स्थापना की जा सकती है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से पुन : अनुरोध है कि वे अपनी पूर्व घोषणा को ध्यान में रखते हुए एवं हमारे ईलाके में पशुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए एक पॉलिक्लीनिक की जल्दी से जल्दी स्थापना करने का संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें। मुझे सोते-जागते और उठते-बैठते

एक ही समस्या को हल करने की चिंता परेशान करती रहती है कि हमारे प्रदेश में जो अवैध कालोनियां हैं उनको जल्दी से जल्दी वैध करार दिया जाये और वैध करार देकर उनको बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को जल्दी से जल्दी मुहैया करवाया जाये। हमारी ये कालोनियां जितनी जल्दी वैध घोषित हो जायें उतना ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि वहां पर रहने वाले लोगों का बहुत ही बुरा हाल है। अगर यह काम जल्दी से जल्दी हो जाता है तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बार-बार हार्दिक धन्यवाद करूंगा। मुझे उम्मीद ही नहीं अपितु पूरा विश्वास है कि आदरणीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी सभी मांगों को स्वीकार करते हुए उनके ऊपर जल्दी से जल्दी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। स्पीकर सर, अब मैं एक शेर यहां पर अर्ज़ करना चाहता हूं :-

चुपचाप बैठा क्यों आसमान देखता है,
पंखों को खोल ज़माना केवल उड़ान देखता है।
लहरों की आदत है शोर मचाने की,
कामयाबी उसे मिलती है जो नज़रों में तूफान देखता है।।

हमारी सरकार हरियाणा के विकास के लिए बहुत से काम तीव्रता के साथ कर रही है। स्पीकर सर, इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करते हुए एवं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री विशम्भर दास बाल्मिकी (बवानी खेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सदन में बजट पर अपनी बात रखने का मौका दिया। हालांकि मेरे से पहले काफी माननीय सदस्यों द्वारा बजट पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है इसलिए मैं उन सभी बातों को ज्यादा नहीं दोहराना चाहता हूं लेकिन इसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आदरणीय वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी ने जो जन हित का बजट पेश किया है मैं उसका यहां पर जिक्र करना बेहद ज़रूरी समझता हूं। अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी ने प्रदेश के स्वर्ण जयंती वर्ष में राज्य का वर्ष 2016-17 का जो बजट प्रस्तुत किया है वह "सबका साथ, सबका विकास" के मूल मंत्र पर चलते हुए प्रदेश के सभी लोगों के समान विकास की सोच का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पांच वर्षों के अंदर किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की घोषणा की है और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना शुरू की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंर्तगत हमारी सरकार ने वर्ष 2016-17 के बजट में 300 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है। पण्डित दीनदयाल उपाध्याय के हर खेत को पानी उपलब्ध करवाने के सपने को साकार करने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए हमारी सरकार द्वारा अनेक नई-नई योजनायें शुरू करने की पहल की गई है। इनमें से 143 करोड़ रुपये की लागत से उठान सिंचाई प्रणाली की क्षमता को सुधारना मुख्य है। इससे हमारे पिछड़े क्षेत्र भिवानी, रिवाड़ी और महेन्द्रगढ़ जैसे दक्षिणी हरियाणा के जिलों को विशेष फायदा होगा। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का संकल्प सभी ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घण्टे बिजली आपूर्ति करने का है। सरकार ने वर्ष 2015 में म्हारा गांव-जगमग गांव नामक एक खास योजना शुरू की है। इस योजना के आरम्भ में 297 गांवों में बिजली आपूर्ति बढ़ाकर 15 घण्टे तथा बाद में 25 गांवों में बिजली आपूर्ति बढ़ाकर 18 घण्टे प्रति दिन की गई है। इसके बेहतरीन परिणामों से उत्साहित हो कर

[श्री विशम्भर दास बाल्मिकी]
सरकार ने चालू वर्ष में इस योजना का विस्तार 260 फीडरों तक करने का निर्णय लिया है जिसके पश्चात लगभग 1000 गांवों को प्रतिदिन 15 घण्टे की बढ़ी हुई बिजली की आपूर्ति होगी। अध्यक्ष महोदय, पहले की सरकारें गरीब लोगों को सिर्फ वोट बैक का जरिया मानती थी और केवल चुनाव के समय एक दो योजनाओं की घोषणा करके भोलेभाले लोगों को ठगने का कार्य करती थी परन्तु माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास की विभिन्न स्कीमें अभी से शुरू कर दी गई हैं। राज्य सरकार हमारे देश के सबसे प्रेरणादायक नेताओं में से एक भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की 125वीं जयन्ती मना रही है। वे भारतीय संविधान के शिल्पी थे और उन्होंने शोषित व पद् दलितों का गौरव व गरिमा बढ़ाई और उनकी आवाज बने। प्रदेश सरकार द्वारा उनकी 125वीं जयन्ती के मौके पर उनके समानता के सन्देश को जन-जन तक पहुंचाने और समाज के वंचितों, गरीबों और सीमांत वर्गों के उत्थान के लिये अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से सरकार द्वारा गरीब लोगों के लिए "अन्तोदय" - पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान के सिद्धांत के अनुरूप उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिये कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। गांवों के लोगों के लिये दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू की गई है ताकि लोगों को लगातार बिजली मिल सके। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने जितने विकास के कार्य किये हैं उनको अगर मैं गिनवाने लग गया तो शायद पूरा दिन भी कम पड़ जायेगा परन्तु मैं संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि आम जनता के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि वर्ष 2016-17 के इन बजट अनुमानों में कोई नया टैक्स लगाने का प्रस्ताव नहीं किया है बल्कि कई टैक्सों में राहत भी दी गई है इसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का व वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र बवानी खेड़ा की कुछ मांग भी रखना चाहता हूँ। पिछली सरकारों ने बवानी खेड़ा विधान सभा क्षेत्र की बहुत अनदेखी की है। मैं आपके माध्यम से बवानी खेड़ा तहसील को उप-मण्डल बनाये जाने और बवानी खेड़ा में मार्केट कमेटी बनाए जाने की मांग करता हूँ ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि गांव प्रेम नगर में प्रस्तावित चौ. बंसी लाल विश्वविद्यालय की भूमि का पूजन करके इसकी आधारशिला रखने का कष्ट करें ताकि आसपास के इलाके के बच्चों को शिक्षा के अवसर मिल सकें। अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में गांव खरक व कलिंगा दो बड़े गांव हैं, मैं आपके माध्यम से यहाँ कन्या महाविद्यालय, आई.टी.आई. व सी.एच.सी. की मांग करता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं बवानी खेड़ा विधान सभा क्षेत्र के स्कूलों को अपग्रेड किये जाने की भी मांग करता हूँ। बवानी खेड़ा विधान सभा क्षेत्र में कई बड़े गांव तिगड़ाना, खरक कलां, खरक खुर्द, कलिंगा, धनाना, तालु, बडेसरा, मिताथल, कुंगड़, बड़सी, रतेरा, बलियाली के अलावा दर्जनों गांव ऐसे हैं जिनमें अन्दर की गलियों की हालत खस्ता है इसलिए इनके निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, समस्याएं तो बहुत ज्यादा हैं परन्तु मैं ज्यादा समय न लेते हुये अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री घनश्याम दास (यमुनानगर) : अध्यक्ष महोदय, स्वर्ण जयंती वर्ष में बजट अनुमान 69 हजार 140 करोड़ रुपये से 28.4 प्रतिशत वृद्धि करके 88 हजार 781.96 करोड़ रुपये के प्रस्ताव

को माननीय वित मंत्री जी द्वारा स्वर्ण जयंती वित नीति संस्थान स्थापित करने का जो संकल्प लिया है उसके लिए मैं माननीय वित मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्रों में पिछले वर्ष के 11 हजार 441.11 करोड़ रुपये से बढ़ाकर इस वर्ष में 13 हजार 494 करोड़ रुपये करके उसे 13.71 प्रतिशत बढ़ाया गया है जो यह दर्शाता है कि हमारी सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत ही करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चित रूप से फसलों के विविधिकरण के लिए सहायक सिद्ध होगी। पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के हर खेत को पानी उपलब्ध करवाने के सपने को साकार करने के लिए भी हमारी सरकार ने पहल की है। प्रदेश के किसानों को समय रहते चीनी मिलें भुगतान कर सकें इसके लिए भी सरकार ने चीनी मिलों को ऋण देने का साहसिक कदम उठाया है परन्तु समस्या के स्थाई समाधान के लिए मैं माननीय वित मंत्री व कृषि मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक चीनी मिलें, बिजली उत्पादन और एथिनॉल उत्पादन शुरू नहीं करेंगी तब तक वे लाभ अर्जित कर सकेंगे इसमें मुझे संदेह है और जब तक चीनी मिलें लाभ अर्जित नहीं करेंगी तब तक वह किसानों को लाभकारी मूल्य देने में असमर्थ रहेंगी। इसलिए मैं माननीय वित मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि निजी तथा सहकारी चीनी मिलें जल्द से जल्द कोजन शुरू करें अर्थात बिजली उत्पादन अथवा एथिनॉल उत्पादन शुरू करें जिससे निश्चित रूप से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। इसके साथ ही हमारे यमुनानगर जिले में बोर्ड तथा प्लाई का एक स्थापित उद्योग है जिसमें लगभग तीन सौ इकाइयां कार्यरत हैं जिनके विकास के लिए विशेष पैकेज की आवश्यकता है क्योंकि यह उद्योग पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करने में सक्षम है क्योंकि ये किसानों से पॉपलर और सफेदा अर्थात कच्चा माल खरीदते हैं जिसके मूल्य बहुत कम हैं जिसके कारण इससे किसानों का रूझान हट रहा है जो भविष्य में इस उद्योग के लिए संकट पैदा कर सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि किसान को पॉपलर तथा सफेदा के ठीक मूल्य मिले। इस पर भी सरकार विचार करे। किसान, उद्योग और श्रमिक का समग्र विकास हो उस पर विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है। मान्यवर, हमारे नगर निगमों और नगर परिषदों में कर्मचारियों की कमी के कारण विकास व स्वच्छता के सभी कार्य बाधित हो रहे हैं। नगर निगम और नगर परिषद दोनों क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इसके साथ अनाधिकृत कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं का नितांत अभाव है। मेरा निवेदन है कि अनाधिकृत कालोनियों को शीघ्रातिशीघ्र अधिकृत कर पाईलट प्रोजैक्ट चलाकर उन कालोनियों का विकास प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो गांव नगर निगमों में आए हैं उनकी स्थिति तो और भी दयनीय है क्योंकि उनकी गिनती न तो गांव में हो रही है और न नगर में जिसकी और भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। स्पीकर सर, वर्तमान बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया बल्कि कुछ करों में छूट दी गई है जो माननीय वित मंत्री का यह कदम स्वागत योग्य है। अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बजट से हरियाणा प्रदेश का सर्वांगिण विकास होगा जिससे हमारा प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बनेगा ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इस बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मूल चन्द्र शर्मा (बल्लभगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तथा वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी की रहनुमाई में जो बजट पेश हुआ है उसमें हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों का ध्यान रखा गया है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसका इस

[श्री मूल चन्द्र शर्मा]

बजट में ध्यान न रखा गया हो। वर्ष 2016-17 के बजट में शिक्षा, सड़क, कृषि तथा चिकित्सा आदि सभी क्षेत्रों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है। मैं तो यह कहता हूँ कि किसी भी क्षेत्र को विकास की दृष्टि से अछूता ही नहीं छोड़ा गया है। यह एक आम आदमी का बजट है जिसमें किसी भी क्षेत्र की अनदेखी नहीं की गई है। यद्यपि मैं विधान सभा का सदस्य अभी बना हूँ लेकिन मैं राजनीति से बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ। मैने बहुत से मुख्यमंत्रियों के शासन काल को देखा है। मैंने वर्ष 1982 से बहुत से बजट पेश होते हुए देखे हैं। मैंने देखा है कि पहले के मुख्यमंत्री बजट को किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित कर देते थे फलस्वरूप दूसरे जिले विकास की दृष्टि से मरहूम रह जाते थे। वर्तमान बजट को "सबका साथ-सबका विकास" की अवधारणा के आधार पर कैप्टन अभिमन्यु जी के नेतृत्व में बनाया गया है। इसके लिए कैप्टन साहब बहुत ही बधाई के पात्र हैं। वर्तमान बजट में किसी भी प्रकार का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है अपितु टैक्स में छूट का ही प्रावधान किया गया है। फरीदाबाद को मेहन्दी उद्योग के लिए जाना जाता रहा है। मेहन्दी उद्योग का नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन काम नहीं है। मेहन्दी के उद्योग में टैक्स लगाया जाता था जिसके कारण इससे जुड़े लोगों को ज्यादा आमदनी या लाभ नहीं मिल पाता था। वित्त मंत्री जी ने जो मेहन्दी उद्योग को टैक्स फ्री किया है उसकी वजह से इस उद्योग से जुड़े काफी बड़ी संख्या में लोगों को लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त जो कृषि के लिए बजट रखा गया है उसके लिए भी मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा प्रदेश में किसानों की फसलों को सफेद मक्खी, लाल मक्खी और ओलावृष्टि से काफी बड़ी संख्या में नुकसान पहुंचा है। सफेद मक्खी के प्रकोप के कारण पांच जिलों में कपास की फसल खराब हो गई थी जिसके लिए 967 करोड़ रुपये की राशी मुआवजे के तौर पर दी गई। इसी प्रकार से 2015 में रबी अर्थात गेहूँ की फसल खराब होने पर मुआवजे के तौर पर लगभग 1092 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर वितरित किए गए। इस तरह से मुआवजे की अदायगी की कार्यवाही हमने जिन्दगी में पहले किसी भी मुख्यमंत्री के शासन काल में नहीं देखी। हमने तो यहां तक देखा है कि 100-200 रुपये की राशि के चैक मुआवजे के तौर पर दे दिये जाते थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सबको साथ लेकर सबका विकास किया है। ऐसा मुख्यमंत्री हमने पहले कभी नहीं देखा है। हरियाणा प्रदेश में चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल तथा चौधरी बंसीलाल जैसे मुख्यमंत्री रहे हैं लेकिन सभी के शासनकालों में कहीं न कहीं एस.वाई.एल. नहर, ओलावृष्टि तथा सफेद मक्खी के नाम पर किसानों के साथ राजनीति की गई लेकिन मुआवजे के तौर पर दिया कुछ नहीं गया। यह पहला ऐसा मौका है जबकि इतनी बड़ी राशि किसानों को मुआवजे के तौर पर दी गई है। हरियाणा प्रदेश में अपने स्वार्थों को साधने के लिए राजनीति का सहारा लिया जाता है। अभी पिछले दिनों प्रदेश में जाट आरक्षण आंदोलन को राजनीति का मोहरा बनाया गया। प्रदेश में लोगों के घर जलाये गए, उनकी दुकानों को आग लगा दी गई, मां-बहनों की इज्जत को तार-तार करके रख दिया गया, आगजनी को अंजाम दिया गया, कहीं जात पात के नाम पर एक दूसरे को मारने का काम किया गया लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने इस तरह की राजनीति पर पूर्ण विराम लगाने का काम किया। अब ऐसे हालात बन चुके हैं कि वही पार्टियां राज करेंगी जो काम करने में विश्वास करती हैं। अब महज राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ही एस.वाई.एल. नहर को मुद्दा नहीं बनाया जा सकेगा। हमें पूरी आशा है कि एस.वाई.एल. नहर मामले पर सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा प्रदेश को राहत मिलेगी। अब पानी के नाम से तथा किसान के

नाम से राजनीति नहीं की जा सकेगी। यह एक बहुत ही बढ़िया बजट है जिसमें प्रदेश की सभी 36 बिरादरियों का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक विनती करना चाहता हूँ। मेरा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। यहां पर स्थित अरावली पहाड़ियों से हजारों करोड़ रुपये का प्रदेश को रेवेन्यू प्राप्त होता था। यहां एन.सी.आर. में पत्थर का बहुत बड़ा काम है। आज हजारों करोड़ रुपये का रेवेन्यू राजस्थान में चला जाता है। राजस्थान से जो सड़क हरियाणा प्रदेश को जोड़ती है वह टूटी-फूटी व बहुत बुरी कंडीशन में हैं जिसकी वजह से कितनी ही दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अगर हरियाणा प्रदेश में मेवात, पलवल, फरीदाबाद की पहाड़ियों में खनन का कार्य शुरू करवा दिया जाता है तो यहां के लोगों को भी काम मिल जायेगा जिसके कारण आम आदमी का विकास भी संभव हो सकेगा। राजस्थान से जो रोड़ी हरियाणा प्रदेश में लाई जाती है उसकी कीमत 42 रुपये प्रति फुट होती है। अगर प्रदेश में खनन कार्य खुल जाता है तो हरियाणा प्रदेश में लोगों को 16 रुपये प्रति फुट के हिसाब से रोड़ी मिल सकेगी। इसके अतिरिक्त फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव तथा मेवात में पानी की सबसे बड़ी समस्या है। यहां पर पानी की कमी की वजह से हाहाकार मचा है। हमारे यहां यमुना नदी बहती है जो फरीदाबाद के दो हिस्से करके निकलती है। अध्यक्ष महोदय, एक चीज देखिये नहरों में लिमिटिड पानी होता है, भाखड़ा नहर की भी अपनी कैपेसिटी है और इसके अतिरिक्त पानी के जो दूसरे सोर्सिस हैं वे भी फिक्स हैं उसके बावजूद कह दिया जाता है कि हसनपुर, मोहना या फतेहपुर से फरीदाबाद को पानी मिलेगा। जब पानी के हर सोर्सिज का लिमिटिड एरिया है तो आप ही बतायें कि अतिरिक्त पानी फरीदाबाद को मिलेगा कहां से ? अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में पानी की समस्या का एकमात्र हल यह है कि चूंकि यहां पर पहाड़ी एरिया है अत : यहां पर एक बांध बना दिया जाना चाहिए। इससे पानी का लैवल स्वाभाविक रूप से उपर आ जायेगा और फरीदाबाद में पानी की समस्या हल हो सकेगी। मेवात की तो बात ही छोड़ो अगर हम आज फरीदाबाद में पीने के पानी की गुणवता देखते हैं तो पायेंगे कि यहां का पानी खारा है। यह फरीदाबाद के लिए सबसे बड़ी समस्या है। फरीदाबाद आने के दो रास्ते हैं एक तो कालिंग कुंज का रास्ता है और दूसरा नेशनल हाइवे का रास्ता है। कालिंग कुंज के रास्ते की वजह से फरीदाबाद सारे दिन जाम की स्थित में रहता है। अध्यक्ष महोदय, अगर कालिंग कुंज का रास्त एन.सी.आर. से हो जाये तो फरीदाबाद की आम समस्या हल हो जायेगी। फरीदाबाद के लोगों को आने-जाने के लिए जाम से राहत मिल जायेगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने बड़ा जिगर करके फरीदाबाद के विकास के लिए काम किया है। किसानों को सफेद मक्खी के प्रकोप से हुई फसल के नुकसान का मुआवजा दिया है। रिजर्वेशन का बिल सर्वसम्मति से सदन में पास करवा कर लोगों को फायदा पहुँचाया है। अध्यक्ष महोदय, हमारा फरीदाबाद औद्योगिक नगरी के रूप में एशिया के मानचित्र में रहा है। फरीदाबाद को कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने उजाड़ने का काम किया था। फरीदाबाद में से उद्योगों को भगाने का काम किया था। फरीदाबाद दिल्ली के आस-पास है। फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात और पलवल एन.सी.आर. में आते हैं। फरीदाबाद एग्रीकल्चर पर निर्भर नहीं है। हमारे यहां से कुण्डली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे निकलता है। इस तरह के कई रास्ते निकलते हैं। यदि औद्योगिक क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाया तो ना तो आगजनी होगी, ना रास्ते रूकेगें। और ना ही लड़ाई-झगड़ें होंगे क्योंकि यह क्षेत्र शांति प्रिय रहा है। 'सबका साथ-सबका विकास' के अनुरूप काम होना चाहिए। इस औद्योगिक क्षेत्र को जब तक बढ़ावा नहीं दिया जायेगा तब तक आम

[श्री मूल चन्द्र शर्मा]

आदमी, मजदूर, किसान व व्यापारी लोगों का भला नहीं होगा। कृषि क्षेत्र में ओलावृष्टि से, सफेद मक्खी के प्रकोप से व अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की फसलें खराब हो जाती है। इस तरह से तो हरियाणा प्रदेश को कृषि का क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र आदि क्षेत्रों में बांटना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि फरीदाबाद में औद्योगिक क्षेत्र की कोई मदर यूनिट स्थापित की जाये, जिससे फरीदाबाद के साथ-साथ चार-पांच जिलों का विकास हो और आपस में भाईचारा बना रहे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू (पेहवा) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बजट के आंकड़ों की बात है, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने बजट की कोई भी मद नहीं छोड़ी है जिसके बारे में आंकड़ों सहित माननीय वित्त मंत्री महोदय को चेताया ना गया हो। बजट के हर पहलू पर उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। बजट के हर बिन्दु पर नुक्ताचीनी करके सरकार को हर कदम पर एक संकेत देने का काम भी किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों का सदन में फिर से जिक्र नहीं करना चाहता। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आये लगभग डेढ़ वर्ष का समय हो गया है। जब हम हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में जाकर पूछते हैं कि आपने नई सरकार बनाने का जो निर्णय लिया था, उसका क्या हुआ? लोग कहने लगे कि हमने इनैलो पार्टी की सरकार बनाई थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बनाई थी, लेकिन हमने एक नया तजुर्बा वर्तमान सरकार से हासिल किया है। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के एक साल बाद हम प्रदेश के सफाई कर्मचारियों से मिले थे, हमने कहा कि आपको 15 हजार महीने और स्थाई नौकरी देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी, अध्यक्ष महोदय लोग कहने लगे कि हमारे साथ तो ठगी हो गई है। हम मिले प्रदेश के किसानों से, हमने उनसे पूछा कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए कहा था, लोग कहने लगे कि रिपोर्ट लागू नहीं की गई। हम मिलें प्रदेश के कर्मचारियों से, हमने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब सरकार के समान वेतनमान देने की बात कही थी, उनका जवाब भी ना में था। हम मिले प्रदेश के युवाओं से, हमने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी ने बेराजगारी भत्ता 6000 से 9000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगार युवाओं को देने की बात कही थी, उनका जवाब भी ना में था। हम मिले प्रदेश के बूढ़े बुजुर्गों से, हमने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी ने बुढ़ापा पैंशन दो हजार रुपये देने की बात कही थी, वे लोग भी कहने लगे कि हमारे साथ तो ठगी हो गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूंगा -

"मस्जिद तो बना दी पल भर में, ईमान की हरारत वालों ने,

ये मन ही पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका।"

मैं बजट के बारे में कहना चाहूंगा -

"बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का,

जब चीरा तो कतरा एक खून निकला।"

हरियाणा प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु हैं। महाभारत में वीर अभिमन्यु को उनके अपने लोगों ने फंसाया था। कोई उनका चाचा था, कोई ताऊ था तो कोई उनका गुरू था। उनकी वीरगाथा सारे हिंदुस्तान में बड़े गर्व के साथ सुनाई जाती है। हमारे कैप्टन साहब पूर्व में एक फौजी रहे हैं। हरियाणा प्रदेश को इनसे बहुत आशाएं थी। अध्यक्ष महोदय, चाहे हिंदुस्तान में सर्वे करवाकर देख लिया जाए हमारा देश सबसे ज्यादा सम्मान राजनीतिज्ञ, नौकरशाह, पत्रकार, न्यायाधीश का नहीं बल्कि फौजी का करता है। इसीलिए हमें वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु से बड़ी आस थी लेकिन जिस तरह पिछली सरकार से प्रदेश को निराशा मिली थी वैसी ही निराशा इस बजट से प्रदेश के हर वर्ग को हो रही है। भाई ढांडा जी कृषि में डायवर्सिफिकेशन की बात कर रहे थे। आज प्रदेश का बिजली तंत्र बिल्कुल नाकारा हो चुका है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूंगा तो एक लम्बी फेहरिस्त बनेगी और सदन का बहुत समय लगेगा। आज हमारे सारे थर्मल पावर प्लांट बंद पड़े हुए हैं, दूसरे राज्यों से सस्ती बिजली लेकर उपभोक्ताओं को महंगे रेट पर दी जा रही है, कृषि की डायवर्सिफिकेशन और बागवानी के नाम पर सरकार ने बड़े-बड़े दावे किये हैं। अध्यक्ष जी, मुझ से मेरा बेटा कहने लगा कि पापा, प्रदेश में नई सरकार बनी है और मैंने अखबार में पढ़ा है कि सरकार बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को अच्छी सब्सिडी दे रही है तो क्यों न हम अमरूद का बाग लगा लें। मैंने उससे कहा कि सोच लो बेटा, यह सरकार भाजपा की है जिसे पूंजीपतियों की सरकार कहा जाता है। फिर मेरे बेटे ने कहा कि पिताजी, प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े नेक इन्सान है। इस पर मैंने उससे कहा कि तुम फिर अमरूद लगा लो। मेरे बेटे ने 10 एकड़ में अमरूद लगा दिए। मैं प्रदेश का विधायक हूँ और हमें अमरूद लगाए हुए एक साल हो गया है और अधिकारीगण मुझसे सैकड़ों साइन करवाकर ले गए हैं परंतु हमें आज तक सब्सिडी नहीं मिली है। आप स्वयं सोच सकते हो कि जब प्रदेश के एक विधायक को सब्सिडी नहीं मिलती तो आम जनता की क्या हालत होगी ? आम जनता को भला कहां से सब्सिडी मिलेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से पहले भी निवेदन कर चुका हूँ और अब फिर कर रहा हूं कि सब्सिडी देने की प्रक्रिया को क्लीयर और सरल किया जाए। आदमी से सैकड़ों जगह साइन करवा लिये जाएं और फिर एक-एक साल तक सब्सिडी न मिले तो आदमी की आस टूट जाती है कि पता नहीं सब्सिडी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। अगर हम रोजगार की बात करें तो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बजट में रोजगार के लिए 4 परसैंट की कमी की गई है। इसे देखकर हम कैसे मान लें कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। हर साल अनेक कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं इसके बावजूद पिछले सवा साल से कोई भी नई भर्ती नहीं हुई है। अगर हॉस्पिटल में चले जाएं तो वहां नर्स नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं मिलते। एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां पर अध्यापक और लैक्चरर की संख्या पूरी हो। हमारे प्रदेश के कर्मचारियों को आज तक पंजाब के समान वेतनमान नहीं दिया गया है। यह देखकर बड़ा दु:ख होता है कि दीवार के परले पासे काम करने वाले कर्मचारियों को हमारे प्रदेश के कर्मचारियों से दोगुना वेतन मिलता है। हमारे प्रदेश के पुलिस के जवानों को पंजाब से आधे वेतन में ही गुजारा करना पड़ता है। इससे ज्यादा घोर अन्याय इन कर्मचारियों के साथ नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, बजट में "आदर्श ग्राम योजना" की बात कही गई है। मेरे छोटे भाई असीम गोयल ने शहीदो को याद करते हुए सदन में एक शेर पढ़ा कि -

"शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले,

वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशां होगा।"

[सरदार जसविन्द्र सिंह संधू]

अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी 23 मार्च, 2015 को हुसैनीवाला में शहीद भगतसिंह, राजगुरू और सुखदेव के शहीदी दिवस पर उनकी समाधि पर गए थे। वहां वे यह कहकर आए थे कि हिन्दुस्तान में किसानों को 5 हजार रुपये पैंशन देंगे। देश के प्रधानमंत्री महान शहीदों की शहादत पर इतनी बड़ी बात कहकर आए थे और उस बात को एक साल हो गया है लेकिन उस स्कीम का अभी तक कोई अता पता तक नहीं है।

वित्त मंत्री(कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय हरियाणा प्रदेश के इस महान सदन में जो बजट का विषय प्रस्तुत किया गया है, उस पर हम डिप्टी लीडर आफ अपोजीशन की महत्वपूर्ण टिप्पणी और समीक्षा सुनना चाहते हैं। जो विषय भारत सरकार से सम्बन्धित हैं उनकी यहां चर्चा करेंगे तो उसका इस बजट की चर्चा में कोई लाभ नहीं होगा।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जब आपके साथी केन्द्र सरकार की नीतियों की यहां बड़ाई और चर्चा कर सकते हैं तो प्रधानमंत्री द्वारा इस देश में कही गई बात पर हम क्यों नहीं चर्चा कर सकते।

क्या हम लोगों पर इस बात के लिए कोई बंदिश है। आपके साथी इस पर चर्चा कर सकते हैं तो क्या इस तरफ के बैंचिज पर बैठे हुए लोगों के लिए कोई बंदिश है ?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूंगा कि बंदिश की बात नहीं है लेकिन एक मर्यादा होती है। हमारे साथी सदस्यों ने जिस भी विषय पर भारत सरकार की जिस भी स्कीम को उद्धृत किया है, ये वे स्कीमें हैं जिनको राज्य सरकार लागू करती है या उनमें अपना कुछ न कुछ कम्पोनेंट एड करती है और उन स्कीमों को एडॉप्ट करती है। इसी कारण ही हमारे साथियों ने उन स्कीमों की यहां चर्चा की है। कोई भारत सरकार की स्कीम है तो उसको इस चर्चा के दौरान अवायॅड करें, केवल मात्र ऐसा मेरा सुझाव है।

कृषि मंत्री(श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, उस दिन तीन स्कीमों की एक साथ घोषणा की गई थी। 12 रुपये का बीमा, 330 रुपये का बीमा और अटल पैंशन योजना। इन तीनों स्कीमों की अनाउंसमैंट उस समय वहां से हुई थी जिसमें किसानों को और दूसरे लोगों को कवर करने की बात थी। शहीदी दिवस पर प्रधानमंत्री जी किसानों की पैंशन की बात कहकर आए थे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि वे इस बारे में जानकारी ले लें कि यह योजना शुरू हो चुकी है। भारत में अटल पैंशन योजना के नाम से स्कीम चल रही है।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने एक साल पहले यह बात कही थी और अब अगला शहीदी दिवस आने वाला है लेकिन यह स्कीम यहां लागू नहीं हुई है। इस प्रकार यह तो लोगों के साथ बेइमानी वाली बात है। मैं आदर्श ग्राम योजना के बारे में कहना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार ने आदर्श ग्राम योजना चालू की है। सरकारी रिकार्ड के हिसाब से इस स्कीम के तहत 15 गांव सांसदों ने गोद लिए हैं, 53 गांव विधायकों ने गोद लिए हैं तथा 12 गांव अन्य संस्थाओं ने गोद लिए हैं। इस प्रकार टोटल 80 गांव गोद लिए गए हैं। प्रदेश में लगभग 6841 गांव हैं जिनमें से 80 गांव गोद लिए गए हैं और बाकी

साढे 6 हजार के आस पास गांव बचे है। मुख्यमंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि इन गोद लिए हुए गांवों को विकास के लिए एक एक करोड़ रुपये देंगे जोकि बहुत अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, एक साल में 7000 गांवों में से 80 गांव गोद लेकर उनका विकास करने की बात कही गई है तो बाकी 6500 गांवों का विकास करने में तो सैंकड़ों वर्ष लग जाएंगे। मेरा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आपने कई बार अखबारों के माध्यम से कहा है कि 5-5 या 7-7 करोड़ रुपये हर कांस्टीच्युंसी में विकास के लिए दिए जाएंगे जोकि अभी तक हमारी कांस्टीच्युंसी के लिए नहीं दिए गए हैं तो फिर समान विकास की बात कहां है।

श्री अध्यक्ष : संधू जी, आपको बोलने के लिए 5 मिनट का समय दिया गया था लेकिन आपको बोलते हुए 15 मिनट हो गए हैं इसलिए आप अपनी बात एक मिन्ट में कंक्ल्यूड करें।

मुख्यमंत्री(श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी यह जानकारी सदन के पटल पर रखी है कि पिछले डेढ़ साल में विकास के लिए 5 करोड़ रुपये से कम पैसा 6 विधान सभा क्षेत्रों में गया था। इन 6 विधान सभा क्षेत्रों के बारे में मैंने कहा है कि यदि वे अभी भी लिस्ट बनाकर विकास कार्यों की दे देंगे तो उसको अगले साल में पूरा करवा देंगे क्योंकि अभी यह वित्त वर्ष तो कल समाप्त हो रहा है। सरकार हर विधान सभा क्षेत्र में हर साल कम से कम 5 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवायेगी। यह जरूरी नहीं है कि उनकी डिटेल विधायक द्वारा दी जाती है बल्कि मेरे पास दरबार में भी लोग मिलने आते हैं उस समय भी एप्लीकेशन दे जाते हैं कि फलां काम करना जरूरी है। इस तरह भी हम काम करवा देते हैं। किस विधान सभा क्षेत्र में कितने रुपये का काम हुआ है उसका रिकार्ड रखा जाता है। यदि किसी माननीय सदस्य को डिटेल चाहिए तो वे मेरे ओ.एस.डी., मुकुल कुमार से पूछ सकते हैं कि पिछले डेढ़ साल में किस विधान सभा में कितना पैसा विकास कार्यों पर खर्च किया गया है। इस तरह से हर विधान सभा क्षेत्र में एक साल में 5 करोड़ रुपये के मिनिमम विकास कार्य होंगे। यह मिनिमम है इससे ज्यादा के भी कार्य हो सकते हैं।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पेहवा से नैशनल हाई वे संख्या 65 पूर्व से निकलता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां पर जमीन सड़क बनाने के लिए एक्वायर हो रखी है इसलिए पेहवा के पश्चिम से भी सड़क बनाई जाये ताकि वहां पर लोगों को परेशानी न हो। इस बारे में मैंने माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर से भी बात की है और उनको लिखकर भी भिजवा दूंगा। दूसरा मेरा अनुरोध है कि पेहवा के अंदर कम्युनिटी सैंटर की जरूरत है और वहां की म्यूनिसिपल कमेटी के पास अढ़ाई एकड़ जमीन भी है इसलिए वहां पर कम्युनिटी सैंटर बनाया जाए। पिछली सरकार के समय में उस जमीन पर भू-माफिया ने कब्जा करने की कोशिश की थी जो हमने छुड़वाया इसलिए उस जमीन पर कम्युनिटी सैंटर बनाया जाये। इसी तरह से इस्माईलाबाद हमारा बड़ा कस्बा है। वहां पर न तो बस स्टैंड है, न स्टेडियम है और न ही कोई रैस्ट हाऊस है। इन चीजों की वहां सख्त जरूरत है। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वहां की ये जरूरतें पूरी की जाएं। अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया और मैं बजट का टोटली विरोध करता हूं।

मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्टीकरण/सूचना

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो जानकारी देने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी ट्यूबवैल कनैक्शन की बात आई थी। इस बारे में विभाग से बात-चीत करने के बाद एक बात तय की है कि जो ट्यूबवैल के कनैक्शन अप्लाई हुए हैं उनकी सवा तीन साल की लिस्ट पैंडिंग है। वर्ष 2013, 2014, 2015 और वर्ष 2016 के इन तीन महीनों की लिस्ट पैंडिंग है। मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि वर्ष 2013 के कनैक्शन 6 महीने में पूरे कर दिए जायेंगे। इसी तरह से नेता प्रतिपक्ष ने और बाद में ढुल साहब ने लॉ एंड आर्डर के बारे में विषय उठाया था। उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं कि ऐलनाबाद विधान सभा क्षेत्र में 7 लोगों के खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। जिनमें से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनमें से जो लखबीर उर्फ लक्खा है उसकी चर्चा की गई है। उसकी छानबीन करने के बाद उसको छोड़ दिया गया था क्योंकि वह उस घटना में संलिप्त नहीं था। इसमें यह भी कहा गया कि वहां गांव जमाल में कृषि मंत्री जी किसी के घर गए। यह बात ठीक है कि विक्रम पुत्र ओम प्रकाश गांव जमाल के विरूद्ध मुकदमा दर्ज है और मंत्री जी विक्रम के घर नहीं गए बल्कि सुभाष के घर गए थे। निश्चित रूप से सुभाष और विक्रम चाचा-भतीजा हैं लेकिन उनके घर अलग-अलग हैं। मंत्री जी चाचा के घर गए हैं, भतीजे के घर नहीं गए और भतीजा आरोपित है। चाचा और भतीजे का रिश्ता जरूर है लेकिन जिस कार्यकर्ता के घर गए उसका नाम सुभाष है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है लेकिन अभी तक भी वे चाचा-भतीजा गांव में खुलेआम घूम रहे हैं। भतीजे की अभी तक गिरफतारी क्यों नहीं हुई।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, यह केस क्राईम ब्रांच, हिसार को सौंप दिया गया है और क्राईम ब्रांच इनवैस्टीगेशन कर रही है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से एक नर्स का विषय था कि अस्पताल के एक डॉक्टर ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। इस मामले की भी छान-बीन की गई और छान-बीन के दौरान यह पाया गया कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। इस बारे में 05.09.2014 को अफराज़ रिपोर्ट लिख दी गई है। अगर इस बारे में कोई और शिकायत आती है और उसके पक्ष में कोई गवाह इत्यादि आता है तो नियमानुसार पुन : उसकी तफशीश भी की जा सकती है। इसी प्रकार से एक रिपोर्ट दी गई है कि टी.वी. के अंदर सब चलता रहा है। इसकी एफ.आई.आर. भी 25 मार्च को लिख दी गई थी और उसमें चार दोषियों के नाम हैं। उन चार दोषियों में से एक दोषी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो तीन दोषी शेष रह गये हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए तीन अलग-अलग टीमें बना दी गई हैं ताकि उनको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जा सके।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से यह प्रार्थना है कि इसका जो एम.एम.एस. अभी चल रहा है उसको भी किसी न किसी प्रकार से रूकवाया जाये।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा श्री परमेन्द्र जी ने कहा है कि उस एम.एम.एस. को रूकवाने के लिए भी हर सम्भव आवश्यक कार्यवाही करवायेंगे।

वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा पुनरारम्भ तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : अब श्री जय प्रकश जी बजट पर अपने विचार रखेंगे।

श्री जय प्रकश (कलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्तमंत्री जी से 4-5 विषयों पर वास्तविक जानकारी चाहता हूं। यहां पर ग्रामीण विकास मंत्रालय को बजट अलॉट हुआ है। मैं यह बात भी विशेष रूप से माननीय वित्त मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि वैसे तो यह समस्या पूरे हरियाणा प्रदेश में है लेकिन विशेषकर मेरे नॉलेज के हिसाब से जो कैथल, जींद और हिसार का इलाका है वहां पर ज्यादातर बड़े गांव हैं उनमें अधिकतर आबादी गांव से बाहर चली गई है और तालाब गांव के बीच में आ गये हैं। सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है कि हरियाणा प्रदेश में जो 10 हज़ार से ज्यादा आबादी वाले गांव हैं उनमें सरकार द्वारा सीवरेज़ सिस्टम डलवाया जायेगा। सरकार की यह एक बहुत ही अच्छी घोषणा है। जैसे सरकार ने घोषणा की है मैं अपने कलायत विधान सभा क्षेत्र के सेरदा, बालू और बात्ता इत्यादि गांवों का जिक्र करना चाहूंगा कि इन गांवों में और ऐसे बहुत से गांवों में मई-जून के महीने में भी जब भयंकर गर्मी का मौसम होता है उस समय भी तालाब ओवरफ्लो रहते हैं और तालाबों का पानी लोगों के घरों में पहुंचा हुआ होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने वाले गांवों में सीवरेज सिस्टम कब तक डलवायेंगे हमें इसकी समय सीमा बता दी जाये और साथ में यह भी बताया जाये कि इसके लिए कितना फण्ड अलॉट किया गया है। लोगों के मन में यह शंका रहती है कि सरकार द्वारा इस काम के लिए बजट में कितना पैसा रखा गया है। ऐसे ही सरकार द्वारा आदर्श गांव के बारे में घोषणा की जा चुकी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हमें एम.एल.ए. बने हुए डेढ़ साल हो गया है और सरकार ने कहा था कि प्रति विधायक प्रति वर्ष एक गांव को इस योजना में शामिल किया जायेगा। इसलिए अगर समय के हिसाब से देखा जाये तो हमारे तो दो गांवों को इस योजना में शामिल किया जाना पक्का हो गया है। मैं इस बारे में यह भी जानकारी चाहता हूं कि आदर्श ग्राम योजना पर काम इसी बजट से शुरू होगा या फिर अगले बजट से शुरू होगा। मैं एक बात और माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रति गांव के हिसाब से तीन करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की गई है मैं इसको बहुत ही कम समझता हूं क्योंकि आज के समय में इससे कोई विशेष कार्य नहीं होने वाले हैं इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाये। जो सरकार का स्वच्छ भारत का उद्देश्य है उसके लिए भी हमारे गांवों का पूर्ण रूप से स्वच्छ होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि वास्तविक रूप में असली भारत तो गांवों में ही बसता है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हमारे गांव ज्यादा से ज्यादा साफ और स्वच्छ होंगे उतना ही हमारा स्वच्छ भारत मिशन सक्सैसफुल होगा। मेरे विचार से गांवों की सफाई व्यवस्था गांवों के बीच में आ गये तालाबों के कारण पूरी तरह से लड़खड़ा गई है क्योंकि वे हर समय ओवरफ्लो रहते हैं और सारे के सारे गांव का गंदा पानी उनमें जाता है। मेरा इस सम्बनध में एक सुझाव है कि पहले तो इस गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था की जाये और साथ में पशुओं के पीने के लिए भी ज्यादा से ज्यादा शुद्ध पानी की व्यवस्था करवाई जाये। जिन गांवों में तालाब नहीं है उन गांवों में भी पशुओं के पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करवाई जाये। इसी प्रकार से मैं एक बात और कहना चाहूंगा जिसका जिक्र विपक्ष के नेता ने भी किया था

[श्री जय प्रकाश]

कि जो आपकी सरकार द्वारा इस बजट में हरियाणा प्रदेश के बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए फण्ड रखा गया है वह बहुत ही कम है। आप आने वाले वर्ष में जिन बेरोजगार भाइयों को नौकरी देंगे वह तो अच्छी बात है लेकिन हमें यह शंका है कि जो बेरोजगार नौकरी नहीं लग पायेंगे उनको बेरोजगारी भत्ते के माध्यम से आर्थिक सहायता देंगे उसके लिए यह राशि बहुत कम रहेगी। हमें यह बताया जाये कि इस राशि को इतना कम क्यों रखा गया है। अब मैं बिजली के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। यह बात पूरी तरह से सच है कि इस वर्ष हरियाणा प्रदेश में बिजली की उपलब्धता बहुत अच्छी रही है। बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा लाईन लॉसिज की वजह चोरी बताकर प्रदेश के लोगों पर आरोप लगाया जाता है और वह भी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पर। मैं इस बारे में आपकी जानकारी में यह तथ्य लाना चाहूंगा कि इससे भी ज्यादा लाईन लॉसिज लूज़ तारों की स्पार्किंग और ट्रांसफॉर्मर्ज पर होने वाली स्पार्किंग से होता है। इसमें मेरा एक सुझाव है कि बिजली चोरी के मामले में जिस तरह से हम सब लोग और खास कर ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोग बदनामी का कारण बने हैं, बिजली की चोरी तो शहरों की बस्तियों में भी हो रही है लेकिन लाइन लॉसिज गांवों में ज्यादा हो रहा है। इस चोरी से भी बड़ा लॉस गांवों में ट्रिपिंग का है वहाँ पर ट्रिपिंग होती रहती है। तारें लटकती रहती हैं और ट्रांस्फार्मर पर आग जलती रहती है। इसलिए इन लाइन लॉसिज से बचने का एक तरीका यह है कि ज्यादा से ज्यादा सब-स्टेशन बनाए जायें और बिजली की पुरानी तारों को बदला जाये। बहुत से गांवों में तो बिजली की तारें तब से चली आ रही हैं जब से हरियाणा में बिजली आई थी, उसके बाद उनको बदला नहीं गया है। इसलिए बिजली के रेट बढ़ाने से ज्यादा जरूरी इन पुरानी लटकती तारों को बदलना है। अब मैं कर्मचारियों के बारे में अपनी बात कहना चाहता हूँ। मेरे से पहले हमारे कई साथी सदस्यों ने भी यह बात कही है और मैं भी कहना चाहता हूँ कि सभी कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान दिये जायें। चुनाव से पहले श्री रामबिलास शर्मा जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम सभी कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देंगे। आज आपके पास बजट में बहुत पैसा है उसमें से अगर इन कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान दे दिया जाये तो मैं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करूँगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारी विधान सभा है उसी प्रकार से पंजाब की भी विधान सभा है और एक ही बिल्डिंग में भी दोनों राज्यों के कर्मचारियों के वेतनमान अलग-अलग हैं। मेरा निवेदन है कि बाहर की लड़ाई तो लड़ी जा सकती है लेकिन एक ही प्रांगण में स्थापित इस विधान सभा के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान तो पंजाब के समान कर दिये जायें तो बहुत अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं अपनी गाड़ियों की पार्किंग के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ पर मुख्य सचिव महोदय बैठे हुये हैं और यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि प्रोटोकोल के हिसाब से तो हम इनके बराबर ही हैं या एक स्टैप ऊपर हैं लेकिन हमारी गाड़ियाँ बहुत दूर खड़ी होती हैं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे ड्राइवर्स और गनमैन के लिए वहाँ पर बैठने और चाय-पानी के लिए कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि एक डोरमैट्री जैसी सुविधा वहाँ पर उपलब्ध करवाई जाये जहाँ पर हमारे ड्राइवर, गनमैन और सहायक आदि वहाँ पर बैठ सकें और चाय-पानी पी सकें। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि जैसा श्री महिपाल ढांडा जी ने इंडिया टुडे का हवाला देते हुये बताया कि हरियाणा 12वें पायदान से पहले स्थान पर आ गया है। यह अच्छी

बात है लेकिन विधायकों के वेतन-भत्तों के मामले में हम सबसे आखिरी पायदान पर खड़े हैं। हमारे से तो गोवा भी ऊपर है। अध्यक्ष महोदय, हमें कम से कम गोवा से ऊपर तो बढ़वा दो। यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय, वित्त मंत्री महोदय तथा संसदीय कार्य मंत्री भी बैठे हुये हैं अगर इस मामले में भी हरियाणा को पहले स्थान पर लेकर आओगे तो बहुत अच्छा होगा। हमारे मीडिया के भाई भी यहाँ बैठे हुये हैं बाद में इस बात के लिये ये हमारी आलोचना भी करेंगे। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि हम तनख्वाह नहीं बढ़वा रहे हैं हम अपने भत्ते बढ़वा रहे हैं। जिस प्रकार से प्राईस इंडैक्स बढ़ जाता है, कर्मचारियों के वेतनमान बढ़ जाते हैं उसी प्रकार आज हमारे भत्ते बढ़वाने की भी आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, आपने विधायकों के वेतन भत्तों के लिए जो कमेटी बनाई थी उसमें मैं भी एक सदस्य हूँ और मेरी तो रिक्मैंडेशन यही है कि जिस प्रकार से आपने सर्वसम्मति से आरक्षण का बिल पास कर दिया उसी तरह से इसको भी पास कर दिया जाये तो हमारा काम चल जायेगा। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

13.00 बजे **श्री हरविन्द्र कल्याण (घरौंडा)** : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट का तो बहुत कम समय है क्योंकि इतने कम समय में तो पूरी बात भी नहीं हो पाएगी। आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, बजट बहुत अच्छा रहा जिसके लिए मैं माननीय वित मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने अपने बजट में बिना टैक्स लगाए हर क्षेत्र व वर्ग का पूरा ध्यान रखा है। जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन्फ्रास्ट्रैक्चर, इण्डस्ट्रीज और उसके साथ-साथ बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं, कमजोर वर्गों, व्यापारी और किसान सभी के सम्मान और उत्थान के लिए इस बजट में पूरा ध्यान रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं बातें तो बहुत करना चाहता था लेकिन समय के अभाव के कारण मैं अपने जो जरूरी विषय हैं केवल उन्हीं तक अपने आप को सीमित रखूंगा। स्पीकर महोदय, अभी पिछले दिनों में एक विषय आया है क्योंकि आप जानते हैं कि भूमि अधिग्रहण अब बहुत मुश्किल हो गया है पर सरकार के किसी भी प्रोजैक्ट के लिए अगर जमीन की जरूरत है तो मोटे तौर पर हम कहना चाहेंगे कि पंचायतों के पास जो जमीन है उसके ऊपर ही हम निर्भर रहेंगे। जैसे अभी पिछले दिनों में कुटेल में मैडिकल युनिवर्सिटी के लिए 178 एकड़ जमीन पंचायत ने दी है और होर्टिकल्वर युनिवर्सिटी के लिए **(इस समय उपाध्यक्ष महोदया चेयर पर आसीन हुई)** अन्जनस्थली गांव में जमीन का इन्तजाम किया गया है। वैसे हमें जमीन जरूर मिली लेकिन पूरे गांव की तरफ से सामूहिक रूप से एक विषय सामने आया कि जो गांव सैंकड़ों एकड़ जमीन सरकार को देगा तो उस जमीन से गांव के विकास के लिए जो आमदन आ रही थी तो उसकी भरपाई कैसे होगी। इसी के साथ गांव की तरफ से रोजगार की बात भी उठकर सामने आ रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने यह बात रखना चाहूंगा कि आने वाले समय में जहां-जहां भी हम पंचायतों से जमीन लेते हैं तो हम यह ध्यान रखें कि उसके लिए हमारी सरकार कोई एक स्पष्ट नीति तैयार करे जिसमें यह स्पष्ट हो कि पंचायत से जितनी जमीन सरकार लेगी तो उसके बदले में उस पंचायत को अर्थिक सहयोग क्या होगा ? और वहां लगने वाले प्रोजैक्ट में उस गांव को रोजगार के नाते सरकार की तरफ से क्या सहयोग होगा ? इसके साथ ही मैं मेरे घरौंडा विधान सभा क्षेत्र की दो-तीन मांगे हैं जिनके बारे में बताना चाहूंगा वैसे तो वहां काफी काम चल रहे हैं इसके अलावा एक सब डिविजन की बात है, एक लड़कियों के कॉलेज की बात है, एक बस स्टैण्ड की बात है,

[श्री हरविन्द्र कल्याण]

आई.टी.आई. की बात है, लेकिन मेरे क्षेत्र का एक गम्भीर विषय है जिसको मैं माननीय कृषि मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि करनाल शहर से एक मुगल कैनाल के रूप में घरौंडा विधान सभा क्षेत्र के गांव में ड्रेन नम्बर-1 बनकर आती है और उसी में एक इन्द्री की एस्केप ड्रेन गांव चोरा के आसपास आकर मिलती है। मगर उसके बाद वह ड्रेन लगभग 3 किलोमीटर तक खत्म हो जाती है और उसमें जो पानी आता है उसके पानी से किसानों की लगभग सैंकड़ों एकड़ जमीन हर वर्ष खराब होती है। उसके लिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उस 3 किलोमीटर के बाद एक ड्रेन जो जमालपुर से बाबरपुर मेन ड्रेन के अन्दर डलती है उसकी कनैक्टिविटी का इन्तजाम किया जाए ताकि यह ड्रेन कॉन्टिन्यू हो जाए और किसानों की जो 250-300 एकड़ जमीन हर वर्ष खराब होती है उससे छुटकारा मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदया : अब वित मंत्री जी वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानों पर उत्तर देंगे।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : उपाध्यक्ष महोदया, इस बार का बजट सत्र हरियाणा प्रदेश की विधायिका के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण अध्याय के तौर पर दर्ज होगा। शायद ही कभी किसी बजट सत्र में पिछले 50 वर्षों में इतनी बड़ी लम्बी चर्चा बजट के भाषण पर हुई हो। जिसमें सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो सब साथियों ने बहुत गहराई से अध्ययन करते हुए अपने-अपने तरीके से इस पर विचार व्यक्त किये। मैं माननीय अध्यक्ष जी को और सदन के नेता को आपको और हमारे विपक्ष के नेता का भी इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमने जो बजट प्रस्तुत किया उसको इस योग्य समझा और उसको पढ़ने की कोशिश करते हुए उसको समझकर अपनी-अपनी दृष्टि से उसकी समीक्षा करते हुए उसकी समालोचना भी की, उसकी कहीं न कहीं प्रशंसा भी की, उसका कहीं न कहीं स्वागत भी किया और उसका समर्थन भी किया और जहां-जहां अपने-अपने तरीके से उचित समझा अगर उसमें कोई कमी पाई तो उसको सदन के माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाने का काम भी किया है। आप सब ने बजट पर इतना समय लगाया और हमारा इतना सहयोग किया उसके लिए मैं आप सबका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम सब इस सदन के जितने माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं वे कभी सत्ता पक्ष में रहे हैं और कभी विपक्ष में रहे हैं और हर कोई अपने-अपने तरीके से हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा करने की सोच रखते हैं। वह अपनी-अपनी विचार धारा से कि हरियाणा का विकास कैसे हो, हरियाणा का भला कैसे हो। इसी सोच के आधार पर इस महान सदन में अपनी बात रखते आए हैं और सबके अपने-अपने अनुभव भी हैं कभी विपक्ष में हैं तो कभी सत्ता में भी रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा सदस्य होगा जो कहीं न कहीं तथा किसी न किसी भूमिका में पहले भी सत्ता पक्ष का हिस्सा नहीं रहा होगा। आप सभी माननीय सदस्यों ने बजट चर्चा में बढ़-चढ़कर भाग लिया इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सदन में बजट पर लंबी-लंबी चर्चाएं की गई और इस दौरान लम्बे-लम्बे विषय भी बराबर कवर हुए और अनेक माननीय सदस्यों के सुझाव व विचार सदन के सामने प्रस्तुत हुए। यह तो मुमकिन नहीं है कि मैं प्रत्येक सदस्य की हर बात पर अपनी रिप्लाई में वक्तव्य दूं लेकिन

जिन सुझावों व विषयों पर कार्य किया जा सकता है उन पर वक्तव्य देने की मेरी भरपूर कोशिश रहेगी और जो सुझाव बजट से इतर हैं अर्थात अलग हैं उनको विचार मंथन के लिए हमने नोट कर लिया है। वर्तमान में जो बजट हम सबने मिलकर पेश किया है उसमें वर्णित किन्हीं बिन्दुओं पर यदि हमारे किसी माननीय सदस्य को लगे कि बजट में फलां विषय पर गलत जानकारियां दी गई हैं तो उन जानकारियों को ठीक करने की कोशिश करें अगर जानकारी सही है और उसकी समझ कुछ अलग प्रकार से निकलकर आ रही है तो उस समझ को दुरूस्त करना मैं अपना धर्म समझता हूँ और उस धर्म को निभाने के लिए सदन में खड़ा हुआ हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, वर्ष 2016-2017 के बजट के माध्यम से हमने हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग यानी किसान, कर्मचारी, व्यापारी, उद्यमी, महिला, बच्चे, वृद्ध, अनुसूचित जाति व पिछड़ी जातियों के कल्याण, विद्यार्थी, बेरोजगार तथा समाज के सभी वर्गो के उत्थान के लिए हमने भरपूर कोशिश की है। हरियाणा की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। कृषि के साथ-साथ ग्राम-विकास का भी अपना एक अलग महत्व है। इन सबका पूर्ण रूप से ध्यान रखने के साथ-साथ उद्योग और उसके आगे सर्विसिस सैक्टर की किस प्रकार से उन्नति हो सके, यह कोशिश हमने वर्तमान बजट के माध्यम से की है। सदन में बजट पर चर्चा के समय जो विचार और सुझाव सामने आये हैं मैं उन विचारों और सुझावों पर एक-एक करके अपने रिप्लाई में टिप्पणी देने की कोशिश करूंगा। इस साल का बजट बनाते समय हमारे सामने कुछ प्रमुख चुनौतियां थी। सबसे पहले "उदय" की स्कीम का जो नकारात्मक प्रभाव आंकड़ों के उपर पड़ने वाला था उसको समायोजित करना, हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरा, सातवें वेतन आयोग का जो प्रभाव है उसको भी हमने बजट में शामिल करना था और उसके साथ-साथ जो पे-ऐनोमली के संबंध में जो माधवन कमीशन की रिपोर्ट आई है जिसके माध्यम से 60-62 हजार कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होने वाला है और उनमें इसको लेकर बड़ी उत्सुकता भी बनी हुई है तथा सदन में भी कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में चिन्ता भी व्यक्त की थी, इस प्रभाव को भी बजट में समायोजित करना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी। इसके अतिरिक्त जो हर महीने विभिन्न प्रकार के पैशनधारियों को पैंशन दी जाती है, पैंशन के हर साल बढ़ते हुए अतिरिक्त बोझ को भी इस बजट में समायोजित करना एक बड़ी चुनौती थी। इसके साथ-साथ लैंड एक्सपैंडीचर और कैपिटल एक्सपैंडीचर को निरन्तर बढ़ाते रहने की चुनौती भी हमारे समक्ष थी और सारे कार्य को पूरी मर्यादा के साथ करना इसकी भी हमें बराबर चिंता थी। मैंने सदन में "उदय" स्कीम के बारे में पहले से ही पूरी तफसील से बता दिया है और मैं नहीं समझता कि अब इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी। पिछली सरकार की जो लीगेसी थी उसको हमने इस बजट के माध्यम से ठीक करने का प्रयास किया है। पिछली सरकार से हमें कर्जे के रूप में जो विरासत मिली है उसके हिसाब से सरकार के एक अंग पर 35000 करोड़ रुपये का कर्ज था। उस एक अंग के कर्जे को उसके खाते निकालकर सरकार ने अपने खातों में लेकर महंगे कर्ज को सस्ते कर्ज में बदलकर प्रति वर्ष एक हजार से बारह सौ करोड़ रूपया ब्याज बचाने की कोशिश की है। हरियाणा की जनता के उपर इतना भारी कर्ज तो पहले से ही चढ़ाया गया था। इतने बड़े कर्ज को एकमुश्त लौटाना तो मुश्किल है इसलिए हमने कर्जे पर ब्याज की रकम कम करके हरियाणा प्रदेश की जनता और इसकी आने वाली पीढ़ियों पर कर्ज का मार कम करने के लिए अनूठी पहल की है और भारत सरकार ने भी अनुमान जताया है कि इस योजना के माध्यम से आने वाले कुछ वर्षों में लगभग 14000 करोड़ रुपये हरियाणा की बिजली कम्पनियों तथा हरियाणा सरकार को इस योजना के माध्यम से जरूर बचने चाहिए। इसी को

[कैप्टन अभिमन्यु]

मद्देनज़र रखते हुए मैंने सदन के पटल पर कहा था कि जैसे-जैसे बिजली कम्पनियों का नुकसान कम होता है तो बिजली की दरें तय करने के लिए हरियाणा रेगुलेटरी कमीशन द्वारा बिजली कम्पनियों के खर्चो का संज्ञान लेकर बिजली की दरें तय की जायेगी तो स्वाभाविक है कि यदि यह खर्च कम होगा तो निश्चित तौर से बिजली की दरें भी कम ही तय की जायेंगी और अंततोगत्वा उसका लाभ बिजली की कम दरों के रूप में उपभोक्ता को निश्चित रूप से मिलेगा। कई माननीय विधायकों ने यह सुझाव दिये थे कि विधायकों को आदर्श ग्राम योजना को सफल बनाने के लिए फंड दिये जाने का प्रावधान होना चाहिए। इस परिपेक्ष्य में मैं बताना चाहूँगा कि आदर्श ग्राम योजना के तहत एक करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान करना भी हमारी सरकार की एक नई शुरूआत है जो निश्चित रूप से "सबका साथ-सबका विकास" की अवधारणा को सफल सिद्ध करेगी और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी माननीय सदस्य के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव इस योजना के तहत नहीं होने दिया जायेगा। (इस समय मेजें थपथपाई गई) उपाध्यक्ष महोदया, यह संभव है कि बजट के आंकड़ों में कुछ कंफ्यूज़न हो सकता है, यह मैंने पहले ही बजट पेश करने के दौरान संकेत दिया था। इस बार के बजट आंकड़ों में कहीं ना कहीं दुविधा होगी और द्वंद होंगे क्योंकि इस बार बजट के आंकड़े दो प्रकार से प्रस्तुत किए गए हैं। एक 'उदय' की स्कीम के प्रभाव के बिना दूसरा 'उदय' की स्कीम पर प्रभाव पड़ने के बाद आंकड़े क्या बनते हैं, उस तरह से बजट पेश किया गया है। उपाध्यक्ष महोदया, इसलिए मैंने निवेदन किया था कि अगर हम पिछले सालों के बजट के आंकड़ों से तुलना करेंगे, तो बजट पर 'उदय' के स्कीम के प्रभाव के बिना पड़ने वाले आंकड़ों से तुलना करेंगे तो तुलना सही होगी। जिसको apple to apple comparison कहते हैं। उस नाते से हम कभी-कभी प्रतिक्रिया देते हैं। पिछले साल के उदय के साथ के आंकड़े और 'उदय' के बिना के आंकड़े, चूंकि उस समय तो 'उदय' था ही नहीं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदया, आने वाले समय में 'उदय' के कारण जो आंकड़े बने हैं, हमनें उनकी तुलना करके टिप्पणी की है। उपाध्यक्ष महोदया, एक-एक आंकड़े पर ना बोलते हुए यदि हम एक बार फिर से दोबारा से उन्हीं आंकड़ों के साथ तुलना करेंगे जो आज हमने 'उदय' के बिना आंकड़ें प्रस्तुत किए हैं तो इसका कम्पैरिजन ठीक आयेगा। उपाध्यक्ष महोदया, उसी की दृष्टि से मैं कहता हूँ कि हमने पिछले साल बजट प्रस्तुत करते हुए जब लक्ष्य तय किए थे तथा श्वेत पत्र में हमने जो बातें लिखी थी तथा जो बातें हमारे संज्ञान और समझ में आई थी कि हरियाणा की अर्थ व्यवस्था को आमूलचूल सुधारने के लिए जरूरी है कि हम फिस्कली रिस्पोंसिबल स्टेट के तौर पर इमर्ज हों। माइक्रो इकनॉमिक इंडीकेटर्स को लेकर हमें इतना सावधान और सजग होना चाहिए कि आज हमारे खर्चे के कारण आने वाली पीढ़ियों पर कर्ज का बोझ नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए मौलिक सुधार और बेसिक स्ट्रक्चरल में सुधार करने की जरूरत थी, उस दिशा में हमने काम करना प्रारम्भ किया है। चाहे फिस्कल डैफिसिट का टारगेट हो, रेवेन्यू डैफिसिट का टारगेट हो, प्राइमरी डैफिसिट का टारगेट हो और चाहे डैट की लॉयबिलीटी विज़ ए विज़ जी.डी.पी. का टारगेट हो, जो रेवेन्यू रिसीट जी.डी.पी. की तुलना में बढ़ने चाहिए उसका टारगेट हो, स्टेट के ऑन रिर्सोसिज बढ़ना चाहिए उसका टारगेट हो। इसलिए मैं इस महान सदन को बताना चाहता हूँ कि यदि आप बजट में प्रस्तुत आंकड़ों पर फिर से नजर डालेंगे तो पाएंगें कि हम हरेक आंकड़े पर सुधार की दिशा में आगे बढ़े हैं। हम एक भी पैरामीटर की तुलना में पिछले साल से कमजोर नहीं हुए हैं। माननीय सदस्य ने ऋण की मात्रा के बारे में चर्चा की थी, विपक्ष के नेता ने इस बात की चिंता व्यक्त कि

जी.डी.पी. की तुलना में ऋण की लॉयबिलीटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उपाध्यक्ष महोदया, पहली बात हमारी जो ऋण के मामले में लॉयबिलीटी है, वह भारत सरकार के फाईनेंस कमीशन की जो तय मर्यादा है या उसकी जो सीमा है हम कम्फर्टेबली उस सीमा के अंदर है। दूसरी बात हमने तय की है कि एफ.आर.बी.एम.एक्ट की मर्यादा का हम पालन करेंगे, उसमें भी हम पूरी तरह से उस सीमा के अन्दर है। उपाध्यक्ष महोदया, तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष की वर्ष 1999-2004 सरकार का कालखंड रहा, उसमें जो डैट लॉयबिलीटी टोटल जी.डी.पी. की थी, वह पिछले 20 वर्षों के इतिहास में लॉयबिलीटी जी.डी.पी. की तुलना में सबसे ज्यादा थी। उपाध्यक्ष महोदया, एक-एक वर्ष का आंकड़ा मैं सदन के पटल पर रखता हूँ। वर्ष 2013-14 में डैट लॉयबिलीटी टू जी.डी.पी. 18.02 प्रतिशत थी, अब बढ़कर साढ़े 19 प्रतिशत के करीब है। वर्ष 1999-2000 में 23.44 प्रतिशत थी, वर्ष 2000-2001 में 23.81 प्रतिशत थी, वर्ष 2001-2002 में 25.75 प्रतिशत थी, वर्ष 2002-2003 में 25.08 प्रतिशत थी और वर्ष 2003-2004 में 26.09 प्रतिशत तक चली गई थी। उपाध्यक्ष महोदया, राजनीति में कोई पार्टी सत्ता में रहती है और कोई पार्टी विपक्ष में रहती है, यह सब चलता रहता है। हर सत्ता पार्टी अपने तरीके से प्रदेश के लोगों के हितों के बारे में काम करने की कोशिश करती है। मैंने अपनी सोच में कभी भी अतीत में पूर्वजों द्वारा जो अच्छे प्रयास किये गए हैं उनकी निंदा करने की दृष्टि से नहीं बल्कि इस दृष्टि से इतिहास का अध्ययन करने की कोशिश जरूर की है कि उनकी बेहतरीन से बेहतरीन सोच के बावजूद कुछ प्रयासों में कुछ कमियां रह गई हों या कुछ गलतियां हो गई हों, उन गलतियों से हम सबक लेकर अपने भविष्य का निर्माण करें और अपने वर्तमान को सुधारने का काम करें। इसलिए इस दृष्टि से मैंने इस बजट में तुलना देने का काम किया है। हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने फिस्कल डैफिसिट के बारे में चर्चा की है कि फिस्कल डैफिसिट बढ़ रहा है, उपाध्यक्ष महोदया, उसके बारे में मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज हमने रेवेन्यू डैफिसिट का बिना 'उदय' की स्कीम के करीब 1.1 प्रतिशत का टारगेट रखा है। हमारा फिसकल डेफिसिट 2.47 है। यह वर्ष 1999 से 2003-04 तक के कालखण्ड में 4.15, 3.89, 4.18, 2.03, 3.54 तक रहा है। हम मानते हैं कि पिछली सरकारों के बेहतरीन प्रयासों के बावजूद भी ये स्थितियां रही होंगी। हमें इंट्रस्ट पेमैंट की भी चिंता है कि कुल आय का कितना हिस्सा ब्याज में चला जाता है। आज जिसे हम घटाकर 15-16 प्रतिशत के बीच में लाए हैं वह वर्ष 1999 से 2003-04 तक 23.54, 22.69, 21.37, 22.48, 21.46 और वर्ष 2004-05 में 20.04 रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लगातार प्रयासों के बाद आज हरियाणा प्रदेश सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सुधार की गुंजाइश निश्चित तौर पर हमेशा बनी रहेगी और बनी रहनी चाहिए। हम इसकी ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। यह हमारा संकल्प है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, सदन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने बजट को पढ़कर चिंता व्यक्त की है। हो सकता है कि उनके बजट को पढ़ने और देखने के तरीके में कुछ अंतर रहा हो। उन्हें लगा कि शैडयूल्ड कास्ट्स के कंपोनैंट एस.सी., एस.टी. प्लान को घटाया गया है। मैं उनको जानकारी देना चाहता हूँ कि एस.सी., एस.टी. कंपोनैंट टोटल बजट्री एलोकेशन का 20.3 प्रतिशत है। बजट में इनके लिए 6373.48 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जोकि पिछले वर्ष बजट प्रावधान 4730 करोड़ रुपये की तुलना में 34.74 प्रतिशत ज्यादा है। मैं इस बात को मानता हूँ कि माननीय सदस्य को आंकड़ों में दुविधा रही होगी। उसका कारण यह है कि भारतवर्ष एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। भारत सरकार ने 'प्लानिंग कमीशन' को खत्म करके 'नीति आयोग' का गठन किया है।

[कैप्टन अभिमन्यु]

'नैशनल इंस्टीटयूशन फॉर ट्रांसफोर्मिंग इंडिया', इस आयोग के बनने के बाद एक कॉओपरेटिव फैड्रलिज्म के सिद्धांत के आधार पर राज्यों के प्रतिनिधि मिलकर भविष्य की योजनाओं को बनाने का काम करते हैं। इस ट्रांजिशन के फेज में राज्यों के प्रतिनिधियों ने कमेटियां बनाकर पिछली बहुत-सी सैंटरल स्पोंसर्ड स्कीम को बंद करवा दिया और नई स्कीम्स की शुरूआत कर दी। उपाध्यक्ष महोदया, इससे सैंटरल स्पोंसर्ड स्कीम्स के स्टेट और सैंटर के लिए एलोकेशन में भी बड़ा भारी परिवर्तन हुआ है। हमारा पिछला सारा वर्ष इसी संक्रमण काल से गुजरता रहा और प्लानिंग बनाने में दुविधा रही कि कौन-सी स्कीम 100 प्रतिशत सैटरल स्पोंसर्ड है और कौन-सी स्कीम 90 प्रतिशत स्पोंसर्ड है इत्यादि। अत : हमें इस कारण से स्कीम्स बनाने में दुविधा रही है। कुछ स्कीम्स ऐसी थी जिन्हें केंद्र सरकार ने बंद कर दिया परंतु राज्य सरकार ने चालू रखा और इससे प्लान एक्सपैंडीचर का खर्च नॉन प्लान एक्सपैंडीचर की दिशा में चला गया। इससे कहीं-कहीं ऐसा आभास हुआ कि प्लान्ड एक्पैंडीचर जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए था वह उस अनुपात में नहीं बढ़ा। अत : मैं आपकी बजट को समझने की दुविधा को स्वीकार करता हूँ। वर्ष 2016-17 से भविष्य में यह दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अब सभी स्कीम्स का प्रारूप तय हो चुका है। इसे तय होने में एक वर्ष का समय लग गया और इसमें सभी राज्यों की सरकारें इनवॉलव्ड थी। मुझ ो पूरी उम्मीद है कि भविष्य में इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। भारत सरकार ने निर्णय लिया है प्लैन्ड एक्सपैंडीचर और नॉन प्लान एक्सपैंडीचर के भेद को समाप्त कर दिया जाएगा क्योंकि अर्थशास्त्री इस भेद को पसंद नहीं कर रहे हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि बजट को हर क्षेत्र में बढ़ाया गया है। इस बात को बजट के आंकड़े भी प्रूव करते हैं लेकिन बजट में दो चीजें हैं - एक प्लान बजट है और दूसरा नॉन प्लान बजट है। इन्होंने नॉन प्लान बजट के अंदर जो पैसा बढ़ाया है वह केवल और केवल पैंशन और सैलरीज में जाने की बात है, उससे विकास नहीं होगा। जो आंकड़ें मैंने आपके सामने रखे थे वे यह थे कि किस तरह से सरकारी विभाग में प्लान बजट में 366 करोड़ रुपये घटाया गया है। ग्रामीण विकास में केवल 23 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है। मंत्री जी, आप प्लॉन एक्सपैंडीचर और नॉन प्लॉन एक्सपैंडीचर दोनों के बारे में बताएं कि प्लॉन बजट में कितना बढ़ाया है और नॉन प्लॉन बजट में कितना बढ़ाया है ताकि सारी चीजें क्लीयर हो सकें।

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है, मैंने उसी बात को स्पष्ट करने की कोशिश की थी। डिवैल्पमैंट और पंचायत विभाग की सैंट्रल स्पोंसर्ड अनेकों ऐसी स्कीम्ज थीं जिनके स्ट्रक्चर में चेजिंज हुए हैं। उसके बावजूद भी राज्य सरकार उन स्कीमों को लेकर आगे चल रही है। प्लॉन एक्सपैंडीचर का जो कम्पोनैंट था, वह राज्य सरकार के खाते में नॉन प्लान एक्सपैंडीचर में बढ़ा है यानि उस दिशा में ट्रांसफर हुआ है। उसका ब्रेकअप विभाग के अन्तर्गत आता है। यदि नेता प्रतिपक्ष अनुमति देंगे तो मैं उसके आंकड़े उनको उपलब्ध करवा दूंगा। ये आंकडें पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है। उपाध्यक्ष महोदया, यदि बजट डाक्यूमैंट को गहराई से देखा जाए तो सारा स्पष्टीकरण आ जाएगा। मोटे तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले सालों की तुलना में जो प्लॉन एक्सपैंडीचर का कम्पोनैंट है वह वर्ष 2014-15 में टोटल खर्चे का 32 परसैंट था जबकि इस बार इसको 40 परसैंट पर लेकर आने में हमने

सफलता प्राप्त की है। इस दिशा में काम करने का हमारा संकल्प है। एक चिंता हमारे साथी ने रिवैन्यू डैफीसिट और फिस्कल डैफीसिट के बारे में व्यक्त की। हमारा रिवैन्यू डैफीसिट का टारगैट 1.1 परसैंट का था। फिस्कल डैफीसिट का टारगैट हम 3 परसैंट तक ले जा सकते हैं लेकिन हम इसको प्वांयट 5 कम करके यानि केवल 2.47 परसैंट तक रखना चाहते हैं और इसके कई कारण हैं। हम और ज्यादा कंजूसी करके चलना चाहते हैं। 'उदय' स्कीम का जो कम्पोनैंट है उसके लिए भारत सरकार द्वारा इजाजत दे दी गई है। 'उदय' स्कीम के प्रभाव के कारण वे मर्यादाएं हम पर लागू नहीं होगी। यह छूट हमें केवल 2 वर्ष के लिए ही दी गई है। हम कल्पना भी करें कि एक वर्ष के लिए भविष्य में यह छूट और दे दी जाएगी तो यह केवल हमारी कल्पना ही है। हो सकता है कि 3 वर्षो में इसका प्रभाव कुछ कम हो लेकिन अंतोतगत्वा इस कर्जे का प्रभाव बजट के आंकड़ों में कभी न कभी दो या तीन वर्षों में आना ही है। आज अगर हम अपने आप को थोड़ा टाइट करके चल पाते हैं तो इसका प्रभाव यह होगा कि आगे जजब करने की क्षमता हम रख पाएंगे। इस दृष्टि से हमने थोड़े कंजर्वेटिव टारगैट्स लिए हैं। हम इस टारगैट को बढ़ा सकते थे लेकिन हमने नहीं बढ़ाया। उपाध्यक्ष महोदया, एक चिंता यहां पर कैपिटा इनकम के आंकड़ों के बारे में आई कि जो ये आंकड़े दिए गए हैं ये गुडगांव और फरीदाबाद के हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस महान सदन में बजट स्पीच में पर कैपिटा इनकम के जो आंकड़े दिए गए हैं वे प्रदेश के आंकड़े हैं न कि किसी एक जिले के हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, जब यह सरकार बनी उस समय एक श्वेत पत्र जारी किया गया था। उस श्वेत पत्र में पर्टीकूलर लिखा गया था कि गुडगांव और फरीदाबाद के आंकड़ें दर्शाकर पर कैपिटा इनकम की बात पर हरियाणा में 10 सालों से लोगों को गुमराह किया गया है। उपाध्यक्ष महोदया, आज वही चीज इस बजट में भी दी गई है। मंत्री जी, गुडगांव और फरीदाबाद दो जिलों को छोड़कर बाकी जिले सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, कुरूक्षेत्र, अम्बाला और पंचकूला आदि जिलों के बारे में बताएं तो ज्यादा सही रहेगा।

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात कही है वही बात हम पहले दिन से कह रहे हैं और सरकार में आने से पहले भी कह रहे थे। यह बात सही है कि पर कैपिटा इनकम में हरियाणा पूरे भारत में अग्रणी राज्यों में है और यह बात भी सही है कि हरियाणा प्रदेश का विकास रीजनल इमबैलैंस का शिकार हुआ है और कुछ क्षेत्रों की घोर अनदेखी हुई है जिनमें से एक क्षेत्र से आप भी चुनकर आती हैं। इसकी चिंता हमने अपने श्वेत पत्र में भी जाहिर की है क्योंकि श्वेत पत्र हमारी डायनोसिज की एक्सरसाईज थी। हम किसी पर उंगली उठाने की सोच के साथ श्वेत पत्र नहीं लेकर आए। उस डायनोसिज में पाया कि प्रदेश में बहुत से जिले ऐसे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। इसके साथ-साथ हमने दूसरे अनालिसिज भी किए थे। नेता प्रतिपक्ष ने भी अभी पर कैपिटा इनकम के बारे में ईशू उठाया है। गुड़गांव और फरीदाबाद जिले की पर कैपिटा इनकम दूसरे जिलो की तुलना में 8 से 10 गुणा ज्यादा है। यह व्यवस्था हमको विरासत में मिली है। हम इसमें सुधार करने के लिए कदम उठा रहे हैं। यह व्यवस्था कोई दस साल में नहीं बिगड़ी बल्कि कई सालों में बिगड़ी है। हमने डायग्नोज करके इसमें सुधार करने के लिए कदम बढ़ायें हैं। हमारी नई इन्टर प्राईसिज प्रमोशन पॉलिसी का मुख्य उदेश्य यही था और उस पॉलिसी में हमने प्रमोशनल तथा इनसैंटिव स्कीम्ज बनाई हैं कि जो नया इनवैस्टमैंट आना है वह एन.सी.आर. के क्षेत्र ही में न आकर दूर दराज के

[कैप्टन अभिमन्यु]

एरियाज में भी आये ताकि वहां पर कारखाने और उद्योग लग सकें। यदि वहां कोई व्यापारी अपना काम शुरू करेगा तो वहीं के किसान का पैदा किया हुआ माल का उपयोग हो सकेगा और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ऐसा होने पर नौजवानों को घर के नजदीक ही रोजगार मिलेगा और शाम को काम करके अपने घर पहुंच सकेंगे। इसीलिए सबका साथ सबका विकास की नीति हम लेकर आये हैं। आज सबका साथ सबका विकास की आवश्यकता है। गुड़गांव में 2012-13 में प्रति व्यक्ति सालाना आय 4.47 लाख रुपये थी जो 2013-14 में बढ़कर 5.05 लाख रुपये हो गई थी। यह पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है और महेन्द्रगढ़ में प्रति व्यक्ति सालाना आया 45596 रुपये है। यह दस गुणा से ज्यादा का अंतर है। हमें ये चीजें ठीक करनी हैं। इसीलिए हमने हैपनिंग हरियाणा समिट किया और एम.ओ.यू. साईन किए हैं। जिसका माननीय विपक्ष के साथियों ने मन के अंदर-अंदर तो स्वागत किया लेकिन अपना विपक्ष का कर्तव्य निभाते हुए उस पर प्रश्नचिन्ह भी लगाये और चिंता भी व्यक्त की है। मुझे इतना विश्वास जरूर है कि कंपीटीटिव फैडरेलिज्म के कारण से दूसरे राज्य जो निवेश आकर्षित करना चाहते थे उनको तो हरियाणा के 5 लाख 84 हजार करोड़ रुपये के एम.ओ.यू. से थोड़ी बहुत जलन हो सकती है लेकिन विपक्ष के साथियों को वह नहीं हो सकती, ऐसा मुझे विश्वास है। विपक्ष के साथियों के मन में खुशी होगी। (विघ्न) विपक्ष के साथी तो जो विकास का रथ हम हरियाणा में लेकर चलें हैं उसका एक महत्वूपर्ण पहिया हैं। सत्तापक्ष और विपक्ष मिलकर काम करेगा तभी हम अपने प्रिय प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ा सकेंगे और राज्य को 50वें वर्ष में सही मायने में स्वर्णीम बना पायेंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी मैं कई बार कहता हूं कि हम सब लोग तो हरियाणा की वैदिक संस्कृति के लोग हैं-

ओम समय गच्छताम् सम वद्धम, संभो मनासि जानताम्,
देवा भागम यथा पूजते, सम भवामी पूजते।

प्रेम से मिलकर चलो और बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति मिल करके कर्तव्यों के मानी बनों। उपाध्यक्ष महोदया, हम तो मिलकर चलने वाले सिद्धांतों के लोग हैं। इसी तरह से मेडिकल एजुकेशन की चिंता व्यक्त की गई जो कि जायज चिंता है। कहा गया कि मैडीकल कॉलेज खोलने का नाम तो पांच का ले दिया और बजट कम रखा गया है। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि 280 प्रतिशत बजट बढ़ाया गया है। ये मैडीकल कॉलेज एक साल में बनकर खड़े नहीं होते हैं। सरकारें निरंतरता में योजनाएं करती हैं और उनका क्रियान्वयन करती हैं। कॉलेज बनाने के हर साल के फेजिज और स्टेजिज तय होते हैं कि किस-किस स्टेज पर क्या-क्या निर्माण होगा और उसी अनुसार बजट की व्यवस्था की जाती है। डाक्टर कमल गुप्ता जी की मुझे चिंता रहती है। वे कहते हैं कि हिसार में अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना है और कहा कि बजट का प्रोविजन केवल 80 करोड़ रुपये का किया गया है। यह तो निरंतरता का विषय है जैसे जैसे काम होता जायेगा पैसा बढ़ता जायेगा। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भी योजनायें सरकार द्वारा बनाई जाती हैं वे लॉग टर्म के हिसाब से बनाई जाती हैं। ऐसे ही बहुत सारी योजनायें ऐसी भी होती हैं कि उनमें सिर्फ टोकन प्रॉविज़न किया जाता है अर्थात जब तक उसका अनुमान नहीं बनता तब तक टोकन प्रॉविज़न करके उसका हैड खोल लिया जाये और आने वाले समय में जैसी भी आवश्यकता हो उसके खर्च की व्यवस्था कर दी जाये। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, यहां पर जो

किसानों की फसलों के प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए खराबे के लिए हमारी सरकार द्वारा मुआवज़ा दिया गया उसकी काफी चर्चा हुई।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, हमने चर्चा के दौरान एक विषय यह भी सरकार के ध्यान में लाया था कि फरीदाबाद में एक मैडीकल कॉलेज के संस्थापक द्वारा अपना मैडीकल कॉलेज बंद करके 400 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके भागने की बात की थी। आपने इस विषय के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : उपाध्यक्ष महोदया, विपक्ष के नेता ने जो फरीदाबाद के मैडीकल कॉलेज का विषय उठाया है। मेरे पास इस मैडीकल कॉलेज के विद्यार्थी आये थे। यह मामला बहुत गम्भीर था कि पहले तो कुछ लोग मैडीकल कॉलेज खोल लेते हैं और फिर उसको बंद करके भाग जाते हैं। इस केस में जो वहां पर 400 बच्चे इंटरनरशिप कर रहे थे उनका क्या होगा ? यह बहुत गम्भीर बात है but we have taken cognizance. मैंने अपने डिपार्टमैंट की टीम वहां पर भेजी थी उस टीम ने मुझे वहां की रिपोर्ट दी है। जहां तक उन बच्चों के भविष्य का सवाल है हमने उन सभी बच्चों को दूसरे मैडीकल कॉलेजिज में एकोमोडेट करवाने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। सभी नियरबाई कॉलेजिज से यह जानकारी हासिल की जा रही है कि किस-किस मैडीकल कॉलेज में कितने-कितने बच्चे एडजस्ट हो सकते हैं। इसके लिए हमें केन्द्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है और इस परमिशन के लिए हमने केन्द्र सरकार को पत्र लिख दिया है। जिसमें हमने वास्तविक स्थिति का वर्णन करते हुए उनसे हमें आवश्यक परमिशन देने का आग्रह किया है। इसके साथ ही मैंने यह भी अपने विभाग से पूछ लिया है कि अगर कोई कॉलेज ऐसे बंद करके भाग जाता है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है तो ऐसे कॉलेज के साथ सख्त से सख्त क्या कार्यवाही हो सकती है। मैंने अपने विभाग से यह कहा है कि यह भी मुझे बताया जाये और आइंदा ऐसा कोई न करे जब भी किसी नये मैडीकल कॉलेज को खोलने की इजाज़त दी जाये उसमें कुछ ऐसी कंडीशंज़ डाली जायें और कुछ ऐसा बॉण्ड उनसे लिया जाये कि अगर वे कल को उसको बंद करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहें तो उसको रिकूप किया जा सके। इस पकार से हमने इसके बारे में विस्तारपूर्वक विचार किया है।

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया जी, माननीय नेता प्रति पक्ष ने एक और बड़ी गम्भीर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने यह कहा था कि जब टोटल जी.डी.पी. का कैपीटल एक्सपैंडीचर मात्र 1.5 प्रतिशत होगा तो विकास कैसे होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि कैपीटल एक्सपैंडीचर विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपके माध्यम से इस महान सदन में यह जानकारी देना चाहूंगा कि हम तो इस कैपीटल एक्सपैंडीचर को बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत के स्तर पर लाये हैं लेकिन जब माननीय नेता प्रतिपक्ष की पार्टी हरियाणा प्रदेश में सत्तासीन थी तो उस समय जो Capital Expenditure as percentage of Gross Domestic Product था वह 1.15 परसैंट था जिसको हमने बढ़ाकर 1.5 परसैंट किया है। दूसरी बात किसानों को उनकी फसल के खराबे का मुआवज़ा देने की थी। बार-बार यहां पर यह बात कही गई कि इतना कुछ देने के बाद भी यह सब पर्याप्त नहीं था। हमने सिद्धान्तत : इस बात को स्वीकार किया है। आज हमारे प्रदेश का किसान आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। कृषि अर्थव्यवस्था पर आज बहुत दबाव है और कृषि अर्थव्यवस्था में आज आमदनी को बढ़ाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि कृषि और कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था पर हमारे प्रदेश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आश्रित है। हमारे प्रदेश का

[कैप्टन अभिमन्यु]

जो सामाजिक और राजनीतिक असंतोष उत्पन्न होता है यह कहीं न कहीं कृषि अर्थव्यवस्था की जर्जर हालात से जुड़ा हुआ विषय है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने किसान के दर्द को समझा और जब-जब किसान के ऊपर संकट आया हमने उसको ज्यादा से ज्यादा मुआवज़ा देकर उस संकट से उबारने का काम किया। जो भी सुझाव सदन के किसी भी माननीय सदस्य की तरफ से हमें प्राप्त हुआ हमने उसको स्वीकार किया और उसके ऊपर कार्रवाई की। मैंने यहां पर यह वायदा किया था कि सदन के पटल पर मैं एक जानकारी रखूंगा जिसमें यह स्पष्ट किया जायेगा कि पिछले 15-16 वर्षों में हरियाणा प्रदेश में किस-किस पार्टी की सरकार के समय किसानों को उनकी किस-किस फसल के कितने-कितने प्रतिशत के नुक्सान का कितना-कितना मुआवज़ा दिया। यह जानकारी मैंने सदन के पटल पर रखी भी है जोकि सभी माननीय सदस्यों के पास पहुंच चुकी है। उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 1999 से वर्ष 2004-05 के काल खण्ड में प्राकृतिक आपदाओं और प्राकृतिक प्रकोप के कारण किसान पर संकट आये कुल मिला करके 6 साल के कार्यकाल में 260 करोड़ रुपये का मुआवज़ा किसानों को दिया गया है जिसकी एवरेज़ 40 से 45 करोड़ रुपये प्रति वर्ष आती है।

श्री अभय सिंह चौटाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, माननीय मंत्री जी इसके साथ-साथ यह जानकारी भी दें कि उस समय कौन-कौन सी प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की फसलों का नुक्सान हुआ था जिनके मुआवज़े की वे बात कर रहे हैं।

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया जी, यह जानकारी मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को अलग से उपलब्ध करवा सकता हूं। मैंने एक कागज और सदन के पटल पर रखा था वह यह था कि पिछली सरकारों द्वारा किस दर से मुआवजा दिया जा रहा था, वह 1000/-रुपये और 1250/- रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाता था जिसको बढ़ा कर हमने 12 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदया, यह इतिहास की बात है कि हम जिस दौर से गुजरे हैं या गुजरने वाले हैं। उस समय 10 वर्ष तक प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है तथा उन्होंने किसानों की हितैषी सरकार होने की बात कही है। मैं उनके समय की बात बताना चाहता हूँ। जब-जब किसानों पर प्रकृति की मार पड़ी तो उन्होंने 10 साल में कुल 925 करोड़ रुपये मुआवजा किसानों को दिया यानि साल का 92.5 करोड़ रुपये औसत मुआवजा दिया गया है। इसके ठीक विपरीत हमारी सरकार ने एक साल में अढाई हजार करोड़ रुपये मुआवजा दिया है। (इस समय मेजें थपथपाई गई) उपाध्यक्ष महोदया, हमने केवल मुआवजा नहीं दिया बल्कि हमने मिनिमम प्रति एकड़ मुआवजे की राशि भी बढ़ाई है। पहले किसानों को 2-2, 5-5 रुपये के चैक दिये जाते थे जिसको देख कर किसान माथा पीटते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा कि कम से कम मुआवजे का चैक 500/- रुपये का होना चाहिए यानि 500 रुपये से नीचे कोई चैक नहीं होना चाहिए। उसी बात पर अमल करते हुये हमने मिनिमम 500 रुपये प्रति किसान मुआवजा देने की नीति पर काम किया है। हमने केवल मुआवजा ही नहीं दिया बल्कि उस अवधि के बिजली के बिल भी हमने माफ किये हैं तथा उस समय का किसानों का ब्याज भी माफ किया है तथा उनकी रिकवरी को डैफर करने का काम किया है। हमने किसानों का गन्ना भी खरीदा है। मैंने बजट पर चर्चा के दौरान भी इस बात की चर्चा की थी कि हमने गन्ना किसानों के लाभ के लिए कितना काम किया है तो मैं कहना चाहूँगा कि हमने तो पिछली सरकार का 270 करोड़ रुपये बकाया भी

किसानों को दिया है। किसानों से लेकर खिलाड़ियों तक पिछली सरकार जितना भी बकाया छोड़ कर गई थी वह हमने सभी का बकाया दिया है। (विघ्न) इसी प्रकार से हमने 1509 किस्म की धान की खरीद भी की है। जहाँ तक धान के रेट की बात है तो यह ऊपर-नीचे पहले भी हुये हैं लेकिन सरकार ने हिम्मत की और एक बोल्ड फैसला लेकर, अपनी तरफ से इन्टरवीन करके सदनीयत के साथ उसको खरीदने के लिए सरकार आगे आई। इस मामले में जो पत्र उपलब्ध करवाया है वह मैं सदन के पटल पर रखता हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा जनहित कांग्रेस की विधायक श्रीमती रेणुका बिश्नोई इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं उन्होंने सदन में आवाज उठाई थी कि उनके विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्यों पर धन खर्च नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि नारनौंद में 2 करोड़ रुपये विकास कार्यों पर खर्च किये गये जबकि हांसी में केवल 17 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि यह सरकार "सबका साथ सबका विकास" और "हरियाणा एक हरियाणवी एक" की नीति पर कार्य कर रही है। उपाध्यक्ष महोदया, वर्ष 2015-16 में हिसार का डी-प्लान का 11 करोड़ रूपया था जिसमें से नारनौंद में अगर 2 करोड़ 11 लाख रुपये विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च किये गये हैं तो हांसी में भी 1 करोड़ 11 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। इसी तरह से हिसार में 2 करोड़ 11 लाख रुपये दिये गये तथा हमारे साथी श्री अनूप धानक के विधान सभा क्षेत्र के लिए भी 1 करोड़ 80 लाख रुपये की ग्रांट डी-प्लान के तहत दी गई है। नलवा विधान सभा क्षेत्र के लिए 1 करोड़ 34 लाख रुपये तथा बरवाला के लिए 1 करोड़ 42 लाख रुपये की ग्रांट दी गई है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया, बजट पर हरियाणा जनहित कांग्रेस की विधायक श्रीमती रेणुका बिश्नोई ने जो चर्चा की थी उसका जवाब देना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। अगर माननीय सदस्या आंकड़े देख लेती तो शायद मुझे जवाब भी नहीं देना पड़ता और सदन का समय भी बच जाता। उपाध्यक्ष महोदया, मै हैपनिंग हरियाणा की थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। हालांकि वह बजट से अलग विषय है लेकिन निश्चित तौर पर बजट पर उसका प्रभाव पड़ता है तो उसको लेकर चिन्ताएं हुई कि ये सफल होगा या नहीं होगा जिस संबंध में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम इसके बारे में आपसे एक साल बाद बात करेंगे। हमने कहा ठीक है उनका काम है ऐज ए वाच डॉग ऑफ डैमोक्रेसी कि सरकार पर पैनी नजर रखना निगाह रखना, सरकार को समय-समय पर चेताना और उस नाते से हम उनकी इस भूमिका को सम्मान और आदर के साथ स्वीकार करते हैं। आज जो ये एम.ओ.यूज. हुए हैं इसका तो पूरे सदन ने स्वागत भी किया है और हरियाणा में निवेश लगने की सम्भावना भी बनी है। पहले हरियाणा प्रदेश में जो वातावरण होता था उससे मैनुफैक्चरिंग सैक्टर इण्डस्ट्रीज में बढ़ने की बजाए घट रहा था। इसकी प्रगति रूक रही थी घट रही थी। जब हम इसके अतीत में गये तो इसका डायग्नोसिस इन्टरपराइजिज प्रमोशन पोलिसी बनाते हुए बहुत सारी बातें सामने आई कि पहले सरकार का और प्रशासन का रवैया क्या था ? पिछले 10 साल क्या खेल चला अगर कोई निवेश करने आ जाता था तो उससे अपना हिस्सा मांगा जाता था, उससे पहले यह पूछते थे कि इसमें हमें क्या मिलेगा ? इस सोच के साथ वह 10 साल निकाल गये। उस समय भ्रष्टाचार का बोलबाला था। लेकिन आज वह सदन में नहीं आए जोकि उनको आना चाहिए था। पिछली सरकारों की श्रमिक असंतोष, कानून व्यवस्था की लचर स्थिति और वादा तोड़ नीति थी। किसी उद्योगपति को ले आए कि आपको ये छूट देंगे और उसने यहां आकर निवेश कर दिया और उसके बाद उसको कोई छूट नहीं मिली। अब हमारे पास वह उद्योगपति आए और उन्होंने कहा कि हमें छूट का वायदा दिया है। अब हमने फैक्ट्रियां लगा ली हैं सैंकड़ो हजारों करोड़ों रुपये

[कैप्टन अभिमन्यु]

लगा लिये हैं और ये हमारा बकाया बनता है तो हमारी सरकार ने कोई न कोई पेंच लगाकर उनको भी रोका है। ऐसे वातावरण में जो निवेश बाहर जा रहा था उसको सुधारते हुए हमने ये हैपनिंग हरियाणा सम्मिट से पहले इंटरपराइजिज प्रमोशन पोलिसी चालू की और पूरे वातावरण को सही बनाया जिससे प्रदेश भर में एक नया वातावरण बना है और हरियाणा में एक संस्कार परिवर्तन हुआ है। हरियाणा की सरकार मुख्यमंत्री से लेकर कर्मचारी तक एक पोजीटिव फ्रेम ऑफ माईंड में आई है और अब वह अपने बिजनेस पर काम कर रही है। हर प्रकार के प्रोसीजर को सरल किया जा रहा है। हमें बड़ी खुशी हुई जब सदन में विपक्ष के नेता ने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया है, जिसमें उन्होंने अपना अनुभव सांझा किया कि जो एग्रीकल्चर सब्सिडी हैं उसकी प्रक्रिया का सरलीकरण करना चाहिए। यह एक बहुत अच्छा सुझाव है जहां पर नागरिक के साथ कोई सरकार काम करती है तो उसमें प्रक्रियाओं को सरल करना बहुत जरूरी है। हमने उद्योग के क्षेत्र में काफी काम इसी स्तर पर किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जो सुझाव दिया है उससे काफी सुधार होगा। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में भी हम हर प्रकार की प्रक्रियाओं को सरल करने का काम करेंगे। एक चिन्ता की गई जिसमें यूनिटैक का नाम आया कि उसके साथ एम.ओ.यू. कर लिया। यह जानकारी पता नहीं कहां से आई लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यूनिटैक के साथ हरियाणा सरकार का कोई एम.ओ.यू. साईन नहीं हुआ है। मैं और किसी व्यक्ति की यहां चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि जो एम.ओ.यूज. हैं वह किसी को हतोत्साहित करने के लिए नहीं हैं अगर कोई निवेशक आता है तो हम इन सब चीजों की समीक्षा करेंगे कि उसके एम.ओ.यू. को कैसे आगे बढ़ाना हैं और निवेशक उसमें कैसे फंडिंग फाईनैंसिंग करके लाना चाहता है। क्या प्रोजैक्ट करना चाहता है। हम हर चीज को पारदर्शी ढ़ंग से करेंगे और हर चीज को ओपन और ट्रांसपेरेंस ढ़ंग से करेंगे। मैं यह महान सदन को निश्चित तौर पर विश्वास दिलाता हूं। माननीय विपक्ष के नेता ने एक चिन्ता व्यक्त की कि उबर के साथ समझौता हुआ है तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि उबर एक इंटरनेशनल टैक्सी कंपनी है जिसके बारे में इन्होंने कहा कि उनकी तो एक भी गाड़ी नहीं है एसैट्स नहीं हैं। क्या यही उनका बिजनस मॉडल है ? अब फेसबुक दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन वह कंटेन्ट ऑन नहीं करती है। गुगल इतनी बड़ी कंपनी है पर वह भी कंटेन्ट ऑन नहीं करती है। यह दुनिया का नया बिजनेस मॉडल है। उबर दुनिया की एक बड़ी टैक्सी कंपनी है वह भी टैक्सी ऑन नहीं करता तो वह उसका बिजनेस मॉडल है। अगर वह हरियाणा में आती है तो जो उन्होंने 40 करोड़ रुपये का मिनिमम निवेश प्रस्तावित किया है तो वह एक बहुत बड़ा निवेश नहीं है। लेकिन उसमें हरियाणा के युवाओं को स्वरोजगार की संभावनाओं पर उसे बढ़ाने में इजाफा करने में हरियाणा सरकार सहयोग कर रही है। एक चिन्ता व्यक्त की कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रैस-वे की जिसका श्रय लेने की बड़ी होड़ है कि हमने बनाया, उसने बनाया, हमने रखा पत्थर, उसने रखा पत्थर। इतिहास यह नहीं देखेगा कि पत्थर किसने रखा है। इतिहास तो यह देखेगा कि उसको मुकम्मल किसने किया और उसको अन्जाम तक कौन लेकर गया। यह हरियाणा की जीवन रेखा है दिल्ली जो एन.सी.आर. क्षेत्र है दिल्ली को प्रदुषण मुक्त करने के लिए, दिल्ली को भीड़ मुक्त करने के लिए और आवागमन की सुविधा दिल्ली के बॉईपास होकर निकल जाए। हजारों-हजारों ट्रक रोजाना दिल्ली से न गुजर कर बाहर से निकल जाए और बाहर जो चीज कई सालों तक बन जानी चाहिए थी वह नहीं बनी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। उस प्रोजैक्ट को हिम्मत व हौंसले के साथ हमारी

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड लिया तथा इसी मामले पर पहले से ही बनी एक बड़ी कमेटी द्वारा अलग स्टैंड लेकर कहा कि हम कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रैस हाईवे बनायेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सरकार से कहा कि आप इस कार्य की समय सीमा तय करके बतायें। हमारी सरकार ने इस प्रोजैक्ट के लिए समय सीमा तय करने का बोल्ड फैसला लिया और कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रैस हाईवे को दो सैक्शन में विभाजित कर दिया। पहले सैक्शन के तहत मानेसर व पलवल एक्सप्रैस हाईवे को इ.पी.सी. के माध्यम से सरकार के खर्चे पर बनाने का काम किया गया और दूसरे सैक्शन में मानेसर से कुंडली तक एक्सप्रैस हाईवे को बी.ओ.टी एन्युटी बेसिज पर आगे टैंडर कर दिया गया। पहले पहल इसको यह चार मार्गीय बनाने का प्रावधान था लेकिन हमारी सरकार ने इसको सिक्स लेन बनाने का फैंसला लिया है और इस ऐतिहासिक फैसले के बारे में बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मानेसर-पलवल सैक्शन बनकर तैयार हो गया है और 5 अप्रैल को माननीय केन्द्रीय जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गड़करी जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। (इस समय मेजें थपथपाई गई) यह कार्य मात्र सरकार के शुद्ध संकल्प के आधार पर पूर्ण हो पाया है। इसके अतिरिक्त बजट चर्चा के दौरान हमारे माननीय सदस्यों ने जो विभिन्न विषयों पर ध्यान आकर्षित किया था, मैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं समझता हूँ कि इस प्रक्रिया में शायद ही कुछ ऐसे बिन्दू शेष रह जायेंगे जो मेरी जवाबी प्रक्रिया में कवर न हो पायें। ऐसा करके निश्चित रूप से सदन का समय भी बचाया जा सकेगा और मैं अपने धर्म के साथ न्याय भी कर पाउंगा। श्री रामचन्द कम्बोज जी ने कहा था कि 300 करोड़ रुपये फसल बीमा योजना के लिए पर्याप्त नहीं हैं। मैनें इससे जुड़ी कुछ बातों का उसी समय जवाब दे दिया था और उन सबके अतिरिक्त में श्री रामचन्द कम्बोज जी को यह भी बताना चाहूँगा कि हमने बजट में यह भी प्रोविजन किया है कि यदि भविष्य में ज्यादा राशि की आवश्यकता पड़ेगी और जितना जरूरी होगा हम इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है और निश्चित तौर से इसमें अपनी हिस्सेदारी देंगे। (इस समय मेजें थपथपाई गई) श्री परमिन्दर सिंह ढुल ने कहा था कि सरकार की नियत, नीति और नजर स्पष्ट नहीं है। मैं उनसे विनती करता हूँ कि यदि वह अपना चश्मा उतारकर देखेंगे तो सब कुछ स्पष्ट दिख जायेगा। (विघ्न)

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : उपाध्यक्ष महोदया, यदि मैने चश्मा उतार लिया तो मुझे वित्त मंत्री जी भी दिखाई नहीं देंगे। (हंसी एवं शोर)

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, यदि अन्दर की आंखे खोलकर देखेंगे तो भी देखा जा सकता है। हमारी सरकार की नीयत, नीति और नजर दूरदृष्टि की है और ढुल साहब का चश्मा शायद नजदीक का है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, ढुल साहब की बात में भी दम है कि उन्होंने चश्मा उतार लिया तो वित्त मंत्री जी दिखाई नहीं देंगे। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, तभी तो मैंने भी उनको विकल्प दिया है कि अन्दर की आंखों का प्रयोग करेंगे तो सरकार की दूरदृष्टि साफ तौर से दिख जायेगी। (विघ्न)

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं बस एक मिनट के लिए माननीय मंत्री जी को इंट्रप्ट कर रहा हूँ। मैंने माननीय मंत्री जी को किसान के मुआवजे का अधिकार प्राप्त करने संबंधी एक सुझाव दिया था उस पर माननीय मंत्री जी की चर्चा नहीं आई है।

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, जो बातें रह जायेंगी, उन सभी बातों का सभी संबंधित माननीय सदस्यों को बहुत खुशी के साथ जवाब दिया जायेगा। हमारे जनप्रतिनिधि इतने काबिल, योग्य तथा सक्षम लोग है यदि यह सरकार को अपना काम अच्छे ढंग से करने में सहयोग देते हैं तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। हम निश्चित तौर से हर सुझाव का स्वागत करेंगे तथा हर सहीं सुझाव पर अमल करने की कोशिश की जायेगी। इस सदन का प्रत्येक सदस्य इस सदन में अपने विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अपने विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं को इस महान सदन में उठाना प्रत्येक सदस्य का मुख्य दायित्व है। इसी परिपेक्ष्य में विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों की समस्याओं को सदन में रखा गया है। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के कुछ मुख्य विषय होते हैं। उन सभी पर तत्काल मेरे द्वारा सदन में उत्तर देना प्रैक्टिकल नहीं होगा लेकिन यदि कोई अलग से चर्चा करना चाहता है तो मैं हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहूँगा। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूँ कि उनके सभी सुझावों को नोट कर लिया गया है। इसी परिपाटी में मैं बताना चाहूँगा कि श्री विपुल गोयल जी ने फरीदाबाद के प्रसिद्ध मेहन्दी उद्योग से संबंधित एक सुझाव दिया था। वह महेन्दी उद्योग के लिए पिछले काफी लम्बे समय से प्रयासरत भी रहे हैं। यहां पर मैं उस मेहन्दी की बात कर रहा हूँ जो हाथ पर रचाने वाली होती है, पूजा-पाठ में प्रयोग की जाती है तथा पत्ते या पाउडर के रूप में जो प्योर मेहन्दी प्रयोग की जाती है। कैमिकल ट्रीटमैंट वाली मेहन्दी की यहां पर बात नहीं की जा रही है। (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : उपाध्यक्ष महोदया, प्योर मेहन्दी को हिना भी कह सकते हैं?

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, आजकल कैमिकल ट्रीटमैंट वाली मेहन्दी को भी हिना कह दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो प्रोसैस्ड मेहन्दी है जिसमें कैमिकल मिलाने के बाद काली मेहन्दी का नाम दे दिया जाता है, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। मेहन्दी कृषि से जुड़ा हुआ व्यवसाय है और फरीदाबाद में इस व्यवसाय के साथ लगभग दस हजार लोग जुड़े हुए हैं। श्री विपुल गोयल ने सुझाव दिया था कि हरियाणा प्रदेश के आस-पास के राज्यों में मेहन्दी उद्योग पर कोई टैक्स नहीं है। उनके इस सुझाव को बहुत गम्भीरता से लिया गया है इस दिशा में विभाग द्वारा काम किया जा रहा है और निश्चित तौर पर जैसे ही उसका एग्जामिनेशन पूरा होगा तो मैं विपुल गोयल जी को भी आश्वासन देता हूँ कि हरियाणा की जनता के हित में 10 हजार लोगों के रोजगार के हित में, किसान और कृषि से जुड़े हुए एक ट्रेड के हित में हम इसको वैट मुक्त करने का विचार करेंगे। उपाध्यक्ष महोदया, मार्किट लोनज़ की जहां तक बात आई है, मैंने पहले भी सदन में बताया है कि डैट लॉयबिलीटिज सीमा में है और पूरी तरह से उन मर्यादों में रह कर ही काम कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने बजट पर माननीय सदस्यों की इतनी चर्चाएं करवाई हैं, मुझे लगता है कि जवाब देने के लिए बजट दोबारा से पेश करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदया, यदि मैं किसी भी माननीय सदस्य का जवाब नहीं दे पाया तो मैं क्षमा याचना चाहूँगा और व्यक्तिगत तौर पर हर बात का जवाब देने के लिए उपलब्ध रहूँगा। उपाध्यक्ष महोदया, एक माननीय सदस्य ने कुण्डली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे के बारे में चिंता व्यक्त की थी कि डी.एम.आई.सी. (Delhi Mumbai Industrial Corridor) लम्बे समय से साईन हुआ था,

माननीय प्रतिपक्ष नेता ने कहा था कि यह तो बहुत पहले साईन हुआ था आज जमीन भी एक्वायर नहीं हुई है, यह बात बिल्कुल सही है। यह भारत सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना थी। जिसको अब तक क्रियान्वयन में आ जाना चाहिए था। हरियाणा के लोगों के लिए यदि यहां उद्योग और फैक्टरी लगती है तो लोगों के लिए अच्छे रोजगार और प्रदेश के विकास की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन तमाम प्रकार के अवरोधो और दिक्कतों के बावजूद वर्ष 2014 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सरकार बनने के बाद तीन हजार एकड़ भूमि को ऐक्वीजीशन ना करने का बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया था क्योंकि किसानों ने कहा कि हम इस ऐक्वीजीशन की प्रक्रिया के रेट के हिसाब से भूमि नहीं देंगे। यह ऐक्वीजीशन ऑफ लैंड प्रदेश सरकार और भारत सरकार के लिए बहुत जरूरी थी। मगर उपाध्यक्ष महोदया, जिस रेट की किसान मांग करते थे, उसके कारण ऐक्वीजीशन में अनवॉयबिलिटी आ जाती थी। इसलिए भारत सरकार ऐक्वीजीशन करने के लिए सहमत नहीं थी। इसी कारण माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भूमि पुत्रों के हित में उस जमीन को ऐक्वीजीशन ना करके उसको छोड़ने का फैसला किया था, जोकि पिछली सरकार के चरित्र के बिल्कुल ही विरूद्ध है। उपाध्यक्ष महोदया, पिछली सरकार जबरदस्ती से एक्वीजिशन किया करती थी। हमारी सरकार ने नया इनीशियेटिव नई पहल करके एक नई योजना बनाई है। इस योजना में जहां पर किसान अपनी भूमि देना चाहते हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को साथ लेकर किसानों की जमीन लेने के लिए बातचीत करते हैं। इस तरह से सरकार को लगभग 1200-1300 एकड़ भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उसमें आगे बढ़ने की दिशा में भारत सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया है। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में यह योजना अभी फलीभूत होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वर्ष 2016-17 में इस योजना पर काम प्रारम्भ हो जायेगा। उपाध्यक्ष महोदया, एक बात का जवाब देने के लिए मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि साल भर पहले भी यह विषय आया था और कहा गया था कि सरकार ने टैक्स रेट तो बढ़ाए नहीं हैं। सरकार साल के बीच में या साल के बाद टैक्स रेट बढ़ा देगी। जहां तक पैट्रोल डीजल की बात है, पैट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाने का फैसला कारपोरेशन का था, यह बजट के बाहर का विषय है।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, जब टैक्स बढ़ाने हो तो कारपोरेशन का नाम दिया जाता है।

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, इस साल हमने पूरी जिम्मेवारी का परिचय दिया है कि जब पिछली बार बजट पेश हुआ था तो विपक्ष के बहुत सारे माननीय सदस्यों ने और कांग्रेस पार्टी की नेता श्रीमती किरण चौधरी ने शेर सुनाकर कहा था कि घोषणाएं तो बहुत अच्छी है, बजट के आंकड़े तो बहुत अच्छे हैं पर इसके लिए पैसा कहां से लाएंगे? उपाध्यक्ष महोदया, मैं बड़ी जिम्मेदारी से सदन में कहता हूँ कि पैट्रोल और डीजल के रेट अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर घटने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर जो कीमतें घटी हैं उसके कारण आज भी पैट्रोल और डीजल 17 और 12 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पिछले डेढ़ साल के रेट से कम है। ऐसे में राज्य के राजस्व के घटने की एक जबर्दस्त स्थिति उत्पन्न हो सकती थी लेकिन हमने दो सिद्धांतों को अपनाया है। पहले सिद्धांत के अनुसार आम उपभोक्ता को लाभ ट्रांसफर होना चाहिए जिसमें हम इनफ्रींज नहीं करेंगे। हमने उनको 12 और 17 रुपये का लाभ पहुंचाया है तथा अपने राजस्व को सुरक्षित रखने के लिए आसपास के राज्यों दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश,

[कैप्टन अभिमन्यु]

उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड की सरकारों के साथ मीटिंग करके उनकी तुलना की ताकि हमारी वैट की दरें ज्यादा न हो और उपभोक्ता को भी सहज लगे। आज मुझे सदन में यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा में आसपास के सभी राज्यों से पैट्रोल और डीजल की कीमतें सबसे कम हैं। हम राज्य के हित में कोऑपरेटिव फैडरलिजम पर आगे बढ़ रहे हैं और हम फिसकल डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और रेवेन्यु डेफिसिट आदि सभी डेफिसिट्स को घटाकर प्रदेश के रिसोर्सिज को बढ़ाना चाहते हैं। हमने श्वेत-पत्र में भी कहा था कि अगर प्रदेश के अपने साधन-स्त्रोत बढ़ेंगे तो हमें कम कर्ज लेना पड़ेगा। हमने सिर्फ उनको मेनटेन करने की कोशिश की है। मेरे पास सभी राज्यों के वैट रेट हैं लेकिन मैं उनकी बात नहीं करना चाहता हूं। मैंने इसे बताने का अपना कर्तव्य समझते हुए इन बातों को आप सभी के सामने रखा है। उपाध्यक्ष महोदया, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार संकल्पबद्ध है कि हरियाणा प्रदेश में अर्थव्यवस्था का निरंतर विकास हो और हरियाणा तरक्की के रास्ते पर बढ़ता रहे। मैं इसी की कल्पना और संकल्प करते हुए आपके माध्यम से एक वैदिक विचार का उल्लेख करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा -

'हे परमपिता, तुम शक्तिशाली हो, तुम सृष्टि का निर्माण करते हो,
तुम धन की वृष्टि हम सब पर करो।'

इसके बाद मैं आप सब सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि इस बजट के अनुमानों को पास और पारित किया जाए। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, बजट पारित करने के लिए मैं पूरे सदन का धन्यवाद करता हूँ।

बैठक का समय बढ़ाना

उपाध्यक्ष महोदया : अगर हाउस की सहमति हो तो बैठक का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : हाँ जी।

उपाध्यक्ष महोदया : ठीक है, बैठक का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

14.00 बजे **श्रीमती बिमला चौधरी (पटौदी)** : उपाध्यक्ष महोदया, हमारे पटौदी विधान सभा क्षेत्र में पिछले सालों का 26 करोड़ रुपये का मुआवजा पैंडिंग पड़ा है इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि यह मुआवजा कब तक दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा?

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं अपनी आदरणीय बहन बिमला चौधरी जी को बताना चाहता हूं कि पिछली बार की सरकारों के मुआवजे इस सरकार ने बांटे हैं जिससे पूरे हरियाणा के किसानों में संतुष्टि का भाव है। बहन बिमला चौधरी जी ने पिछले दो महीनों में एक दो बार इस बारे में बात की है इसलिए उनकी पटौदी क्षेत्र की यह बात मुख्यमंत्री जी के और वित्त मंत्री महोदय जी के संज्ञान में है और जल्दी ही उसका समाधान निकाला जाएगा।

श्रीमती बिमला चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलवाते हुए कहना चाहूंगी कि मुआवजे के जो चैक दिए गए थे वे बाउंस हुए पड़े हैं इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हमारे यहां के लोगों के मुआवजे के पैसे दिए जाएं। (विघ्न)

श्री रामबिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, पिछली सरकार द्वारा अनांउस किया गया 270 करोड़ रुपये का मुआवजा हमने दिया है और 1100 करोड़ रुपये का मुआवजा और भी हमने दिया है।

वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा तथा मतदान

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2016-2017 के लिए बजट अनुदानों तथा मांगों पर चर्चा तथा मतदान होगा।

पिछली प्रथा अनुसार और सदन का समय बचाने के लिए ऑर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांड्ज एक-साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जाएंगी। माननीय सदस्यगण, किसी भी डिमांड पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन जिस डिमांड पर वे बोलना चाहते हैं उसका नाम बताना आवश्यक होगा।

कुछ सदस्यों के द्वारा निम्न डिमांड्स पर बोलने की रिक्वेस्ट आई हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं - श्री केहर सिंह डिमांड नं. 24, 38, श्री रविन्द्र बलियाला डिमांड नं. 8,9,10 श्री रणबीर गंगवा डिमांड नं. 24, श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया डिमांड नं. 35, 45, श्री ओमप्रकाश बरवा डिमांड नं. 24, श्री रामचंद कम्बोज डिमांड नं. 8, 9, 21, 24, 38, 41, श्री परमिन्दर सिंह ढुल डिमांड नं. 3, 11, 12 और 27, श्री वेद नारंग डिमांड नं. 29, 38, श्री अनूप धानक 9, 11, श्री हरिचंद मिड्ढा डिमांड नं. 13, 24, 38, श्री पिरथी सिंह डिमांड नं. 19, श्री राजदीप फौगाट डिमांड नं.11, श्री मक्खन लाल सिंगला डिमांड नं. 4 और श्री जाकिर हुसैन डिमांड नं.13, 14, 24, 26, 27, 32, 36। हर सदस्य डिमांड पर केवल 2 मिनट तक बोलेगा और जिस डिमांड पर वे बोलना चाहते हैं केवल उसी पर ही बोलने की कृपा करें।

कि राज्स्व खर्च के लिए 69,72,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. के 1-विधान सभा के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 122,34,00,000 रुपये से अनाधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 2-राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 244,23,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 3-सामान्य प्रशासन के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 1069,65,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 4-राजस्व के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 204,84,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 5-आबकारी व कराधान के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 5713,95,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 6-वित्त के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 455,61,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 7-आयोजना एवं सांख्यिकी के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 1344,46,70,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 3609,08,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 8-भवन तथा सड़के के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 12865,21,44,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 6,81,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 9-शिक्षा के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 421,42,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 10-तकनीकि शिक्षा के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 313,13,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 11-खेलकूद तथा युवा कल्याण के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 13,83,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 12-कला एवं संस्कृति के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 3338,68,94,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च 510,00,00,000 से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 13-स्वास्थ्य के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 97,19,80,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 14-नगर विकास के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 3549,11,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 15-स्थानीय शासन के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 52,54,15,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 2,00,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 16-श्रम के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 70,71,80,000 रुपये अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 17-रोजगार के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 278,37,35,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 47,00,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 18-औद्योगिक प्रशिक्षण के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 662,52,00,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 11,55,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 19-अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण के अधीन व्ययों के बारे मेंवर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 4199,94,33,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 92,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 1096,79,50,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 110,70,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 21-महिला एवं बाल विकास के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 94,19,39,000 रुपये अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 22-भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 368,19,12,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 9843,87,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 23-खाद्य एवं आपूर्ति के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 1867,31,68,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 655,50,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 24-सिंचाई के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 706,73,43,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 5,02,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 25-उद्योग के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 13,85,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 26-खान एवं भू-विज्ञान के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 1937,04,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 27-कृषि के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 716,29,00,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 15,00,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 28-पशुपालन एवं डेरी विकास के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 47,76,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 29-मछली पालन के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 382,32,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 30-वन एवं वन्य प्राणी के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 8,60,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 31-परिस्थिति विज्ञान एवं पर्यावरण के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 3070,22,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 220,64,80,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 84,19,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 33-सहकारिता के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 2176,41,65,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 260,7500,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 34-परिवहन के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 2,81,40,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 66,81,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 35-पर्यटन के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 3565,70,78,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 226,40,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 36-गृह के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 50,75,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 37-निर्वाचन के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 1890,76,50,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 12,17,60,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 38-लोक स्वास्थ्य एवं जल पूर्ति के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 133,96,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 39-सूचना एवं प्रचार के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 10741,66,05,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1933,51,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 40-उर्जा तथा विद्युत के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 86,03,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 41-इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिक के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 495,37,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 42-न्याय प्रशासन के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 218,86,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 43-कारागार के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 39,39,72,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 5,80,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 44-मुद्रण एवं लेखन सामग्री के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि पूंजिगत खर्च के लिए 4729,38,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 45-राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

उपाध्यक्ष महोदया : परमिन्दर सिंह ढुल जी, आप डिमांड नं. 3 पर अपनी बात रखें।

श्री परमिन्दर सिंह ढुल(जुलाना) : उपाध्यक्ष महोदया, डिमांड नं. 3 पर मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि मेरे हल्के जुलाना को सब डिवीजन घोषित किया जाए क्योंकि यह हमारी बहुत पुरानी और लम्बित मांग है। प्रदेश में जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं उनको पंजाब के समान वेतनमान देने का काम किया जाए। विधान सभा के कर्मचारियों को भी पंजाब विधान सभा के

[श्री परमिन्द्र सिंह ढुल]

कर्मचारियों के बराबर वेतनमान दिया जाए। रिटायर्ड कर्मचारियों की बात मंत्री जी के संज्ञान में है। पंजाब के रिटायर्ड कर्मचारियों को 65,70 और 75 उम्र में वृद्धि के नियम के हिसाब से पैंशन दी जाती है लेकिन हमारे यहां इस नियम के हिसाब से पैंशन नहीं दी जाती। पंजाब में मैडीकल भत्ता 1500 रुपये दिया जाता है जबकि हमारे यहां केवल 500 रुपये मेडिकल भत्ता दिया जाता है। हमारे यहां के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए भी पंजाब की तरह 65, 70 और 75 साल की उम्र में वृद्धि का नियम रखा जाए। उपाध्यक्ष महोदया, कर्मचारियों के लिए कैशलैस बीमा योजना शुरू की जाए क्योंकि क्रोनिक डिसीजिज जैसे हार्ट अटैक और कैंसर ऐसी बीमारियां हैं जिनमें तुरंत ओपरेशन की आवश्यकता होती है इसलिए कर्मचारियों को कैशलैस बीमा की सुविधा दी जानी चाहिए।

श्री मक्खन लाल सिंगला (सिरसा) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं डिमांड संख्या 4 के बारे में कहना चाहता हूं कि इस मांग में शहरों के विकास के लिए पर्याप्त राशि प्रस्तावित की गई है, बशर्ते इस राशि का राजनैतिक नेताओं के हस्तक्षेप के कारण दुरूपयोग न हो। शहरी विकास में हरियाणा पड़ौसी राज्यों से काफी आगे है क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है और यह तीनों तरफ से दिल्ली केन्द्र की राजधानी के साथ लगता है। पिछले लगभग 11 वर्षो में शहरों का उपयुक्त विकास करवाने की बजाय प्रदेश की सरकार ने शहरी साधनों का व्यक्तिगत लाभ के लिए दोहन किया है। कांग्रेस सरकार ने गुड़गांव में बेशकीमती जमीनों को औने पौने दामों पर 'सेज' के नाम रिलांयस जैसी कम्पनियों को सौंप दिया जिन्होंने हरियाणा के शहरियों को विकास के सपने दिखाए थे। शहरों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई राशि का सदुपयोग करने के लिए सम्बन्धित योजनाओं को सही ढंग से लागू करने के लिए स्थानीय निकाय संस्थाओं का पूर्ण सहयोग लेना अति आवश्यक है और यह भी देखना आवश्यक है कि कहीं अधिकारी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए स्वीकृति राशि का दुरूपयोग न करें बल्कि प्रत्येक पैसे का लाभ शहरों में रहने वाले सभी वर्गों को मिलना चाहिए। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजन के तहत अनेक योजनाएं क्रियान्वित हैं जिनको लागू करना स्थानीय निकाय संस्थाओं का काम है जैसे कि आवसीय योजना, स्लम क्षेत्र विकास योजना जिसके लिए केन्द्र व राज्य सरकार से प्रयाप्त राशि की प्राप्ती होती है जिसका सदुपयोग किया जाए तो हर वर्ग को सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। इन योजनाओं को सही तरीक से लागू किया जाए तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए यह योजनएं अति लाभप्रद सिद्ध हो सकती हैं। इन सभी योजनाओं को लागू करने के लिए जिला स्तर से लेकर तहसील स्तर तक एक मोनिट्रिंग समिति अपनी देख रेख में केन्द्र व राज्य सरकार से प्राप्त की गई अनुदान की राशि का भी सही उपयोग करवा सकती है। मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि सिरसा शहर में सीवरेज व्यवस्था आए दिन खराब रहती है। वहां सीवर का पानी लोगों के घरों में चला जाता है। पीने के पानी की सप्लाई की जो लाईनें हैं वे बहुत कमजोर हो चुकी हैं जिसके कारण उनमें सीवरेज का पानी मिल जाता है और लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है। इसलिए पानी की सप्लाई की नई लाईनें डाली जाएं। इसके अतिरिक्त जिस कालोनी में सीवरेज व्यवस्था नहीं है उनमें सीवरेज डाला जाए और जो कालोनी अवैध हैं उनको वैध किया जाए। इस लिए उपरोक्त विवरण को देखते हुए बजट में प्रस्तावित राशि का सदुपयोग तभी हो सकता है जब हम कुप्रबंधन व्यवस्था को समाप्त करें और स्वीकृत राशि का दुरूपयोग न होने दें। (विघ्न)

श्री जाकिर हुसैन (नूँह) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं डिमांड संख्या 4 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जो राजस्व विभाग से संबंधित है। मैं मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड के बारे में अपनी बात कहना चाहता हूं। मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड की मीटिंग पिछले साल 28 अप्रैल को 6 साल बाद हुई थी और अब 4 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्ष में एक साल बाद मीटिंग होगी। मैं कहना चाहता हूं कि मेवात को पिछड़ा क्षेत्र मानते हुए मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड का गठन किया गया था ताकि महकमों की जो अपनी स्कीम्ज हैं उनसे अलग फंड मुहैया मेवात को कराया जा सके। यह इसकी जान और आत्मा थी। पिछले साल 29 करोड़ रुपये मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड के तहत दिए गए जिसमें से 14-15 करोड़ रुपये तो इस्टैब्लिश्मैंट का खर्चा था जो हर साल फिक्स होता है। विकास के लिए मात्र 14 करोड़ रुपये ही थे और उस 14 करोड़ रुपये में बहुत सी चीजें ऐसी थी जो अन्य विभागों की स्कीम्ज चल रही थी उसमें शामिल थे। बजट स्पीच में भी मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड के लिए फंड की कहीं कोई चर्चा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 4 अप्रैल को इसकी मीटिंग है। 100 करोड़ रुपये का बजट मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड का रखा जाए ताकि वहां पर लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सकें। यदि मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो वहां पर थोड़ी ज्यादा तनख्वाह मिलने पर भी डाक्टर रूकते नहीं हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि मेवात के लिए डाक्टर्ज की तनख्वाह डेढ़ी या डबल की जाये ताकि वहां डाक्टर रूक सकें। इसके अतिरिक्त वहां जो स्कूल चल रहे हैं उनको भी शिक्षा विभाग को दिया जाये। यह निर्णय भी हुआ था। मेरी अंत में प्रार्थना है कि मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा जाए। धन्यवाद।

प्रो. रविन्द्र बलियाला(रतिया) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं डिमांड संख्या 8 पर बोलना चाहता हूं जो भवन एवं सड़कों से संबंधित है। आज प्रदेश में इतना पैसा खर्च करने के बाद भी सड़कों की हालत बहुत खराब है। इस बारे में रामचन्द कम्बोज जी ने भी जिक्र किया था। यदि इस राशि का दुर्पयोग नहीं होता तो जरूर प्रदेश को लाभ होता। इतनी भारी बरकम राशि खर्च करने के बाद भी प्रदेश में सड़कों का सुधार नहीं हुआ है। मुझे संदेह है कि इस राशि का भी पहले की तरह कहीं न कहीं दुरूपयोग न हो जाये। इसलिए इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये कि इस राशि का दुरूपयोग न हो। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका बहुत ज्यादा लाभ प्रदेश को होगा। जैसे सभी माननीय सदस्य इस मद से सम्बंधित अपने-अपने हल्के की समस्यायें माननीय मंत्री जी के सामने रखते हैं और मंत्री जी उनका निराकरण करने का आश्वासन देते हैं। मैं समझता हूं कि इतनी भारी भरकम राशि खर्च करने के बावजूद इस प्रकार की समस्यायें नहीं रहनी चाहिएं थी अगर ऐसा हुआ है तो फिर कहीं न कहीं इसमें अवश्य घपलेबाज़ी हुई है। मुझे लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़कें) से सम्बंधित अपने हल्के की दो-चार समस्याओं का पता है जिसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि इस विभाग का पूरे हरियाणा प्रदेश में ऐसा ही हाल होगा। मेरे हल्के में एक चिम्मों गांव है वहां पर एक रैस्ट हाऊस स्थित है उसकी बिल्डिंग बहुत ही पुरानी है और जर्जर हालत में है। यह भवन कभी भी गिर सकता है। सरकार द्वारा इस मद के लिए इतनी भारी भरकम राशि का प्रावधान किया गया है लेकिन हमें शंका है कि इसके बावजूद भी इस विभाग के कामों की वैसी की वैसी स्थिति रहने की सम्भावना है जैसे कि पिछले साल रही है। मंत्री जी के पास एक प्रस्ताव आया हुआ है जिसमें रतिया हल्के के लाली और बलियाला गांवों के बीच में घग्गर नदी के ऊपर एक पुल बनाने की मांग की गई है। इस सम्बंध में मेरा एक क्वैश्चन भी लगा था लेकिन समय के अभाव के कारण उसका नम्बर नहीं आ सका। इस

[प्रो0 रविन्द्र बलियाला]

पुल का बजट एस्टीमेट केवल 10 करोड़ रुपये का है और इस पुल के बन जाने से रतिया हल्के के बलियाला, नंगल, सरदारेवाला, लुठेरा, बोड़ा और खाई सहित 15 गांवों का फायदा हो जायेगा। इन सभी गांवों का डिस्ट्रिक्ट हैडक्वॉर्टर फतेहाबाद है इस पुल के बन जाने से इन गांवों के निवासियों को फतेहाबाद जाने के लिए 17 किलोमीटर का रास्ता कम तय करना पड़ेगा। इस पुल के बन जाने से पुराने पुल के ऊपर ट्रैफिक लोड कम हो जायेगा क्योंकि यह जो पुराना पुल है उसकी हालत बेहद जर्जर है और वह कभी भी गिर सकता है। उस पुल का प्रयोग लोग अपनी जान जोखिम में डालकर करते हैं। वहां पर एक हादसा भी हो गया था जिसमें पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई थी।

उपाध्यक्ष महोदया : बलियाला जी, आप भाषण मत दें बल्कि डिमाण्ड के ऊपर ही बोलें और दो मिनट में अपनी बात पूरी करें।

प्रो. रविन्द्र बलियाला : उपाध्यक्ष महोदया, अगर यह पुल बन जाता है तो इससे वहां के लोगों का बहुत फायदा होगा और यह पुल बाई-पास का भी काम करेगा। अगर ऐसा होता है तो इससे सभी को यह संदेश जायेगा कि इस मद के अंदर रखा गया पैसा सही जगह पर लगा है। अब मैं मांग संख्या 9 के बारे में बात करना चाहता हूं जो कि शिक्षा के बारे में है। इस मद में भी बजट की बहुत बड़ी डिमाण्ड की गई है। इसी तरीके से अगर यह बजट सही जगह खर्च होगा तो उससे उम्मीद है कि इससे कुछ न कुछ लाभ शिक्षा का होगा। अगर पीछे के प्रोजैक्ट्स को देखा जाये तो बहुत से ऐसे प्रोजैक्ट्स हैं जिनका शिक्षा क्षेत्र को कोई लाभ नहीं हुआ जैसे कि एजुसैट है। एजुसैट के नाम पर शिक्षा विभाग में भारी भरकम खर्च किया गया लेकिन आज वे प्रोजैक्ट्स पूरी तरह से बंद पड़े हैं। ऐसे ही प्रदेश के बहुत से स्कूलों और कालेजों की बिल्डिंग्स जर्जर अवस्था में है। मेरे रतिया हल्के में ब्राह्मणवाला और बादलगढ़ के स्कूलों को अपग्रेड किया गया था लेकिन इन स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई है। इन दोनों स्कूलों को अभी तक एस.एन.ई. नम्बर भी नहीं दिया गया है। लाम्बा गांव के स्कूल की अपग्रेडेशन का मामला भी निदेशालय स्तर पर पिछले पांच सालों से लम्बित है। इतनी भारी भरकम राशि का प्रॉविजन रखा जाता है लेकिन वास्तव में ग्राऊंड लैवल पर कोई विशेष कार्य नहीं होते यह अपने आप में चिंता का विषय है। अब मैं डिमाण्ड नम्बर 10 के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि तकनीकी शिक्षा के बारे में है। यहां पर यह चर्चा भी बहुत बार हुई कि प्रदेश के अधिकतर पॉलिटैक्निक कालेजों में प्राध्यापकों की ज्यादातर सीटें खाली पड़ी हैं। इसका सीधा-सीधा मतलब तो यही है कि हमारी कार्यप्रणाली में कहीं न कहीं गुणवत्ता की कमी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय इसके ऊपर जरूर ध्यान देंगे। प्रदेश के जो पॉलिटैक्निक कालेज बंद पड़े हैं उनको पुन: चालू किया जाये और जिन पॉलिटैक्निक कालेजों में प्राध्यापकों के पद खाली पड़े हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाये। सरकार की कोशिश यही होनी चाहिए कि जो अध्यापक और प्राध्यापक हैं वे क्वॉलिटी एजुकेशन दें और यह तभी सम्भव हो पायेगा यदि हम उनको समय पर सैलरी देंगे और जो भी उनकी जायज़ डिमाण्ड्ज़ होंगी उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदया : बलियाला जी, आपको बोलते हुए बहुत ज्यादा समय हो गया है इसलिए अब आप अपनी बात जल्दी समाप्त करें।

प्रो. रविन्द्र बलियाला : उपाध्यक्ष महोदया जी, यह विषय मैंने पहले भी सदन में उठाया था कि बहुत से कालेजिज में ऐसे बहुत से प्राध्यापक हैं जिनके स्केल लम्बे समय से रूके हुए हैं। वर्ष 1993 में कुछ कालेजिज में कुछ प्राध्यापक एडहॉक बेस पर लगे थे जिनको वर्ष 1996 में दो साल की पॉलिसी बनाकर रेगूलर कर दिया गया था लेकिन बहुत से प्राध्यापक इससे वंचित रह गये थे। फिर से जब कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में सत्तासीन थी उस समय जो प्राध्यापक इस लाभ से वंचित रह गये थे उनको रेगूलर करने के आदेश पारित किये गये थे। जिससे जो प्राध्यापक इस लाभ से वंचित रह गये थे उनको रेगूलर कर दिया गया। इनमें से भी 38 प्राध्यापक ऐसे हैं जो रेगूलर तो हो गये हैं लेकिन उनको वर्ष 1993 से सर्विस का बैनीफिट नहीं मिला है। इस प्रकार से उनकी सिनियोरिटी का मसला अभी भी लटका हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में अध्यापक या प्राध्यापक कैसे हमारे प्रदेश के बच्चों को क्वॉलिटी एजुकेशन दे पायेंगे। इसी प्रकार से एक कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी का मामला है।

उपाध्यक्ष महोदया : रविन्द्र जी, आप भाषण कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप केवल डिमाण्ड पर बोले और भाषण नहीं करें।

प्रो. रविन्द्र बलियाला : उपाध्यक्ष महोदया जी, मैं शिक्षा में गुणवत्ता की बात कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदया : रविन्द्र जी, इसके अलावा आप जो भी कहना चाहते हैं उसको लिखित रूप में दे दें उसको भी सदन की प्रोसीडिंग्स का पार्ट बना लिया जायेगा।

प्रो. रविन्द्र बलियाला : ठीक है उपाध्यक्ष महोदया जी, मैं अपनी बाकी की बातें लिखित में दे देता हूं।

(चेयर के आदेशानुसार लिखित स्पीच सदन के पटल पर रखी गई।)

Subject : Regularisation of ad-hoc Class-II Lecturers in Accordance with the policy No. 6/38/95-2GSI dated 07/03/1996 w.e.f. 31/01/1996 which has been revived on 16/06/2014 vide letter No. 617/2014-1 GSI dated 16/06/2014.

Sir,

1. That there are about 90 lecturers, who were appointed during the year 1993-94 as Lecturers on ad-hoc basis and are presently working under the Department of Higher Education Haryana. These Lecturers were appointed on ad-hocr. by advertising the posts in National level newspaper e.g. "The Tribune", "Dainik Tribune" and "Times of India" through a departmental selection committee comprising of Financial Commissioner and Principal Secretary, Director of Higher Education, Joint Director Colleges and Subject Expert after fulfilling eligibility conditions as per University Grant Commission as well as Department of Higher Education, Govt. of Haryana. In this connection it is also submitted that these lecturers are duly approved by the concerned university also. These lecturers are now working as Assistant/Associate Professors in the govt. colleges of the State on regular basis after getting selected through HPSC/DSC in continuation of their ad-hoc service. It is also submitted that my clients have joined their regular service after obtaining NOC from the Higher Education Department Haryana. It is also pertinent to mention here that their ad-hoc service have

*चेयर के आदेशानुसार लिखित स्पीच सदन के पटल पर रखी गई।

[Prof. Ravinder Balila]

been duly recognized by the department for their carrier advance schemes too.

2. That Government of Haryana issued 'guidelines through Chief Secretary, Government of Haryana vide No. 6/38/95-2GSI dated 07103/1996 through which a decision to regularize the services of all those ad-hoc Class-II employees was taken, for those employees who completed two years service on 31/01/1996.

3. That keeping in view the guidelines issued vide Chief Secretary letter dated 07/03/1996, cases of all ad-hoc lecturers along-with their service book were invited by the Department of Higher Education, Haryana vide letter No. 4/24-96- C-I (1) dated 13-03-1996. It is also pertinent to mention here that all such cases were submitted to the department of higher education by hand by all the colleges before 20/03/1996.

4. That on 8-12-1997, Chief Secretary, vide letter no. 43/15/97-1GSI withdrawn the guideline issued vide No. 6/38/95-2GSI dated 07/03/1996 and consequently service books of ad-hoc Class-II lecturers were returned to their colleges stating the reason thereof.

5. That during 1997, 1999, 2003, 2004 and 2006 vacancies of Lecturer Class-II were advertised through Haryana Public Service Commission/ Departmental Selection Committee. My clients have applied for these posts after obtaining NOC from the Department of Higher Education except in the year 2006 where departmental committee was constituted to make appointments on regular basis, hence there was no need to apply through proper channel. On the basis of academic record and performance in interview, my clients were selected on regular basis while working on ad-hoc basis and joined the services on regular basis accordingly.

6. That some of the counterparts of my clients (i.e 38 lecturers), however, competed the selection process but were not selected by the HPSC/ DSC, but they were continue to serve on ad-hoc basis untill 24-01-2012.

7. That on 29-07-2011, Chief Secretary, Government of Haryana issue guidelines to regularize the services of ad-hoc class-II employees, who completed the 10 years service on 10-04-2006 vide No. 6/50/2007-1 GSI dated 29-07-2011 with terms and conditions that they possessed the minimum prescribed qualification, their work and conduct was good and those who were selected as per procedure.

8. That Department of Higher Education, Haryana regularized the services of ad-hoc lecturers who were ad-hoc on 29/07/2011 order No. 4/100-93 C-I (1) dated 25-01-2012 in terms of policy issued vide No. 6/50/2007-1 GSI dated 29-07-2011.

9. That on 16-06-2014, The Government of Haryana took a policy decision and the Chief Secretary issued guidelines vide No. 6/7/2014-1GSI dated 16/06/2014 to revive the policy dated 07/03/1996 with the following remarks

"The State Government has reconsidered the matter and has decided to revive the above mentioned policy dated 07/03/1996 to the extent that only those Group B employees working on ad-hoc basis whose services could not be regularized vide State Government policy dated 07/03/1996 due to withdrawal by the State Government vide letter dated 08/12/1997 shall be regularized with effect from the date they were eligible as per the policy dated' 07/03/1996. Other terms and conditions of regularization would remain the same. The above decisions regarding regularisation would be applicable to the employees who are presently working with the Department."

10. That the department of higher education Haryana has arbitrarily considered the cases of only those lecturers who were regularized on 25/01/2012 and an order No. 4/100-93 C-I (1) dated 02/07/2014 was issued by the department of Higher Education Haryana regularizing the services of 38 lecturers who were ad-hoc on 31/01/1996 but were regular on 16/06/2014.

11. That on dated 09-03-2015 vide letter No. 4/100-1993 C 1 (2) dated 09/03/2015 department of higher education Haryana invited the cases of all those lecturers who were ad-hoc on 31/01/1996 but were regularized through HPSC/DSC while serving on ad-hoc basis and consequently my clients submitted their cases to the Department of Higher Education Haryana along-with their service books.

12. That in compliance of the policy dated 07/03/1996 the Department of Technical Education, Haryana and Health Department, Haryana has already issued orders for regularizing the services of all those class-II employees who were ad-hoc on 31-01-1996 and got regular appointment through HPSC/DSC between 8/12/1997 to 16/06/2014. The said departments have regularized the services of such employee w.e.f. 31-01-1996 with all consequential benefits.

13. That it is a fact that the official/officer of the department of higher Education Haryana had delayed willfully the matter in 1996 as well as at present also because after 09-03-2015, they are sitting tightly on the files and no action has been taken so far even after seeking advice from the Chief Secretary Haryana on dated 20/06/2014 on file regarding the matter in question. Wherein Chief Secretary, Govt. of Haryana has clearly stated as under "The letter dated 16-06-2014 issued by the General Administration Department is very clear. The officials concerned are to be dealt with under the policy dated 07/03/1996. The queries at (i) and (ii) are not required to be sent to the Government. A list of eligible incumbents may be prepared and put up to the Government, if approved." The Departmental officials further seek query from the office of the Chief Secretary wherein it is clearly stated by the office of the Chief Secretary that ACSHE is competent to take decision in the matter.

14. The officials of the Department of Higher Education Haryana willfully and arbitrarily prepared a list of 38 lecturers who were ad-hoc on 31-01-1996 but were regular on 16-06-2014.

[Prof. Ravinder Balila]

15. That on13/03/2015 contractual/guest faculty lecturers about 140 in number were also regularized setting aside all the rules and regulations framed in this connection.

16. That 5/10/2015 benefit of Senior/Selection grade was also released to such 20 lecturers whose services were regularized from 31/01/1996 in terms of the said policy dated 07/03/1996 vide No. 2/21-2013 CV (I), but cases of my clients have been kept pending.

17. That this is a clear cut discriminative policy of the Department of Higher Education Haryana, which is also clear violation of the well established principles of natural justice and equality before law.

श्री रामचंद कम्बोज (रानियां) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं डिमांड नं. 8 पर बोलना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसी बजट अनुदान राशि से मेरे हल्के में रानियां से कुतावड़ पुल का निर्माण करवाया जाये जिसकी प्रोपोजल भी बन चुकी है। उसमें जमीन अधिग्रहण की समस्या थी। इस बारे में मैंने एस.ई. और एक्सियन से भी बात की तो उन्होंने बताया कि अगर रिटेनिंग वाल बन जायेगी तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी और यह पुल बन जायेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी 20 जुलाई, 2015 को इस पुल की घोषणा की थी। इसी तरह से नॉर्थ घग्गर कैनाल (एन.जी.सी.) की 24 नम्बर बुर्जी पर जो पुल है वह भी गिर चुका है और किसानों को अपनी फसल मंडी तक पहुंचाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी अनुदान राशि से उस पुल का भी निर्माण करवाया जाये। इसी प्रकार से अब मैं डिमांड नं. 13 के तहत कहना चाहूंगा कि सी.एच.सी. की बिल्डिंग जो जर्जर हालत में है उसका भी निर्माण करवाया जाये। अब मैं डिमांड नं. 9 पर शिक्षा के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूँ। रानियाँ में कॉलेज की घोषणा हो चुकी है तथा उसका प्रोपोजल तैयार हो चुका है। इस बारे में मेरी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से बात भी हुई थी कि वहाँ पर इसी सत्र से लड़कियों की क्लासिज शुरू करवाई जाएं क्योंकि वहाँ पर 300-350 लड़कियाँ हर साल 10+2 के बाद कॉलेज न होने के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं। वे एडमिशन नहीं ले पाती और घर में बैठ जाती हैं तथा शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदया, इसके बाद मैं डिमांड नं.24 सिंचाई के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूँ। किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की है। मेरे हल्के में सिंचाई का एक मुख्य स्रोत घग्गर नदी है। वर्ष 2010 में हमारे एरिया में घग्गर नदी के कारण बाढ़ आई थी और उसका मुख्य कारण यह था कि घग्गर नदी की खुदाई लगभग 20 साल पहले हुई थी। ओटू झील से लेकर सूरेवाला तक उसकी खुदाई हुई ही नहीं है और वहाँ पर वह नदी कुछ ही करम की रह जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि घग्गर नदी की खुदाई जल्दी से जल्दी करवाई जाये। इसी प्रकार से घग्गर नदी पर चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी के मुख्यमंत्रीत्वकाल में ओटू-वीयर झील बनाने के लिए प्रोपोजल तैयार किया गया था जिस पर पिछले 10 साल में थोड़ा बहुत काम हुआ है इसलिए जननायक चौधरी देवी लाल के नाम पर ओटू वीयर का जल्दी से जल्दी निर्माण करवाया जाये। उपाध्यक्ष महोदया, ओटू-वीयर झील के नाम से जो मिट्टी का खनन हुआ उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है इसलिए मैं यह भी अपील करूंगा कि उस घोटाले की जांच भी करवाई जाए। मेरी दूसरी मांग है कि जो

मेरे क्षेत्र रानियां में सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट है जिसकी मुख्यमंत्री जी ने 575 लाख रुपये की घोषणा भी की हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उस सीवरेज ट्रिटमैंट प्लांट का निर्माण कार्य भी शुरू करवाया जाए क्योंकि उसके न बनने से लोगों को बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय मेरे क्षेत्र रानिया शहर में पीने के पानी की भी बहुत भारी समस्या है। वहां पीने के पानी ट्यूबवैलों के माध्यम से दिया जा रही है। अगर वहां पीने के पानी के लिए नहर का पानी उपलब्ध हो जाए तो कैनाल बेस्ड वाटर मिले तो मेरा यह मानना है कि उससे 80 प्रतिशत बीमारियों पर काबू में पाया जा सकता है। मेरी दूसरी जो बात है वह यह है कि मेरा एरिया कैंसर हैपेटाईटस-बी और हैपेटाईटस-सी की बीमारी से बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त है। सिरसा और फतेहाबाद दो जिलों में लोग कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हैं। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि जैसे तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि जो नशे हैं उन पर भी रोक लगाई जाए और इसके अलावा एक जो सफेद चिट्टे के नाम से एक नशा आया है जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। मैं अनुरोध करूंगा कि उसके लिए भी कोई कानून व्यवस्था बनाकर उसको भी कंट्रोल किया जाए ताकि युवा पीढ़ी उस नशे की तरफ न बढ़ सके।

उपाध्यक्ष महोदया : आप अपनी बात को आधा मिनट में खत्म कीजिए।

श्री रामचन्द कम्बोज : उपाध्यक्ष महोदया, दूसरा मेरे विधान सभा क्षेत्र को राजस्थान से जोड़ने के लिए सिरसा से वाया ऐलनाबाद होकर जाना पड़ता है, जिससे बणी, बचेयर नथोर गांव के जो लोग हैं उनको घूम कर जाना पड़ता है और अगर जीवन नगर, करीवाला, बणी, सूरेवाला और हनुमानगढ़ होकर जाने वाला रोड़ सही ढ़ग से बना दिया जाए तो ---

उपाध्यक्ष महोदया : आप यह कौन सी डिमांड पर बोल रहे हैं ?

श्री रामचन्द कम्बोज : उपाध्यक्ष महोदया, मैं डिमांड नं. 8 पर बोल रहा हूं जो मेरी सबसे पहली डिमांड थी। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि उस रोड़ को भी कम्प्लीट करवाया जाए क्योंकि उस पर जो ये 25-30 गांव है जिनकी राजस्थान के साथ रिश्तेदारियां भी हैं और फसल का लेन-देन भी होता है अगर वह रोड़ बना दी जाए तो उन 25-30 गांवों को अपनी फसलों को बेचने के लिए बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ-साथ जो आवारा पशुओं के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने इसी सदन में गौसंरक्षण और गौसंवर्धन बिल पास किया है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि गऊशालाओं के लिए सरकार की तरफ से कभी कोई विशेष अनुदान राशि नहीं आई। मेरा निवेदन है कि इसके लिए बजट में ही अलग से कोई प्रावधान किया जाये क्योंकि गऊशालाएं किसानों के जरिये ही चलती हैं लेकिन सरकार की तरफ से उनके लिए अभी तक कोई अनुदान राशि नहीं दी गई। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर गऊशालाओं के लिए सरकार की तरफ से कोई विशेष अनुदान राशि दी जाए तो बहुत-बहुत धन्यवाद होगा।

उपाध्यक्ष महोदया : आप केवल अपनी डिमांड नं. पर ही बोलें। यह स्पीच का समय नहीं है। कम्बोज जी, प्लीज आप बैठ जाईये।

श्री केहर सिंह(हथीन) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपकी मार्फत सदन में आपनी डिमांड नं. 24 और 38 पर बोलना चाहता हूं। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने पिछले बजट सत्र में हमें

आश्वासन दिया था कि आगरा कैनाल के ऊपर जो 16 करोड़ रुपये का आबियाना है उसे सरकार वहन करेगी लेकिन आज तक भी इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि हमारा यह दुर्भाग्य है कि हम हरियाणा प्रदेश में जरूर हैं लेकिन हमारी सिंचाई की जो व्यवस्था है वह उत्तर प्रदेश के ऊपर टिकी हुई है और वर्षों से हमारी एक मांग चली आ रही है कि हमारी इस नहर का आबियाना दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदया, यद्यपि पिछले सत्र में मंत्री जी ने आबियाने को सरकार द्वारा वहन करने का वायदा किया था लेकिन बजट में इसका विवरण कहीं भी नहीं किया गया है। यही कारण है कि आगरा कैनाल से निकलने वाली हथीन, होडल, हसनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कम पानी दिया जा रहा है। इसी वजह से बिछौर माईनर, नीमका माईनर, पुन्हाना माईनर, बोराका माईनर, गेलपुर माईनर, कोट माईनर, खिल्लूका माईनर में टेल तक पानी नहीं पहुंचता है। जमीनी पानी खारा है इसी वजह से अन्धोप, खाईका, बिछौर, नांगलसभा, आली ब्राम्हण, आलीमेव, कौन्डल पावसर, कूपनगर, नाटौली, नांगलजाट, बहीन, कोट, पहाड़ी, हथीन, रिन्डका, जोधपुर, रजपुरा, दुर्गापुर, टीकरी ब्राम्हण, अहरवां, भंगूरी, कलसोड़ा, ममोलका, गेलपुर इत्यादि गांवों में नहरी पानी नहीं आने से अब की बार हजारों एकड़ जमीन पर बिजाई नहीं हो पाई है। उपाध्यक्ष महोदया, गुड़गांव कैनाल से निकलने वाली उटावड़ डिस्ट्रीब्यूटरी के भी टेल तक पानी नहीं पहुंचता है। जिसके कारण उटावड़, रूपडाका, चिल्ली, मालपुरी, गोहपुर, बूराको, पचानका, हथीन, विनोदागढ़ी, घरौट, बिचपुरी, राखौता, बढ़ा महेशपुर, स्वामिकामाईन के गांव स्वामिका, जनाचौली गांवों के किसानों को पानी नहीं मिलता है इसी वजह से किसान भूखमरी के कगार पर हैं। इन गांवों तक पानी तभी पहुँच सकता है जब वर्षों से चली आ रही हथीन माईनर की मांग को पूरा किया जाए। हथीन जनसभा में बीते वर्ष मुख्यमंत्री जी इस माईनर की घोषणा करके आए थे। उटावड़ डिस्ट्रीब्यूटरी के टेल तक पानी तभी पहुंच सकता है जब गुड़गांव कैनाल से किरिंज के पास से डिस्ट्रीब्यूटरी में कम से कम तीन पम्प सैटों से पानी डाला जाये। गौरतलब है कि यहां पर पम्प सैटों की संख्या तो चार है लेकिन असलियत में एक या दो ही पम्प सैट्स चलाये जाते हैं जिसकी वजह से पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता है। इसके अतिरिक्त आए दिन यह पम्प सैट खराब हो जाते हैं जिसकी वजह से भी पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है इसलिए मेरा निवेदन है कि खराब पम्प सैटों को बदला जाये और कम से कम तीन पम्प सैटों को चलाकर डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी डाला जाये केवल तभी पानी टेल तक पहुंच सकेगा। गुड़गांव कैनाल से निकलने वाली धतीर डिस्ट्रीब्यूटरी के हैड पर भी चार पम्प सैट्स हैं जबकि उनमें से केवल एक पम्प चलाया जाता है जिसकी वजह से गांव कलवाक, पारौली, चांदपुर, देहलाका, भूरजा सिकंदरपुर, धतीर गांवों के किसान अपने खेतों की सिंचाई ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। मेरा निवेदन है कि यहां पर भी कम से कम तीन पम्प सैटों के माध्यम से पानी डालने का कार्य किया जाये तथा खराब पम्प सैटों को बदला जाये ताकि यहां आखिरी छोर में पड़ने वाले किसानों के खेतों में भी पानी पहुंचाया जा सके। उपाध्यक्ष महोदया, गुड़गांवा कैनाल से निकलने वाली दुबालू माईनर को बीच में से ड्रेन का रूप दे दिया गया है इसी वजह से गांव कानौली, मण्डकौला, नौरंगाबाद की ज्यादातर जमीन पर सेम की समस्या बनी हुई है मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस माईनर को पूर्ण रूप से ड्रेन का रूप दिया जाए। मेरे हल्के में जीता खेडली, कानौली, स्यारौली, मण्डकौला, नौरंगाबाद, रिबड, अकबरपुर, नौरोल, विद्यावली, मढनाका, दुरची, मीरपुर, मठेपुर, छांयसा, हुचपुरी, महलूका, रणसीका, जिलालपुर गांव सेम की समस्या से पीड़ित हैं और करीब 12 वर्ष से फसल पैदा नहीं कर पाए हैं। ये किसान दु:खी

परेशान हैं। इन किसानों की परेशानी को केवल एक तरीके से खत्म किया जा सकता है कि उलेंटा हसनपुर ड्रैन, मढनाका-विद्यावली ड्रेन न.8 व मढनका व मठेपुर से एक ड्रेन निकालकर हथीन तक ले जाई जाए या गुड़गांव कैनाल के पास-पास ट्यूबवैल लगाकर उस पानी को गुड़गांव कैनाल में डाला जाए। पिछले सदन में माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम जब तक सेम की समस्या को खत्म नहीं कर देते हैं तब तक उन पीड़ित किसानों को प्रतिवर्ष मुआवजा देंगे और हमसे उन गांवों की सूची ली गई जो सेम की समस्या से पीड़ित हैं। मैंने फैक्स के माध्यम से सूची दी परन्तु आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। यहां पर 8500 एकड़ जमीन सेम की समस्या से पीड़ित है। बजट में जे.एल.एन उठान सिंचाई प्रणाली की क्षमता को सुधारने के लिए 300 करोड़ व 565 जल मार्गों का सुधार, 291.64 करोड़ की लागत से 75 सिंचाई नहरों एवं माईनरों के विस्तार, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण परियोनाओं में 21 जिलों में से केवल छह जिले ही शामिल किए गए है। पलवल, मेवात व फरीदाबाद जिलों को इस योजना में न लेकर यहां के किसानों के साथ भेदभाव ही किया गया है। उपाध्यक्ष महोदया, सेम की समस्या से पीड़ित गांवों के किसानों को इस बजट से उम्मीद थी। यहां के किसान पिछले 20 वर्ष से सेम की समस्या से पीड़ित हैं और हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी सेम की समस्या हल्का हथीन के निम्नवर्णित गांवों में नामत : कानौली, स्यारौली, जीता खडेली, मण्डकौला, नौरंगाबाद, रिबड, अकबरपुर, नाटौल, विद्यावली मढनाका, दुरैची, महलूका, छांयसा, हुचपुरी, रणसीका, जलालपुर तथा अहरवां इत्यादी में हैं। उपाध्यक्ष महोदया, बिजली के लिए 16826.70 करोड़ का बजट रखा गया है उसमें जिला पलवल व हल्का हथीन में कोई भी सब-स्टेशन की योजना नहीं है। इस बजट में बहीन में 33 के.वी. सब-स्टेशन व उटावड़ में नया 33 के.वी सब-स्टेशन खुलने की उम्मीद थी परन्तु इस बजट के माध्यम से यहां के निवासियों को बिजली क्षेत्र में भी निराशा ही हाथ लगी है। इसके अतिरिक्त दूषित पानी की बदौलत हल्का हथीन व जिला पलवल कैंसर, हैपेटाईट्स बी व सी की महामारी की चपेट में है परन्तु सरकार से बार-बार अनुरोध के बावजूद भी गांव कलवाका, देहलाका, जैन्दापुर, गेलपुर, रतिपुर, अहरवां, धमाका, राखौता, जोधपुर, दुर्गापुर, भंगुरी, ममोलाका, टिकरी ब्राम्हण, मौहदम्का, हुर्डाथल, लखनाका, उटावड़, गुराकसर, पहाड़पुर, रनियालाखुर्द, कुकरचांटी, रूपनगर, नाटौली, गोहरपुर, खिल्लू, आलीमेव, आली ब्राम्हण, नांगल जाट, अन्धोप, नांगलसभा तथा बहीन इत्यादि गांव पीने के पानी की समस्या से बेहाल हैं और यदि इस संबंध में सर्वे करवाया जाए तो आप पायेंगे कि इन गांवों के लोग एक वर्ष में करीब 100 करोड़ का पानी मोल पीते हैं और पशुओं को पिलाते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, जनस्वास्थ्य के उपर जो पैसा खर्च किया जा रहा है वह भी लोगों को पानी सुलभ कराने में विफल रहा है। पूर्व में रेनीवैल योजना 506 गांवो के लिए बनाई गई थी लेकिन आज तक केवल 66 गांवों को उस रेनीवैल योजना से लाभ प्राप्त हुआ है। जिस हल्के में 30000 रुपये प्रति व्यक्ति की प्रति वर्ष आमदनी हो और उस हल्के को 100 करोड़ रुपये का पानी खरीदना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर पानी की कितनी विकट समस्या है। इसका केवल एक ही समाधान है और वह यह है कि पलवल जिले के थंथरी के पास यमुना नदी के उपर बांध बनाया जाये केवल तभी जिला पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव व मेवात में सिंचाई व पीने के पानी का समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस प्रकार से हर खेत व हर घर तक पानी पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। मेरा अपना गांव नांगलजाट शत-प्रतिशत पानी मोल लेकर पीता है। परन्तु इस बजट में सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उपाध्यक्ष महोदया डिमांड न. 24 और 38 के परिपेक्ष्य में मैं माननीय मंत्री जी के

[श्री केहर सिंह]

संज्ञान में लाना चाहूँगा कि यह बहुत गरीब हल्का है। वित्त मंत्री जी ने जो आंकड़े पेश किए हैं पलवल जिले की 65 हजार रुपये प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय दिखाई गई है और हथीन में तो मात्र 30 हजार रुपये प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय दिखाई गई है। मेरी इन डिमांड्ज को पूरा किया जाए ताकि हथीन क्षेत्र की जनता खुशहाल हो सके और आपकी सरकार का भी प्रदेश के हर खेत के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य पूरा हो सकेगा।

श्री रणबीर गंगवा (नलवा) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं डिमांड न. 24 पर अपनी बात रखूंगा। मेरे हल्के ओ.पी.जिंदल माईनर, न्यू सिरसाना माईनर तथा बालसमंद डिस्ट्रीब्यूटरी है लेकिन अफसोस है कि इनकी टेल तक पानी नहीं पहुंचता है। इसके अतिरिक्त मेरे एरिया में रिमॉडलिंग के नाम पर नहरों से निकालने वाली मोरियों को छोटा कर दिया गया है जिसकी वजह से पीने का पानी भी बहुत मुश्किल से पहुंच पाता है। आज यहां के किसानों की भी हालत बहुत खराब हो चुकी है। उपाध्यक्ष महोदया, मैंने पहले भी इस बारे सदन में आवाज उठाई थी कि हिसार में यमुना का पानी आता था जो अब बंद हो गया है इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बी.एम.सी. में जो सिवानी फीडर है उससे कोई इंतजाम करवाकर हिसार में टेल तक पानी पहुचाने की व्यवस्था की जाये। उपाध्यक्ष महोदया डिमांड न.19 के संबंध में बताना चाहूँगा कि अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उनका पूर्ण लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता है इसलिए इन योजनाओं का लाभ संबंधित को हर हाल में पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आज गांवों में जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले बैकवर्ड जाति के लोग हैं उनकी हालत भी बहुत खराब हो चुकी है और उनके पास जगह उपलब्ध नहीं हैं। जो जगह उनके पास थी, उन पर कब्जे हो गए हैं। कई गांवों में तो पंचायती जमीनें बची नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदया, जमीनों को एक्वायर करके उन्हें जमीन देने का काम करें ताकि वे अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। यह बड़ी भारी समस्या उन लोगों के सामने है। उपाध्यक्ष महोदया, मुझे इस बात की तकलीफ है कि जो बैकवर्ड क्लास की 71 जातियां हैं उनको ना कांग्रेस पार्टी ने और ना ही मौजूदा पार्टी की सरकार ने कोई भी सुविधा देने का काम किया है। उपाध्यक्ष महोदया, बैकवर्ड क्लास की 71 जातियों को 16 प्रतिशत रिजर्वेशन में तृतीय श्रेणी के क्लर्क और चपरासी लगते हैं। सदन ने जिस तरह से सर्वसम्मति से रिजर्वेशन का बिल पास किया है, रिजर्वेशन में बी.सी.-ए. कैटेगरी की स्थिति एस.सी. कैटेगरी से ज्यादा अच्छी नहीं है। मात्र एक सोशल स्टेटस है। सरकार को बिल में संशोधन करके 16 प्रतिशत आरक्षण प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में भी करना चाहिए था। उपाध्यक्ष महोदया, ये जातियां वो जातियों हैं जो केवल अपने हकों के लिए सरकार को सिर्फ ज्ञापन देने का काम करती है। ये जातियां कभी भी झगड़ा नहीं करती है और ना ही इनमें झगड़ा करने की हिम्मत है। उपाध्यक्ष महोदया, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कभी भी इन जातियों की तरफ ध्यान नहीं दिया यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इन जातियों की तरफ ध्यान नहीं देगी तो माननीय सदस्य श्री मिड्ढा वाली बात चरितार्थ हो जाएगी कि गरीब की बात नहीं सुनोगे तो गरीब रो देगा। उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे डिमाण्ड नं016 पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री ओम प्रकाश बड़वा (लोहारू) : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे डिमाण्ड नं0 24 पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। लोहारू हल्का राजस्थान के साथ

लगता है। ज्यादातर रेतीला इलाका है, बरानी इलाका है। लोहारू इलाके में बहल और लोहारू दो ब्लॉक हैं जहां पर अंडर ग्राउंड वॉटर सिस्टम से और स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई होती है। लेकिन सिवानी ब्लॉक में ना तो कोई अंडर ग्राउंड वॉटर सिस्टम है और ना ही कोई नहर है। पूरा का पूरा इलाका बरानी है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि वहां पर नहर की व्यवस्था की जाये जैसे पहले देवसर फीडर है उसको बहल तक बढ़ाया जाये। दूसरा जो सेम या बरसात के पानी की निकासी के लिए ड्रेन बनाई गई है जो ओ.टू. वियर झील तक जाती है, इससे भी एक माईनर निकल सकता है। उपाध्यक्ष महोदया, वो माईनर वॉटर रिचार्जिंग का काम कर सकता है। बहल और लोहारू में टयूबवैल का अंडर ग्राउंड वॉटर बहुत नीचे जा रहा है। उस अंडर ग्राउंड वॉटर के पानी के लैवल को बढ़ाने के लिए जो फालतू पानी है उसको लोहारू की नहरों में छोड़ा जा सकता है चाहे वो सेम का पानी हो या बरसात का पानी हो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की नई स्कीम आई है कि 5 लाख खेत तालाब बनाएं जायेंगे ताकि वॉटर रिचार्जिंग हो। उस हिसाब से एक तालाब अगर वहां पर बन जाये तो लोहारू हल्के के लिए काफी फायदे मंद साबित हो सकता है। अब मैं डिमाण्ड नं0 8 पर बोलना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, मैंने माननीय मंत्री जी से पहले भी निवेदन किया था कि नेशनल हाइवे-65 से बड़वा और सिवानी गांव के अंदर एक सड़क बनी हुई है। चुनाव आदि विशेष अवसरों पर लोग सालासर धाम में जाकर अपनी मुराद पूरी करने के लिए सवामणी लगाने की बात कबुलते हैं। लेकिन सालासर धाम की तरफ जाने वाली सड़क पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। यह मामला भी मैंने सात दिन पहले इसी सत्र में रखा था। अभी तक उस सड़क पर केवल दो ट्रक पत्थर ही डाले गए हैं। यह रास्ता चलने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से एक बार फिर से निवेदन करता हूँ कि उस रास्ते को बनाकर चलने के काबिल किया जाये। उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री पिरथी सिंह (नरवाना)(एस.सी.) : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे डिमांड नं. 24 पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए सरकार ने कल्याणकारी योजनाएं तो बहुत बनाई हैं परंतु उनको सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है जिसकी वजह से इन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिलता। मांग नम्बर 19 में इन योजनओं के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। अगर यह राशि सुचारू रूप से इन वर्गों के लिए खर्च की जाए तो निश्चित तौर पर उनके रहन-सहन के ढंग में सुधार होगा। विडम्बना यह है कि जो राशि प्रस्तावित की गई है उसका सारा लाभ इनको नहीं मिल पाता और उसमें से अधिकारियों की मिलीभगत से आधे से ज्यादा पैसा दूसरों की जेबों में चला जाता है। हरियाणा देश में अनुसूचित जाति की आबादी में पांचवे नम्बर पर आता है जिसमें से 80 प्रतिशत आबादी गांव में रहती है। अनुसूचित जाति के 55 प्रतिशत लोग साक्षर हैं जबकि दूसरी जाति के लोग ज्यादा पढ़े-लिखे हैं। साक्षरता को बढ़ाने के लिए सरकार को हर संभव प्रयास करने चाहिएं ताकि इनके बच्चे पढ़-लिखकर अच्छा जीवन-यापन कर सकें। इन वर्गों के लिए अनेक योजनाएं हैं जैसे शगुन योजना, आवास योजना, डॉ. अम्बेडकर मेधावी योजना, अनुसूचित जाति उच्च शिक्षा योजना, स्वयं रोजगार के लिए अनेक योजनाएं, प्रतिस्पर्धा शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना, अंतरजातीय योजना आदि अनेक योजनाएं हैं। अगर सही ढंग से लागू किया जाए तो इन सभी

[श्री पिरथी सिंह]

वर्गों का उत्थान हो सकता है। केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं हरियाणा प्रदेश में लागू हैं। उनके लिए हरियाणा सरकार के पास जो वित्तीय अनुदान आता है उसको अगर सही तरीके से प्रयोग में लाया जाए तो इन वर्गों का सुधार हो सकता है। सरकारी ढांचे में कुप्रबंधन एवं बजट राशि के दुरूपयोग के कारण इन वर्गों को योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इन वर्गों की शिक्षा के लिए अनेक योजनाएं हैं जिससे इनको साक्षरता में सुधार करने का मौका मिल सकता है परंतु यह सारी योजनाएं कागजों में ज्यादा है और सरकार की निष्क्रियता की वजह से उनको लागू नहीं किया जा रहा। इन वर्गों के लिए सामाजिक योजनाओं का भी प्रावधान है जिसके लिए उचित ढांचे की आवश्यकता है और इन वर्गों के उत्थान के लिए सरकारी तंत्र को चुस्त-दुरूस्त करने की आवश्यकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदया, नरवाना हल्के में विज्ञान के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा के लिए एम.एस.सी. इन कैमेस्ट्री, फिजिक्स, जूलोजी, बोटनी और मैथ जैसे विषयों की कोई व्यवस्था न होने के कारण यहां के हजारों छात्र-छात्राओं की प्रतिभा पर ग्रहण लग गया है। अत: आज की आवश्यकता के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास हेतु वैज्ञानिक शिक्षा समय की सर्वोत्तम मांग है। हमारे के.एम. सरकारी महाविद्यलाय में वर्तमान में 300 से ज्यादा बी.एस.सी. फाइनल नॉन मेडिकल और मेडिकल के विद्यार्थी अध्यनरत हैं जबकि 2015 के पास आउट छात्रों की संख्या 275 है पिछले तीन सत्रों के विद्यार्थियों की संख्या लगभग 1000 के पार है जिनमें से अधिकतर दूरदराज के गांव से आने वाली लड़कियां हैं। इनमें 50 प्रतिशत से अधिक छात्राएं बी.एस.सी. पास हैं। नरवाना क्षेत्र के आसपास कहीं भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें एम.एस.सी. कैमेस्ट्री, फिजिक्स, बोयोलॉजी इत्यादि विषय पढ़ाए जाते हों। हमारी वैज्ञानिक प्रतिभा व्यवस्था के अभाव में दम तोड़ रही है। आज की गला-काट प्रतियोगिताओं के जमाने में पात्र छात्र योग्य होते हुए भी दाखिला पाने से वंचित रह जाते हैं। सम्पन्न परिवारों के कुछेक बच्चे सी.डी.एल.यू. सिरसा, एच.ए.यू. और जी.जे.यू. हिसार, बी.एल.यू. भिवानी, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरूक्षेत्र एवं महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक में प्रवेश पा जाते हैं लेकिन अधिकतर ग्रामीण विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और बी.एस.सी. फाइनल के उपरान्त पढ़ाई छोड़ जाते हैं। अत : आपसे हार्दिक अनुरोध है कि आप नरवाना के.एम. सरकारी कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कैमेस्ट्री का सुभारम्भ वर्ष 2016 से ही कोर्सिज या एम.एस.सी. कोर्सिज को शुरू करवाने का कष्ट करें। विशेषकर एम.एस.सी. शुरू करवाने का काम करें। साथ ही इस कॉलेज में आप समाज एवं नारी सशक्तिकरण अभियान के तहत अन्य विषयों में एम.एस.सी. क्लासिज शुरू करवाने के लिए अलग से पी.जी. ब्लॉक भी बनवाने के लिए कृतसंकल्प हों। हम सभी नरवानावासी एवं ग्रामीण अंचल के निवासी आपके बहुत आभारी होंगे। अत : कृतज्ञ, प्रबुद्ध विवेकशील एवं बौद्धिक समाज के निर्माण के लिए नरवाना के.एम. सरकारी कॉलेज में उदारतापूर्वक एम.एस.सी. कैमेस्ट्री की अनुमति प्रदान करें जो यहां के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित हो। साथ ही आपसे हार्दिक अनुरोध है कि यहां पर पी.जी. ब्लॉक की आधारशिला भी अपने कर कमलों से रखने का कष्ट करके कृतार्थ करें।

श्री राजदीप सिंह फौगाट(दादरी) : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे डिमांड नं. 11 पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरी डिमांड का विषय खेल है। जब एक बच्चा खिलाड़ी बनने की सोचता है तो उसका सारा बचपन और सारी जवानी मैदान पर ही गुजरती है। इससे उसकी पढ़ाई सौ प्रतिशत बाधित होती है। अगर खिलाड़ी साधारण

परिवार से हो तो उसके खाने-पीने की सारी व्यवस्था उसका परिवार ही करता है। जब वह खिलाड़ी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचता है तो कोई भी सरकार उस पर मोहर लगा देती है कि इसे हमने तैयार किया है। अगर हम ध्यान से देखें कि वास्तव में सरकार खिलाड़ियों को किस तरह की सुविधा प्रदान कर रही है और अगर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र दादरी की बात करूं तो (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : फौगाट जी, आप अपनी डिमांड पर ही बात कीजिए।

श्री राजदीप सिंह फौगाट : उपाध्यक्ष महोदया, मैं अपनी डिमांड पर ही आ रहा हूँ। मेरे क्षेत्र ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत-से खिलाड़ी दिए हैं जो ओलम्पिक और एशियाड गेम्स में हिस्सा ले चुके हैं परंतु दादरी शहर में खेलों का एक भी स्टेडियम नहीं है। वहां पर खेलों के प्रशिक्षण के लिए कोच तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मेरे हल्के के सबसे बड़े गांव बौंद ने हॉकी के बहुत ज्यादा खिलाड़ी दिए हैं। यहां के खिलाड़ी अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम चमका रहे हैं। अगर आप इस गाँव में जाएंगे तो आपको हर घर में एक हॉकी स्टिक तो अवश्य मिल जाएगी परंतु वहां हॉकी खेलने के लिए स्टेडियम नहीं बनाया गया ताकि कोई बच्चा हॉकी खेलने की प्रैक्टिस कर सके। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि दादरी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का स्थल है वहां पर एक स्टेडियम बनाया जाए। मैं स्टेडियम के निर्माण से भी एक कदम आगे बढ़कर यह कहना चाहूंगा कि बौंद से हरियाणा में सबसे ज्यादा खिलाड़ी निकले हैं इसलिए बौंद में एस्ट्रोटर्फ बिछाने का काम किया जाए, ऐसी मेरी डिमांड है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं विषय से हटकर एक बात और कहना चाहूंगा। दादरी के वकील एक महीने से इसलिए हड़ताल पर बैठे हैं कि उनका एक साथी वकील है, जिसके भाई और पिता ने आज से लगभग एक साल पहले आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने सुसाइड नोट में उस वकील की पत्नी पर इल्जाम लगाया है लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले एक महीने से वकील हड़ताल पर बैठे हैं। सुसाइड नोट में उन्होंने नाम भी लिखा है लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिस वजह से दादरी के लोग परेशान हैं। इस समस्या का समाधान किया जाए ताकि वकील हड़ताल से उठें और आरोपी गिरफ्तार हों। वकील एक महीने से डी.एस.पी. की कोठी के आगे बैठे हुए हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

श्री वेद नारंग (बरवाला) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं डिमांड संख्या 24 पर अपनी बात कहना चाहता हूं। सिंचाई के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि नहरी पानी सिंचाई का सबसे बड़ा माध्यम है लेकिन अफसोस की बात है कि बरवाला में जितनी नहरें आती हैं, सबके रख रखाव में कमी है। उन नहरों की न तो समय पर सफाई की जाती है और न ही टेल तक पानी पहुंचाया जाता है। बरवाला के किसान पानी से वंचित हैं और टेल पर जिन किसानों के खेत आते हैं उनको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि नहरों का पूरा रख रखाव किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह वायदा किया था कि आखिरी टेल तक पानी पहुंचाया जाएगा। हम सरकार से उम्मीद रखते हैं कि इस बजट में नहरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि किसानों के खेत तक पूरा पानी जाए। उपाध्यक्ष महोदया, मैं डिमांड संख्या 38 पर अपनी बात रखना चाहता हूं। यह विषय लोक स्वास्थ्य और जलापूर्ति के बारे में है। पीने के पानी का मनुष्य के स्वस्थ जीवन में अहम रोल होता

[श्री वेद नारंग]

है लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बरवाला में जितने भी वाटर वर्क्स आते हैं उनके रख रखाव की व्यवस्था ठीक नहीं है। वहां घास उगा रहता है। उसकी सफाई नहीं होती है तथा सफाई मात्र कागजों में होती है। उपाध्यक्ष महोदया, ऐसी ही हालत बरवाला में सीवरेज व्यवस्था की भी है। पीने के पानी के जो पाइप लगे हुए हैं वे सारे टूटे पड़े हैं और हालत यह है सीवरेज का पानी पीने के पानी में मिलकर घरों में पहुंच रहा है जिससे पीलिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मेरा निवेदन है कि मेरे बरवाला हल्के की सीवरेज और पीने के पानी की व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया जाए।

श्री अनूप धानक (उकलाना)(एस.सी.) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं डिमांड नं. 11 पर अपनी बात रखना चाहता हूं। हमारे युवा आज डिप्लोमा करके रोजगार के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। वे किसी लघु उद्योग को लगाने के लिए खादी बोर्ड के पास लोन लेने के लिए जाते हैं तो खादी बोर्ड द्वारा उनकी फाइल बनाकर उनको बैंक भेज दिया जाता है। बैंक वाले उनसे चक्कर कटवाते रहते हैं लेकिन लोन सैंग्शन करके नहीं देते तथा बेरोजगारी बेरोजगारी बनकर रह जाती है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो लोन बैंकों के माध्यम से दिया जाता है वह सीधा खादी बोर्ड ही सैंग्शन करे तथा इस लोन के लिए सबसिडी वगैरह की सारी फोरमैलिटीज भी खादी बोर्ड ही करे। उपाध्यक्ष महोदया, टी.पी.टी. सोसायटी बनाकर काफी युवा आजकल प्राइवेट बसिज चला रहे हैं। सरकार द्वारा 25.2.16 को जो अधिसूचना जारी की गई है उससे 9 हजार के लगभग लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उन युवाओं ने जो 20-22 लाख रुपये में बसिज खरीदी हैं उसका कर्जा वे कैसे उतारेंगे इसलिए मेरी मांग है कि 25.2.16 की अधिसूचना को रद्द किया जाए। उपाध्यक्ष महोदया, बालक गांव में साढे 6 एकड़ जमीन गांव के लोगों ने स्टेडियम बनाने के लिए दी हुई है इसलिए मेरी डिमांड है कि इस स्टेडियम को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। उपाध्यक्ष महोदया, मैं मांग संख्या-9 के बारे में अपनी बात कहना चाहूंगा। शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि जो स्कूल सारे नार्म्ज पूरे करेंगे उनको अपग्रेड किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदया, मेरी मांग है कि हमारे बिटमना और शिवानी बोलान गांवों के स्कूल सारे नार्म्ज पूरे करते हैं इसलिए उनको अपग्रेड किया जाए। इसके अतिरिक्त मैं अपने हल्के की कुछ मांग रखना चाहता हूं कि मेरे हल्के के गांव दाहड़ के वाटर वर्क्स के टैंक में सेम का पानी आता है जिसके कारण टैंक का पानी गंदा हो जाता है और वहां के लोग यह गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। मेरी मांग है कि वहां के वाटर वर्क्स का टैंक दोबारा बनाया जाये। इसी तरह से मेरे हल्के के पावड़ा गांव की 45 एकड़ जमीन मण्डी बनाने के लिए एक्वायर की हुई है। वहां पर मण्डी बनाने के लिए एक फेज का पैसा भी आ गया था लेकिन पता नहीं किन कारणों से वह पैसा वापिस ले लिया गया। मेरी मांग है कि पावड़ा में जल्द से जल्द मण्डी बनवाई जाए। इसी तरह से मेरे हल्के के गांव गबीपुर और खरकड़ा में पीले कार्ड का सर्वे दोबारा करवाया जाये। वहां पर बहुत से पात्र लोगों के पीले कार्ड नहीं बने हैं। धन्यवाद।

श्री हरी चंद मिड्ढा : उपाध्यक्ष महोदया, मैं जींद शहर के बारे में जितना कहूं उतना ही कम है। मैं मांग करता हूं कि जींद शहर में बाई पास, सीवरेज व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, बच्चों के लिए दवाईयों की व्यवस्था आदि कार्य करवाये जायें। उपाध्यक्ष महोदया, बच्चों को तो सभी सुविधाएं मिलनी ही चाहिएं। हमारे वहां जो कच्चे रास्ते हैं उनको भी पक्का करवाया जाये।

जींद शहर और वहां के 26 गांव बड़ी बुरी हालत से गुजर रहे हैं। अगर मैं डिटेल में बोलूंगा तो बहुत समय लगेगा दूसरे सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। मेरी मांग है कि वहां की सभी समस्याओं को दूर किया जाये। धन्यवाद।

श्री बलकौर सिंह (कालांवाली)(एस.सी.) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं डिमांड संख्या 3 पर बोलना चाहता हूं। कालांवाली में सब तहसील बनी है जिसका आफिस एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग में चल रहा है। कालावाली में सब तहसील की अपनी बिल्डिंग नहीं है। पिछली सरकार ने वहां के लिए बहुत सारी घोषणाएं की थी और कालावाली को सब डिविजन बनाने की घोषणा भी की गई थी। इस सरकार ने भी वहां पर सब डिविजन बनाने के लिए जमीन एक्वायर का सर्वे भी करवाया है लेकिन उसके आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वहां कालावाली के आसपास 50-55 गांव पड़ते हैं जिनको वहां सब डिविजन बनने से बहुत लाभ होगा। मैं इलाके की सहूलियत को देखते हुए मांग करता हूं कि कालावाली में सब डिविजन बनाया जाये और उसका अलग से कम्पलैक्स भी बनाया जाये ताकि सब तहसील का ऑफिस और दूसरे ऑफिस वहां शिफ्ट हो सकें।

श्री जाकिर हुसैन (नूंह) : उपाध्यक्ष महोदया जी, मैं डिमाण्ड संख्या 9 पर बोलना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले साल सरकार ने मेवात जिले के शिक्षा के स्तर को देखते हुए एजुकेशन पॉलिसी को रिलैक्स किया था और मेवात जिले के 34 स्कूलों को अपग्रेड किया था लेकिन उनमें अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उन अपग्रेडिड स्कूलों में पढ़ाई शुरू करवाई जाये और इस साल भी कम से कम 34 या इससे भी ज्यादा स्कूलों को अपग्रेड किया जाये। जिस प्रकार से सरकार द्वारा हरियाणा प्रदेश के हरेक जिले में यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई है उसके तहत मेवात में भी जल्दी से जल्दी एक यूनिवर्सिटी खोली जाये। इस सदन में माननीय शिक्षा मंत्री और मेवात डवैल्पमैंट बोर्ड की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे यह आश्वासन दिया था कि हरियाणा रोडवेज़ की बसिज़ में बालिका शिक्षा वाहिनी योजना के तहत लड़कियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा मेवात में जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाई जाये। (विघ्न) मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी से यह भी डिमाण्ड करूंगा कि मेवात में लड़कियों के लिए रैजीडैंशियल स्कूल खोले जायें जिनमें उर्दू स्टडीज़ हों क्योंकि मेवात में ज्यादातर मुस्लिम आबादी रहती है। इसके साथ ही साथ उनमें जॉब ऑरिएंटिड कोर्सिस भी करवाये जायें। अब मैं डिमाण्ड नम्बर 13 के बारे में बात करना चाहता हूं। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां पर स्वास्थ्य का जिक्र हुआ। यह कहा गया कि हरियाणा के 20 जिलों में स्वास्थ्य का अलग-अलग पैमाना बनाया गया और वर्तमान सरकार द्वारा पिछली सरकार की इस कार्यवाही को पाप कहा गया है। यह तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन हमारे ईलाके में कांग्रेस पार्टी के शासन काल में एक पूर्व मंत्री ने लूट मचाई उसको पुण्य माना जा रहा है। कल 42 मिनट कबड्डी और कुश्ती पर यहां पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने चर्चा की लेकिन उन्होंने इस बारे में 42 सैकण्ड भी इस बारे में बात नहीं की। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि उस मेडीकल कॉलेज की निष्पक्ष तौर पर किसी विशेष जांच एजेंसी से जांच करवाई जाये। मेरी इस बात का माननीय सदस्य श्री तेज पाल तंवर साहब भी समर्थन कर रहे हैं और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष ने भी मेरी इस डिमाण्ड का समर्थन किया है। सभी सदस्य मेरी इस बात को मान रहे हैं। इस घोटाले में जो कांग्रेस राज के

[श्री जाकिर हुसैन]

अधिकारी और मंत्री संलिप्त हैं उनकी जल्दी से जल्दी जांच करवाई जाये। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी हरेक जांच का आश्वासन दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस घोटाले की जांच का एक बार फिर से सदन में आश्वासन चाहता हूं। एक बात यहां पर नगर विकास की की गई। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेवात में आज नहीं बल्कि 10 साल पहले जब माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला साहब ने मेवात को जिला बनाया था उसमें आज तक हुडा का कोई भी सैक्टर नहीं है। वहां पर हुडा ने ज़मीन एक्वॉयर की हुई है लेकिन अभी तक भी वहां पर एक भी सैक्टर नहीं काटा गया है। पूरे नूंह शहर में स्लम एरिया बड़ी तेज़ी से डवैल्प हो रहा है। वहां पर आई.एम.टी. रोज़का में इण्डस्ट्रियल एरिया डवैल्प हो रहा है। मेवात में हुडा का सैक्टर बनाये जाने की बहुत भारी डिमाण्ड है लेकिन अभी तक भी हुडा ने लोगों की इस डिमाण्ड को नहीं माना है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि वहां पर जल्दी से जल्दी हुडा का सैक्टर काटा जाये। यह मेरे इलाके की लम्बे समय से पैंडिंग बहुत बड़ी डिमाण्ड है। अब मैं डिमाण्ड नम्बर 24 के बारे में बोलना चाहता हूं। सिंचाई के क्षेत्र में हमारे मेवात में बहुत काम हुआ है। इस मामले में जो मेवात का पन्ना पिछले 10 साल से फटा हुआ था उसको दोबारा से जोड़ने का काम किया गया है। कोटला परियोजना पर भी खास तौर से ध्यान दिया गया है। कोटला परियोजना के विस्तार का सदन में भी आश्वासन दिया गया था और मेवात डवैल्पमैंट बोर्ड की मीटिंग के एजेंडा में भी यह मामला था। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि कोटला परियोजना का भी जल्दी से जल्दी विस्तार किया जाये। उपाध्यक्ष महोदया, एक हमारी मेवात फीडर कैनाल बननी है उसके अंदर हमारे एरिया के लिए 600 क्युसिक पानी अपर यमुना बोर्ड से तय है। यह नहर साल्हावास से सोहना आयेगी इससे पीने का पानी भी मिलेगा और इससे गुडगांव, मेवात, फरीदाबाद और पलवल चार जिलों का फायदा होगा। जब इस नहर का पानी सोहना की पहाड़ी से गिरेगा तो उससे 10 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी। यह बात माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है और यह उनका स्वयं का प्रपोज़ल है। इसके लिए ज़मीन भी एक्वॉयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बादली से के.एम.पी. एक्सप्रैस वे के साथ-साथ इसको बनाया जा सकता है। बहुत जल्दी इस योजना को वास्तविक रूप दिया जा सकता है। इसे सैंट्रल वॉटर कमिशन ने भी अपने अप्रूवल दे रखी है। इसलिए मेरी अपील है कि इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाये। माननीय मंत्री जी इस सबजैक्ट पर काम कर रहे हैं मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। जो मेवात फीडर कैनाल है यह सही मायनों में मेवात की लाईफ लाईन है इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत आदेश जारी करें। यह मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं। अब मैं डिमाण्ड नम्बर 26 पर बोलना चाहता हूं जो कि खान एवं भू-विज्ञान से सम्बंधित है। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में खनन का कार्य माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बंद हुआ था। इस बारे में आप जानती हैं कि राजस्थान के अरावली क्षेत्र में बाकायदा लीगल माईनिंग हो रही है। यह माईनिंग हमारे और आपके क्षेत्र का एक बहुत बड़ा रोजगार था जिसको बंद कर दिया गया। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हुआ था लेकिन यह कानून पार्लियामैंट से बदला जा सकता था लेकिन कांग्रेस सरकार ने जहां और लूट मार की है इल-लीगल माईनिंग के माध्यम से भी बड़े स्तर पर लूट मार की है। कांग्रेस ने ही इस इल-लीगल माईनिंग को चलने दिया और इसको लीगल नहीं होने दिया। इसका कानून पास हो सकता था। आज भारतीय जनता पार्टी की राज्य और केन्द्र दोनों जगह सरकार है। उपाध्यक्ष

महोदया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूँगा कि जिस प्रकार एस.वाई.एल. नहर पर सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार को भेजा है उसी प्रकार प्रदेश में माइनिंग को लीगल करने बारे भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार को भेजा जाये ताकि प्रदेश के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके तथा प्रदेश की आर्थिक दशा सुधर सके। अब मैं डिमांड नं.36 गृह पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, मैंने जब यह देखा कि कांग्रेस सरकार के समय का जो भी घोटाला मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरन्त उसकी जांच के आदेश दे दिये तो मैंने भी हिम्मत करके मेवात के एक घोटाले के बारे में लिख कर दिया। वह घोटाला भी writing on the wall नहीं writing in the sky था जो कि दिन में दिखाई दे रहा था कि हाँ घोटाला हुआ है। पूर्व कांग्रेस सरकार के मंत्री ने चोरबाजारी की। उसकी जाँच का आदेश नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि गृह विभाग में मेवात के लिए एक सेल बनाई जाये जो मेवात के हर विभाग की जांच करे और कांग्रेस के संरक्षण में जो अधिकारी गलत काम कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाये। मेडिकल कॉलेज मेवात का डायरेक्टर जो कांग्रेस राज में भी लगा हुआ था और वह आज भी लगा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जिस कांग्रेस ने 20 जिलों में पाप किये थे वे 21वें जिले मेवात में पुण्य कैसे हो गये ? मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर के खिलाफ एक मामूली सी विभागीय जांच बिठाई है जबकि उसके निर्माण में घोटाला है जिसके लिए पी.डब्ल्यू.डी. विभाग की टैक्नीकल कमेटी होनी चाहिए थी या विजिलैंस की कमेटी होनी चाहिए थी। मैं इस महान सदन का धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पर आवाज उठाये जाने के बाद वहाँ पर साफ-सफाई हुई है। लेकिन इस साफ-सफाई से उनके बुरे कार्यों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता इसलिए मेडिकल कॉलेज मेवात की विजिलैंस जांच करवाई जाये। वहाँ अधिकारी 15-15 साल से बैठे हुये हैं। उपाध्यक्ष महोदया, अब मैं डिमांड नं. 38 लोक स्वास्थ्य एवं जल पूर्ति के बारे में बोलना चाहता हूँ। Subject Committee on Public Health, Irrigation, Power and Public Works (B&R) ने 25 मार्च को अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी कि मेवली को रेनीवेल से जोड़ा जायेगा लेकिन वह आज तक नहीं जोड़ा गया। इसी प्रकार से बादली से मैडिकल कॉलेज नूंह तक सिर्फ 22 करोड़ की लागत से अलग से लाईन आ जायेगी और मैडिकल कॉलेज नूंह में पानी की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यह रिपोर्ट मैं सदन के पटल पर रखता हूँ। अब मैं डिमांड नं. 34 परिवहन के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। ट्रांस्पोर्ट के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लगभग 25 रूट बंद हो चुके हैं ये रूट चलाए जायें। वहाँ स्टाफ की बहुत कमी है। इसमें भी करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है जिसकी इन्कवायरी करवाई जाये।

बैठक का समय बढ़ाना

उपाध्यक्ष महोदया : यदि हाउस की सहमति हो तो बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : हाँ जी, हाँ जी।

उपाध्यक्ष महोदया : ठीक है, बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

15.00 बजे **श्री जाकिर हुसैन** : उपाध्यक्ष महोदया, अब मैं डिमांड नं. 32 ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास पर बोलना चाहता हूँ। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें पिछले 10 साल से बहुत बड़ी लूट मची हुई है। उपाध्यक्ष महोदया, मैंने नवम्बर-2015 के सैशन में भी प्रश्न नं. 959 उठाया था कि इसका रिकॉर्ड देखा जाए क्योंकि उसका कहीं कोई ऐस्टीमेट नहीं जिसका मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था लेकिन उसका आज तक भी कोई जवाब नहीं आया है। उस समय के जो अधिकारी हैं वह 15-15 साल से वहीं नूंह में लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वहां पर एक जे.ई. है जिसके खिलाफ श्री कृष्ण कुमार बेदी जी उस समय हमारे ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने नगीना थाने में एफ.आई.आर दर्ज करवाई थी जिसका नं. 240 है। विभाग की सारी रिपोर्ट भी उसके खिलाफ हैं जिसमें करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है फिर भी उस समय के अधिकारियों ने उस जे.ई. के खिलाफ कार्रवाई न करके उसको फरीदाबाद में प्राईम पोस्टिंग पर लगा दिया। मुझे यह नहीं पता कि कांग्रेस सरकार के समय के इन भ्रष्ट अधिकारियों को क्यों संरक्षण दिया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदया यह एफ.आई.आर. है और बेदी साहब इसके गवाह हैं। यदि आपकी सहमति हो तो मैं ये सारे कागज सदन के पटल पर रख देता हूं। इसके साथ ही हमारे मेवात की कुछ जरूरी मांगें हैं वह भी मैं लिखित में सदन के पटल पर रख देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप इनको दे दें यह भी प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बन जाएंगे।

***श्री जाकिर हुसैन** : ठीक है, उपाध्यक्ष महोदया।

1. The budget of MDB be increased the minimum 100 crores for developmental works.
2. Mewat feeder canal be constructed.
3. To provide very special pay to the specialist doctors, MBBS Doctors and para medical staff working at the Medical College, Nalhar & Hospitals of Mewat.
4. Setting up of the University of Mewat.
5. Passenger Railway line from Gurgaon to Alwar via Nuh.
6. To develop residential HUDA sectors at Nuh.
7. Setting up of 10+2 Girls residential schools having Urdu & Arabic classes and other job oriented courses in all six blocks of Mewat area.
8. To start D.Ed & B.Ed courses in Urdu and Islamic studies in the existing institutions in Mewat area.
9. Setting up of the regional centre of the Karnal Horticulture University in the Mewat.
10. Setting up of the marketing centre for the vegetables and flowers at Tauru.
11. Extension of kotla lake/Irrigation Project
12. Implementation of "Balika Siksha Vahini" a fee and special travelling Project for girls.

*चेयर के आदेशानुसार लिखित स्पीच को कार्यवाही में शामिल किया गया।

HARYANA POLICE SERVICES

(हरियाणा पुलिस सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr. P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. District (जिला): MEWAT P.S. (थाना) NAGINA Year (वर्ष): 2015
   FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0240 Date (दिनांक): 17/12/2015
2. S.No. Acts (अधिनियम) Sections (धाराएँ)
   (क्रं. सं.)
   1 IPC 1860 120B
   2 IPC 1860 406
   3 IPC 1860 409
   4 IPC 1860 420
3. Occurrence of offence (अपराध की घटना)

1 Day (दिन)	Date To (दिनांक से)	Date To (दिनांक तक)
Time Period (समय अवधि):	Time From (समय से)	Time To (समय तक)
(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई	Date (दिनांक) : 17/12/2015	Time To (समय) 17.00
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)	Entry No. (प्रतिष्टि से) 019	Time (समय) 18.09

4. Type of Information (सूचना का प्रकार) : Written
5. Place of Occurrence
   (घटनास्थल) :
   1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा) : Beat No. (बीट से)
      NORTH. 02 Km(s)
      (b) Address (पता): BHADAS.

Office Name (कार्यालय का नाम): NAGINA Login IP (लॉग इन 3 ईपी) 10.88 233.141

Office Name (आधिकारिक नाम): ASHOK KUMAR 17/12/2015 21:06 04

User Name (यूजर नेम): 60414

[श्री जाकिर हुसैन]

HARYANA POLICE SERVICES

(हरियाणा पुलिस सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr. P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन)

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Retative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	UMAR MOHD SARPANCH		VILL BHADAS PS NAGINA
2	SADDIK AHMADJE		
3	PALTURAM GRAM SACHIV		

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता/(सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण) :

9. Paticulars of properties of interest (संबन्धित सम्पति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub type (उप प्रकार)	Value(In Rs./-) (मूल्य रुपये में)

10. Total value of property stolen (In Rs/-)(चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु. में)):

11. Inquest Report/U.D. case No. if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट/यू.टी.प्रकरण सं. यदि कोई हो) :

No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य)

Office Name (कार्यालय का नाम): NAGINA Login IP (लॉग इन 3 ईपी) 10.88 233.141

Office Name (आधिकारिक नाम): ASHOK KUMAR 17/12/2015 21:06 04
User Name (यूजर नेम): 60414

निम्नलिखित रुटों पर पहले बसें चला करती थी जो अब रुट बंद कर दिये गये हैं :—

1. नूंह से नगीना वाया कोटला।
2. नूंह से हथीन वाया आलदूका।
3. नूंह से सोहना वाया टपकन, बसई।
4. नूंह से अलावलपुर वाया मलाई।
5. नूंह से देवला - नंगली।
6. नूंह से भरतपुर वाया कांमा (राजस्थान)।
7. नूंह से सीकरी (राजस्थान)
8. नूंह से गंजखेड़ली (राजस्थान)।
9. नूंह से नंदबई (राजस्थान)
10. नूंह से कांमा (राजस्थान) वाया पुन्हाना।
11. नूंह से मथुरा (उत्तर प्रदेश)
12. नूंह से तिजारा (राजस्थान) वाया फिरोजपुर झिरका।
13. नूंह से नगर (राजस्थान)।
14. नूंह से हांसी।
15. तिगांव से पिनगवां।
16. फि. पु. झिरका से बीवां।
17. फि. पु. झिरका से कोलगांव।
18. फि. पु. झिरका से पिनगवां वाया साकरस।
19. फि. पु. झिरका से पुनहाना वाया तिघरा।
20. फि. पु. झिरका से चण्डीगढ़ (रात्रि सेवा)
21. फि. पु. झिरका से अलीगढ़ (U.P.)

नये रुट शुरु होने चाहिए :—

1. नूंह से आगरा (उत्तर प्रदेश) वाया पुन्हाना।
2. नूंह से बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) वाया पलवल।
3. नूंह से बालाजी वाया अलवर (राजस्थान)।
4. नूंह से जयपुर वाया अलवर (राजस्थान) अतिरिक्त बसें चलाई जाएं।
5. नूंह से हरिद्वार (उत्तर प्रदेश) ।
6. नूंह से गुड़गांव वाया रेहना, सादंई, सोहना।

नये वोल्वो सेवा शुरु की जाए :—

1. अलवर से चण्डीगढ़ वाया नूंह।

[श्री जाकिर हुसैन]

हरियाणा राज्य परिवहन डिपो, नूंह 1 जनवरी 2013 को बना था। डिपो को बने लगभग तीन वर्ष हो चुके हैं, परन्तु आज भी बसें व स्टाफ की कमी होने से इसकी हालत सब-डिपो से बदतर है। मेवात की जनता को इन सुविधाओं के अभाव में यात्रा करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। समस्याएं निम्नलिखित हैं :—

डिपो में कुल बसें	चाहिए
96	160-200

मौजूदा स्टाफः—

मौजूदा मेकेनिकल स्टाफ	चाहिए
15-16	70-80
मौजूदा ट्रैफिक मैनेजर	चाहिए
शुन्य	1-2

1. स्टेशन सुपरवाइजर कोई नहीं है।
2. मुख्य निरीक्षक कोई नहीं है।
3. निरीक्षक कोई नहीं है।
4. उपनिरीक्षक मौजूदा 6-7 हैं लेकिन चाहिए 40-50।
5. मुख्य लिपिक
6. सुपरिन्टेंडेन्ट कोई नहीं है।
7. लेखा अधिकारी कोई नहीं है।
8. ए.डी.ए. कोई नहीं है।
9. एस.पी.ओ. कोई नहीं है।
10. कार्य प्रबंधक कोई नहीं है।
11. एस.एस.आई. कोई नहीं है।

हरियाणा राज्य परिवहन डिपो, नूंह 1 जनवरी 2013 को अस्तित्व में आया जिसके लिए सरकार ने करोडों रुपया दिया। वर्कशॉप की अर्थफिलिंग बाउन्ड्रीवाल, जी.एम. ऑफिस व जिर्णोद्धार के अनेको कार्य शामिल थे। परन्तु महाप्रबंधक व बिल्डिंग क्लर्क नरेश कुमार व ओ.आर.सी. ओमप्रकाश ने मिलकर कोई कार्य न कराकर सारा पैसा कागजों के बल पर डकार गये। जो मेवात की जनता के साथ भद्दा मजाक है। पूरे प्रकरण की जाँच कराई जाए कि सरकार ने हरियाणा राज्य परिवहन डिपो नूंह को कितना धन उपलब्ध कराया तथा कितना कहाँ खर्च किया गया ?

नोट : महाप्रबंधक व बिल्डिंग क्लर्क व ओ.आर.सी. की भूमिका की उच्चस्तरीय कमेटी बना कर जाँच कराई जाए।

HARYANA VIDHAN SABHA

THE SUBJECT COMMITTEE
ON
PUBLIC HEALTH, IRRIGATION,
POWER AND PUBLIC WORKS (B&R)
(2014-2015)

SECOND REPORT

(Presented to the House on 25th March, 2015

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT
CHANDIGARH
2015

[श्री जाकिर हुसैन]

From

The Engineer-in-Chief
Public Health Engineering Department
Panchkula.

To

The Superintending Engineer
Public Health Engineering Circle
Palwal

Memo No. 44534 The Project dated : 18.05.2015

Subject : **Permission for supply of dringking water from Ranney Well Scheme (SBS Malab) in village Meoli.**

Please refer to your office memo No. 1536 dated 25-02-2015 and No. 2377 dated 24-03-2015 on the subject noted above.

The necessary approval of Government is hereby conveyed for providing potable drinking water to village Meoli from village Malab, which is covered under Ranney Well Segment of Rajiv Gandhi Drinking Water Supply Scheme consequent upon the decisions taken in the meeting during the visit of Sub. Committee of Public Health, Irrigation, Power and Public Works (B&R) of Haryana Vidhan Sabha on 14.02.2015 to village Malab and Meoli.

It is therefore requested that the latest status of the above work alongwith implementation of the decision taken during the visit of Sub. Committee of Public Health, Irrigation, Power and Public Works (B&R) of Haryana Vidhan Sabha be intimated to this office without further delay.

Executive Engineer (Project)
Engineer-in-Chief, Haryana

Costing and Design Calculation of Independent Infrastructure for Laying Independent pipe line from water works Badli to Nuh Town, Nalhar Medical College Nuh and surrounding 17 Nos, Villages.

DESIGN CALCULATION

A. Population Projections (Based On Geometrical Method)

Sr. No.	Name of Town/ Village/Project	Population as per 2001 Census	Prospective Population for the year 2012	Prospective Population for the year 2027	Prospective Population for the year 2042
	NUH TOWN				
1	Nuh Town	11039	14732	21836	32387
		11039	14732	21836	32387
VILLAGE ADJOINING TO NUH TOWN					
1	Rehna	2734	3930	6436	10547
2	Tapkan	2494	3895	7157	13148
3	Biwan	625	727	895	1100
4	Sonkh	1018	1497	2533	4287
5	Nalhar	679	1320	3267	8089
6	Baroji	489	595	687	837
7	Gehbar	364	531	889	1489
8	Muradbas	1608	2128	3118	4568
9	Kherla	3161	4326	6635	10177
10	Untka	965	1397	2314	3834
11	Khori Nuh	126	179	291	472
12	Shahpur Nangli	2624	3236	4306	5733
13	Sadain	702	953	1014	2191
14	Chendeni	3026	3834	5293	7309
15	Palri	1214	1840	3247	5728
16	Palla	1278	2202	4625	9713
17	Nuh Rural	1443	2370	4662	9171
		245500	**34960**	**57369**	**98393**

[श्री जाकिर हुसैन]

Costing and Design Calculation of Independent Infrastructure for Laying Independent pipe line from water works Badli to Nuh Town, Nalhar Medical College Nuh and surrounding 17 Nos. villages.

ABSTRUCT OF COST

Sr. No.	Description	Qty.	Unit	Rate	Amount
A)	Head Works at Badli				
1	Provision for construction of 1 No. sump dia with depth 3.50 Mtr. at main water works Badli for Nuh Town complete in all respects	1	No.	500000	500000
2	Provision for construction of 1 No. Pump house of size 4x 5 mtr complete in all respects	1	No.	500000	500000
3	Provision for Providing and supply, erection & commissining of centrifugual type Horizontal 2 No. Clear water pump of complete in all respects (1 W+1 S.B) 9500 LPM 30 mtr head 105 BHP	2	No.	1000000	2000000
	Total				**3000000**
B)	**Rising main**				
1	Provision for supplying, laying, jointing, cutting and testing on Rising Main DI pipe line and specials including cost Of excavation and specials to the required depth and refilling same in all respects. (Rate alloted to M/S IHPL)				
	600 mm i/d DI K-9 pipe line	18400	mtr.	9946	183006400
	Total				**183006400**
C)	Const. of Intermediated Boosting station				
1	Provision for Const. of 1 No. U.G.T. capacity-1134172 itrs of size 15.24x24.39x3.05 m depth complete in all respects	1	No.	7939204	7939204
	capacity-1134172 Itr @ Rs. 7/- per Itr				
2	Provision for Land for the const. of UGT at Intermediate Boosting station complete in all respect	0.5	Acre	10000000	5000000
3	Provision for 1 No. Diesel genreting set 125 KVA & 2 No. transformer (1 W+1 stand bye) at Badli	1	L.S.	2500000	2500000
4	Provision for CI/DI specials sluice valve, Tee, Bend, Reducer etc complete in all respects	1	L.S.	800000	800000
5	Provision for carrige of material	1	L.S.	550000	550000
	Total			**Rs.**	**16789204**
	Grand Total			**Rs.**	**202795604**
	Add 1% contingency charges			Rs.	2027956
			Total	Rs.	**204823560**
	Add 0.75% Quality control charges			Rs.	1536177
			Total	**Rs.**	**206359737**
	Add 10% Price essclanation			Rs.	20635974
			Total	**Rs.**	**226995710**
			Say Rs.	**2270.00**	**Lacs**
				Executive Engineer	

श्री परमिन्दर सिंह ढुल(जुलाना) : उपाध्यक्ष महोदया, आज पंजाब केसरी अखबार में एक बहुत अच्छी खबर छपी है जिसमें हरियाणवी फिल्म सतरंगी को नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। इससे पहले भी हमारी हरियाणा के अन्दर फिल्म बनी हैं जैसे चन्द्रावल, चन्द्रावल-2, तेरा मेरा वादा।

उपाध्यक्ष महोदया : परमिन्दर सिंह जी, आप कौन सी डिमांड पर बोल रहे हो।

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं अपनी डिमांड नं. 12 कला संस्कृति पर बोल रहा हूं। मैं सदन के नेता के संज्ञान में भी लाना चाहता हूं कि इस प्रकार की फिल्म बहुत मुश्किल से बन पाती हैं और जिसका बजट भी थोड़ा ही होता है। इसलिए प्रदेश सरकार भी इन हरियाणवी संस्कृति की फिल्मों को बढ़ावा दें क्योंकि उनको फिल्म इण्डस्ट्रीज में ज्यादा बढ़ावा नहीं मिल पाता। मैं समझता हूं कि उससे लाख-दो लाख रुपये से ज्यादा टैक्स नहीं आएगा। पंजाब सरकार ने इसी बजट सैशन में एक कानून बनाकर पास किया है कि पंजाबी संस्कृति को बढ़ावा देने वाली जितनी भी फिल्में होंगी उनको जितने भी सिनेमा हैं उनमें हफ्ते में एक दिन जरूर चलाया जाएगा और किसी भी सैशन में एक दिन किसी भी एक फिल्म को किसी समय दिखाया जाएगा और वह टैक्स फ्री रहेगी। इससे हमारे कलाकारों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और हमारी संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यह सतरंगी फिल्म आपके कार्यक्रम 'बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ' पर बिल्कुल फिट बैठती है। इसमें एक बिना बाप की बच्ची है किस प्रकार से वह पैदा हुई, किन संघर्षों में वह बड़ी हुई, किस-किस के सहारे वह पढ़कर आगे बढ़ी और अपने आपको कामयाब किया और संयोग से मेरे अपने जिले के संदीप शर्मा हैं उनकी इसमें डायरैक्शन है उन्होंने ही इसकी प्रोडैक्शन की है तो मेरा अनुरोध है कि आप भी इस प्रकार की फिल्मों के लिए कोई नीति बना कर हरियाणा की संस्कृति को आगे बढ़ाएं। उनके लिए जिस प्रकार से पंजाब सरकार ने योजना बनाई है, क्या आप भी ऐसी कोई योजना बनाकर हरियाणा की संस्कृति को बढ़ावा देंगे ? इसी डिमांड में मेरी दूसरी मांग कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड के बारे में है इसके बारे में मैं कई बार मुख्यमंत्री जी से मिला भी हूं। हमारा एक रामराय गांव भगवान परशुराम और भगवान राम जी से जुड़ा हुआ है। हमारे माननीय मंत्री श्री रामबिलास शर्मा जी उसको जानते हैं कि रामराय नामक एक तीर्थ है जो भगवान परशुराम से जुड़ा हुआ है जो कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड की भूमि में आता है और गांव पोकरी खेड़ी में पुष्कर राज का तीर्थ है और उसी प्रकार गांव आसन में अश्वनी कुमार का सारे भारत में एक मात्र तीर्थ है जहां की मान्यता है कि इस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य रोग मुक्त होता है। इसलिए आप इनको अधिग्रहण करें क्योंकि इनकी हालत अच्छी नहीं है तो इनके लिए भी कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड से कुछ हिस्सा दिलाया जाए। इसके अलावा सिंचाई मंत्री जी की तो मेरे ऊपर पूरी कृपा है इसमें मंत्री जी बस मेरी एक ही मांग है कि जो मैंने जुलाना में री-ऑर्गेनाईजेशन ऑफ डिविजन मांगा हुआ है उसको बना दिया जाए। अगर जुलाना में अलग से वह डिविजन बन जाएगा तो काम में गति भी आएगी और आपके पैसे का सदुपयोग भी होगा। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि एच.एस.के.एम.बी. के लिए जुलाना में पिछले दिनों जाट आरक्षण आन्दोलन के दौरान अग्निशमन के लिए एक नई गाड़ी भेजी गई थी जो एक मात्र गाड़ी थी उसी को जला दिया गया। अब वहां नई फसल आने वाली है और वहां पर कोई अग्निशमन की गाड़ी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जुलाना में कोई दूसरे अग्निशामक वाहन का इंतजाम न होने से कोई भी अनहोनी मुमकिन हो

[श्री परमिन्द्र सिंह ढुल]

सकती है। मेरी सरकार से विनती है कि इस अग्निशामक वाहन का यहां पर इंतजाम करवाया जाये। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान इस अग्निशामक वाहन के जलाये जाने की वजह से इस वाहन पर आउटसोर्सिंग पॉलिसी के आधार पर तैनात 12 नवयुवक बेरोजगार हो गये हैं। अगर मान लो जुलाना क्षेत्र में कहीं आग लग जाती है तो अग्निशामक वाहन को गोहाना, जींद या रोहतक से बुलाना पड़ेगा। इससे पहले की नई फसल की कटाई का कार्य शुरू हो अग्निशामक वाहन का यहां पर इंतजाम जरूर करवाया जाये। जुलाना क्षेत्र में कोई खेल स्टेडियम नहीं है अत : मैं मांग करता हूँ कि यहां पर कोई बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम का भी निर्माण करवाया जाये। मेरे गांव रामराय तथा गतौली में तैराकी से संबंधित खिलाड़ी बहुतायत में मिल जाते हैं। यदि पूरे हिन्दुस्तान के हिसाब से देखा जाये तो यहां के तैराकों ने तैराकी के क्षेत्र में मैडल प्राप्त कर नौकरी हासिल की है, सेना में भी भर्ती हुए हैं, देश के अलग-अलग स्थानों पर स्थित तरनतालों में कोच के रूप में सेवायें दे रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि इन गांवों में स्विमिंग पुल का निर्माण करवाया जाये। इसके अतिरिक्त गांव निडाना, सिवाहा, हथवाला, किलाजफरगढ़, माली, खरकरामजी, बुआना और बीबीपुर में भी खेल स्टेडियम बनाए जायें। इसके अतिरिक्त मैं सदन के माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि गांव भैरोखेड़ा से ढिगाणा और निडाना से बिरोली तथा ढिगाणा से पढाना तक अगर सड़क बना दी जाती है तो इसका फायदा यह होगा कि यहां साथ लगते लगभग 22 गांवों के किसानों को जींद अनाजमंडी में जाने के लिए जींद नहीं जाना पड़ेगा क्योकि एक तरह से यह रास्ता अनाजमंडी जीन्द के साथ सीधा जुड़ जायेंगा। इससे समय व धन की बचत तो होगी ही साथ ही किसानों को रेलवे फाटक क्रॉस करने की समस्या से भी मुक्ति मिल जायेगी। यह सभी रास्ते 5 करम के बनायें गये हैं इन्हें चौड़ा करना भी बहुत जरूरी है। मैंने रास्ता चौड़ा करने के लिए कई बार सदन में आवाज उठाई है लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। इसी प्रकार रामराय गांव से बीबीपुर गांव तक रास्ता नहीं जुड़ा हुआ है। अगर यह रास्ता जुड़ जाता है तो नारनौद हल्के के कई गांव जैसे राजथल, मिलकपुर, खेड़ी तथा राखीगढ़ी के किसानों को अनाजमंडी जींद में आने के लिए जींद से होकर नहीं आना पड़ेगा क्योंकि इन गांवों के बीच जो यह दो किलोमीटर का रास्ता है जोकि अभी तक नहीं बना है, इसको बना दिया जाता है तो गोबिन्दपुर के रास्ते सीधा अनाज मंडी जींद में पहुंचा जा सकता है। इसी प्रकार यदि गतौली गांव से करसौला गांव को जोड़ दिया जाता है तो किसानों को अनाज मंडी जींद में जाने के लिए मेन हाईवे पर आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि करसौला गांव के साथ ही जुलाना अनाज मंडी स्थित है। मेरी जैजवंती और बिशनपुरा नामक दो रेलवे स्टेशनों के रास्ते को गांव के साथ जोड़ने बारे भी एक डिमांड है। यदि बिशनपुरा रेलवे स्टेशन से गांव किनाना तक का जो दो किलोमीटर का रास्ता है अगर इसे पक्का बनाकर जोड़ दिया जाता है तो साथ लगते कम से कम आठ दस गांवों के रोहतक से दिल्ली आने जाने वाले डेलीकम्यूटर्ज को बहुत सहूलियत होगी। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : ढुल साहब, आपने यह डिमांड राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भी रखी थी।

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने यह डिमांडज उस समय नहीं रखी थी, मैं बस एक और मांग का जिक्र करके अपनी सीट धारण कर लूंगा। उपाध्यक्ष महोदया, यदि

जैजवंती रेलवे स्टेशन से जाने वाले रास्ते को गांव खेड़ा-बख्ता के साथ जोड़ दिया जाता है तो इससे भी निश्चित रूप से मेरे हल्के के लोगों को काफी सुविधा होगी। (विघ्न)

श्री हरि चन्द मिड्ढा : उपाध्यक्ष महोदया, यदि आपकी सहमति हो तो मैं महज आधा मिनट लेकर अपनी बात रखकर बैठ जाऊँगा। पांडु-पिंडारा को समस्त हिन्दुस्तान में पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है लेकिन यहां पर अब ऐसी स्थिति बन चुकी है कि न तो यहां पर तालाब के लिए जगह बची है और जो तालाब बचा भी है उसमें पानी ही नहीं है इसके अतिरिक्त यहां पर आने-जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले रास्ते की भी बहुत बुरी हालत है। इस अवस्था में धार्मिक कर्म-कांड से जुड़े लोगों व अन्य लोगों के सामने विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस समस्या की तरफ ध्यान देकर यहां पर आवश्यक कदम उठाये जायें। (विघ्न)

डॉ. अभय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदया, जिस पांडु-पिंडारे नामक धार्मिक स्थल का अभी मिढा साहब ने जिक्र किया है, तालाब का स्थान तो कुछ हद तक बाकी है लेकिन पानी तो बिल्कुल ही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदया : ठीक है, अब आप बैठिए क्योंकि बलवान सिंह जी भी डिमांड्ज पर बोलना चाह रहे हैं। आपकी और मिढा साहब की डिमांड को संबंधित मंत्री ने नोट कर लिया है।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया(फतेहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं मांग संख्या : 35 पर बोलना चाहता हूँ। जब माननीय पर्यटन मंत्री जी प्रश्न काल के दौरान पर्यटन पर जवाब दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम किसी स्थान की लोकेशन को देखकर उस लोकेशन को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करके पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। उस परिपेक्ष्य में मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि लोकेशन के मामले में पूरे फतेहाबाद से बढ़कर कोई दूसरी बढ़िया लोकशन हरियाणा प्रदेश में नहीं है। फतेहाबाद जिले में कुदरत की बहुत बड़ी मेहरबानी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी टोहाना रैली के दौरान घोषणा की थी कि फतेहाबाद में स्थित चिल्ली को झील का रूप दिया जायेगा। निश्चित रूप से यदि चिल्ली को झील का रूप दिया जाता है तो यहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा शहर को गंदगी से छुटकारा भी मिलेगा। फतेहाबाद से 20 किलोमीटर दूर महाराजा अग्रसेन धाम के नाम से अग्रोहा धाम स्थित है जहां पर काफी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। अगर फतेहाबाद में यह पर्यटन स्थल बनता है तो पर्यटक नाईट स्टे फतेहाबाद में करेंगे जिसकी वजह से होटल व्यवसाय बढ़ने के साथ-साथ यहां के दुकानदारों की आमदनी भी बढ़ेगी। अत : मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द फतेहाबाद को पर्यटन के मानचित्र पर आगे लाने के लिए सरकार को विशेष रूप से कदम उठाने चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, मैं मांग संख्या न. 45 जोकि लोन से संबंधित है, पर भी अपने विचार रखना चाहता हूँ। जिस किसान के पास 10-12 किल्ले जमीन होती है उस किसान के लिए तो बैंक वाले घर जाकर लोन का केस तैयार करके लोन दे देते हैं लेकिन जिस किसान के पास एक किल्ला, डेढ़ किल्ला या दो किल्ले होते हैं उस किसान को लोन के लिए बैंक द्वारा बार-बार चक्कर लगवाये जाते हैं। सरकार को ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि बैकों से छोटे किसानों को उनकी जमीन के हिसाब से 10,15 या 20 प्रतिशत लोन बिना किसी कठिनाई के प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त तहसील में रजिस्ट्री कराने की जो प्रक्रिया है वह भी बहुत जटिल है। मेरी सरकार से विनती है कि महज एक सफेद कागज पर रजिस्ट्री का प्रावधान करते हुए इस प्रक्रिया को सरल बनाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, अब विभिन्न डिमांड्ज को सदन में वोटिंग के लिए रखा जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है -

कि राज्स्व खर्च के लिए 69,72,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चो को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. के 1-विधान सभा के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

राजस्व खर्च के लिए 122,34,00,000 रुपये से अनाधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 2-राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 244,23,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 3-सामान्य प्रशासन के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 1069,65,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 4-राजस्व के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 204,84,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 5-आबकारी व कराधान के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 5713,95,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 6-वित्त के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 455,61,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 7-आयोजना एवं सांख्यिकी के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 1344,46,70,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 3609,08,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 8-भवन तथा सड़कें के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 12865,21,44,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 6,81,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 9-शिक्षा के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 421,42,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 10-तकनीकि शिक्षा के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 313,13,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 11-खेलकूद तथा युवा कल्याण के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 13,83,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 12-कला एवं संस्कृति के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 3338,68,94,400 रुपये तथा पूंजीगत खर्च 510,00,00,000 से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 13-स्वास्थ्य के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 97,19,80,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 14-नगर विकास के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 3549,11,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 15-स्थानीय शासन के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 52,54,15,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 2,00,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 16-श्रम के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 70,71,80,000 रुपये अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 17-रोजगार के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 278,37,35,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 47,00,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 18-औद्योगिक प्रशिक्षण के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 662,52,00,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 11,55,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 19-अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण के अधीन व्ययों के बारे मेंवर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 4199,94,33,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 92,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

[उपाध्यक्ष महोदया]

कि राजस्व खर्च के लिए 1096,79,50,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 110,70,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 21-महिला एवं बाल विकास के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 94,19,39,000 रुपये अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 22-भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 368,19,12,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 9843,87,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 23-खाद्य एवं प्रर्ति के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 1867,31,68,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 655,50,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 24-सिंचाई के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 706,73,43,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 5,02,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 25-उद्योग के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 13,85,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 26-खान एवं भू-विज्ञान के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 1937,04,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 27-कृषि के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 716,29,00,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 15,00,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 28-पशुपालन एवं डेरी विकास के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 47,76,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 29-मछली पालन के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 382,32,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 30-वन एवं वन्य प्राणी के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 8,60,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 31-परिस्थिति विज्ञान एवं पर्यावरण के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 3070,22,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 220,64,80,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 84,19,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 33-सहकारिता के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 2176,41,65,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 260,75,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 34-परिवहन के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 2,81,40,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 66,81,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 35-पर्यटन के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 3565,70,78,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 226,40,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 36-गृह के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 50,75,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 37-निर्वाचन के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 1890,76,50,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 12,17,60,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 38-लोक स्वास्थ्य एवं जल पूर्ति के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 133,96,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 39-सूचना एवं प्रचार के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 10741,66,05,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1933,51,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 40-उर्जा तथा विद्युत के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

[उपाध्यक्ष महोदया]

कि राजस्व खर्च के लिए 86,03,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 41-इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिक के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 495,37,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 42-न्याय प्रशासन के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 218,86,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 43-कारागार के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 39,39,72,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 5,80,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 44-मुद्रण एवं लेखन सामग्री के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 4729,38,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं. 45-राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2016-2017 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

विधान सभा समितियों की रिपोर्टस प्रस्तुत करना

(i) पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की 62 वीं रिपोर्ट

उपाध्यक्ष महोदया : अब श्री हरविन्द्र कल्याण चेयरपर्सन, लोक उपक्रमों संबंधी समिति वर्ष 2008-2009 तथा 2010-2011 (वाणिज्यिक) 2011-2012 (सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र) के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों पर वर्ष 2015-2016 के लिए लोक उपक्रमों संबंधी समिति की 62वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

चेयरपर्सन, लोक उपक्रमों संबंधी समिति (श्री हरविन्द्र कल्याण) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष 2008-2009 तथा 2010-2011 (वाणिज्यिक) 2011-2012 (सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र) के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों पर वर्ष 2015-2016 के लिए लोक उपक्रमों संबंधी समिति की 62वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ।

(ii) कमेटी ऑफ लोकल बाडीज एंड पंचायती राज इंस्टीटयूशंज की 8वीं रिपोर्ट

उपाध्यक्ष महोदया : अब डॉ0 अभय सिंह यादव चेयरपर्सन, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति निदेशक, स्थानीय लेखा-परीक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा लेखा परीक्षित अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए जिला परिषद्, सिरसा, अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013, तक की अवधि के लिए पंचायत समिति पेहवा के लिए, अप्रैल, 2005 से मार्च, 2013, तक की अवधि के लिए पुंडरी, अप्रैल, 2010 से मार्च, 2013, तक की अवधि के लिए टोहाना तथा अप्रैल, 2010 से मार्च, 2013, तक की अवधि के लिए निसिंग पर वर्ष 2015-2016 के लिए स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति की आठवीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

Chairperson, Committee on Local Bodies and Panchayati Raj Institutions (Dr. Abhe Singh Yadav) : Madam, I beg to present the Eighth Report of the Committee on Local Bodies and Panchayati Raj Institutions for the year 2015-16 on the Report of the Audit and Inspection Notes on the Accounts of Zila Parishad, Sirsa for the period from April, 2012 to March, 2013, Panchayat Samitis, Pehowa for the period from April, 2012 to March, 2013, Tohana for the period from April, 2010 to march 2013 and Nissing for the period from April, 2010 to march, 2013 audited by the Director Local Audit, Haryana.

(iii) **कमेटी ऑफ लोकल बाडीज एंड पंचायती राज इंस्टीटयूशंज की 9वीं रिपोर्ट**

उपाध्यक्ष महोदया : अब डॉ0 अभय सिंह यादव चेयरपर्सन, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति निदेशक, स्थानीय लेखा-परीक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा लेखा परीक्षित अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए नगर निगम, गुड़गांव तथा अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए करनाल के लेखों पर लेखा-परीक्षा तथा निरीक्षण नोट पर वर्ष 2015-2016 के लिए स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति की नौवीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

Chairperson, Committee on Local Bodies and Panchayati Raj Institutions (Dr. Abhe Singh Yadav) : Madam, I beg to present the Ninth Report of the Committee on Local Bodies and Panchayati Raj Institutions for the year 2015-16 on the Report of the Audit and Inspection Notes on the Accounts of Municipal Corporations, Gurgaon for the period from April, 2012 to March, 2013 and Karnal for the period from April, 2013 to March, 2014 audited by the Director, Local Audit, Haryana.

(iv) **एस्टीमेट्स कमेटी की 44वीं रिपोर्ट**

उपाध्यक्ष महोदया : अब श्री मूल चंद शर्मा चेयरपर्सन, प्राक्कलन समिति वर्ष 2015-2016 के लिए कृषि विभाग के बजट अनुमानों पर वर्ष 2015-2016 के लिए प्राक्कलन समिति की 44वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

Chairperson, Committee on Estimates (Shri Mool Chand Sharma) : Madam, I beg to present the Forty Fourth Report of the Committee on Estimates for the year 2015-2016 on the Budget Estimates for 2015-2016 Agriculture Department.

(V) **गवर्नमैंट एश्योरेंसिज कमेटी की 45वीं रिपोर्ट**

उपाध्यक्ष महोदया : अब सरदार जसविन्द्र सिंह संधू चेयरपर्सन, सरकारी आश्वासनों के बारे में समिति वर्ष 2015-2016 के लिए सरकारी आश्वासनों के बारे में समिति की 45वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

चेयरपर्सन, सरकारी आश्वासनों के बारे में समिति (सरदार जसविन्द्र सिंह संधू) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष 2015-2016 के लिए सरकारी आश्वासनों के बारे में समिति की 45वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ।

(VI) कमेटी ऑन दि वेलफेयर ऑफ शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिडयूल्ड ट्राइब्ज एण्ड बैकवर्ड क्लासिज की 39वीं रिपोर्ट

उपाध्यक्ष महोदया : अब श्री बलवन्त सिंह चेयरपर्सन, अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति वर्ष 2015-2016 के लिए अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति की 39वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

Chairperson, Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes (Shri Balwant Singh) : Madam, I beg to present the Thirty Ninth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes for the year 2015-2016.

विधान कार्य—

1. दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 2016

उपाध्यक्ष महोदया : अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 प्रस्तुत करेंगी और यह भी प्रस्ताव करेंगी कि इस पर तुरन्त विचार किया जाए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 प्रस्तुत करती हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करती हूँ -

कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है -

कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदया : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है -

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है -

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है -

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है-

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदया : अब मंत्री जी प्रस्ताव करेंगी कि बिल पास किया जाए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूँ-

कि बिल पास किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि बिल पास किया जाए।

श्री नसीम अहमद (फिरोजपुर-झिरका) : उपाध्यक्ष महोदया, पिछले पंचायत चुनाव में बी.सी. उम्मीदवारों के लिए कंडीशंज लगाई थी और अब नगर पालिका और नगर निगम चुनावों के लिए भी कंडीशंज लगाई जा रही हैं परंतु इनमें यह स्पष्ट नहीं है कि यह सीट बी.सी. (ए) के लिए है या बी.सी. (बी) के लिये है या किसी और कैटेगरी के लिए है। पंचायत चुनावों में जो सीट्स बी.सी. कैटेगरी के लिए आरक्षित थी उनमें बी.सी. की सभी कैटेगरीज और ओ.बी.सी. कैटेगरी के उम्मीदवारों ने फार्म भर दिये और वे पंचायतों के सरपंच और मैम्बर भी बन चुके हैं। अत : मेरी यही गुजारिश है कि यह कैटेगरीज स्पष्ट की जाएं।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है-

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

(2) दि हरियाणा म्युनिसिपल कारपोरेशन (अमैंडमैंट)बिल, 2016

उपाध्यक्ष महोदया : अब शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016 प्रस्तुत करेंगी तथा यह भी प्रस्ताव करेंगी कि इस पर तुरन्त विचार किया जाए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016 प्रस्तुत करती हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करती हूँ-

कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है -

कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक,पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदया : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है -

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है -

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है -

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है-

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदया : अब मंत्री जी प्रस्ताव करेंगी कि बिल पास किया जाए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूँ-

कि बिल पास किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि बिल पास किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है-

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

(3) दि कंट्रैक्ट लेबर (रैगुलेशन एण्ड एबोलिशन) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 2016

उपाध्यक्ष महोदया : अब श्रम एवं रोजगार मंत्री ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2016 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस पर तुरन्त विचार किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2016 प्रस्तुत करता हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ-

कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हरियाणा संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हरियाणा संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है -

कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हरियाणा संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदया : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है --

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है -

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है -

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है-

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदया : अब मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ-

कि बिल पास किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि बिल पास किया जाए।

श्री जय प्रकाश बरवाला (कलायत) : उपाध्यक्ष महोदया, इसमें मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अगर किसी ठेकदार को 50 से कम मजदूरों की जरूरत है तो इस बिल के पास होने के बाद ठेकेदार को लाईसैंस की आवश्यता नहीं होगी जिससे मजदूरों का शोषण होगा। आज भी अनइम्पलायड नौजवानों का और मजदूरों का ठेकेदारों द्वारा शोषण हो रहा है। इसके अलावा इस बिल में अब 100 मजदूरों की जगह 300 का जो प्रोविजन किया गया है उसके बारे में मंत्री जी अपने जवाब में बता दें।

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, यह ठेका श्रम (विनयमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 केन्द्र सरकार का अधिनियम है। हमने हरियाणा में व्यापारी और उद्योगों की सहूलियत के साथ-साथ मजदूरों के हित को भी ध्यान में रखते हुए कुछ संशोधन बिल में किए हैं। यहां से बिल पास होने के बाद हम केन्द्र सरकार को भेजेंगे और राष्ट्रपति महोदय ही इस पर मोहर लगाकर इसे पास करेंगे। अन्य कई राज्यों ने इस प्रकार के परिवर्तन किए हैं। इस समय बिल में प्रोविजन है कि जो कोई 20 या उससे अधिक लेबर आऊट सोर्सिज करके रखता है तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसके ऊपर यह कानून लागू होता है। जो छोटा मध्यम उद्योगपति है उसको साल के बीच-बीच में जब काम करने का कोई ठेका मिलता है तो उनको कुछ एक्स्ट्रा मैन पावर रखनी पड़ती है। जिसके कारण उसे हर बार रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आना पड़ता है। छोटे और मध्यम उद्योगपति के ऊपर यह समस्या ज्यादा आती है। जो बड़ा उद्योगपति है वह तो 50 से अधिक की श्रेणी में आ जायेगा। छोटे और मध्यम उद्योगपति को यह सहूलियत देने के लिए ऐसा प्रोविजन किया गया है कि 50 तक यदि किसी ने लेबर कंट्रैक्ट पर रखनी है तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्ताव हम लेकर आये हैं।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है-

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

(4) दि इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2016

उपाध्यक्ष महोदया : अब वित्त मंत्री औद्योगिक विवाद (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस पर तुरंत विचार किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं औद्योगिक विवाद (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016 प्रस्तुत करता हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ -

कि औद्योगिक विवाद (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि औद्योगिक विवाद (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है -

कि औद्योगिक विवाद (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदया : अब सदन बिल पर क्लाज-बाई-क्लाज विचार करेगा।

क्लाज - 2

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है -

कि क्लाज - 2 बिल का पार्ट बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज - 1

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है -

कि क्लाज - 1 बिल का पार्ट बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है -

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है -

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदया : अब वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ -

कि बिल पास किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि बिल पास किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है -

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(5) दि फैक्ट्रीज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2016

उपाध्यक्ष महोदया : अब वित्त मंत्री कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस पर तुरंत विचार किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016 प्रस्तुत करता हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ -

कि कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है -

कि कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदया : अब सदन बिल पर क्लाज-बाई-क्लाज विचार करेगा।

क्लाजिज - 2 से 6

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है -

कि क्लाजिज - 2 से 6 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज - 1

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है -

कि क्लाज - 1 बिल का पार्ट बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है-

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदया : अब मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ-

कि बिल पास किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि बिल पास किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है-

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बैठक का समय बढ़ाना

उपाध्यक्ष महोदया : यदि हाउस की सहमति हो तो बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : हां जी, हां जी।

उपाध्यक्ष महोदया : ठीक है, बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

(6) दि पेमैंट ऑफ वेजिज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2016

उपाध्यक्ष महोदया : अब श्रम एवं रोजगार मंत्री मजदूरी संदाय (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस पर तुरन्त विचार किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं मजदूरी संदाय (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016 प्रस्तुत करता हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ-

कि मजदूरी संदाय (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि मजदूरी संदाय (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है -

कि मजदूरी संदाय (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदया : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है -

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है --

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है --

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है-

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदया : अब मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ-

कि बिल पास किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि बिल पास किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है-

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदया : आनरेबल मैम्बर्ज, अब यह सदन दिनांक 31 मार्च, 2016, प्रात:10 :00 बजे तक स्थगित किया जाता है।

*15:36 बजे (तत्पश्चात सदन की बैठक वीरवार, 31 मार्च, 2016, प्रात: 10 :00 बजे तक स्थगित हुई।)

54380—H.V.S.—H.G.P., Chd.

© 2016

Published under the authority of the Haryana Vidhan Sabha and printed by the Controller, Printing and Stationery Department, Haryana, Chandigarh.